विचार
नवभारत टाइम्स
नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली। बुधवार, 13 नवंबर 2024

मुनासिब मांग

सुप्रीम कोर्ट मे पिछले दिनो एक याचिका दाखिल कर पीएम जन आरोग्य योजना मे पारपरिक चिकित्सा पद्धति को शामिल करने की माग की गई। यह बिल्कुल ठीक है कि ऐसा करने से एक बड़ी आबादी को सस्ती स्वास्थ्य सुविधाओ का लाभ मिल सकेगा। साथ ही, पारपरिक चिकित्सा को भी बढ़ावा मिलेगा।

दायरा बढ़ेगा | सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मागा है। हालांकि यह मामला ऐसा नही है, जिस पर सरकार को फैसला लेने मे बहुत दिक्कत हो। PM-JAY या आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। लगभग 55 करोड़ लोग इसके दायरे मे आते है। लेकिन एक बड़ी आबादी अब भी इसके लाभ से छूटी हुई है। पारपरिक चिकित्सा और भी लोगो को जोड़ सकती है।

AI image

पारपरिक चिकित्सा को लेकर याचिका

सरकार पर बोझ नहीं | भारत की पारपरिक चिकित्सा पद्धति जैसे कि आयुर्वेद और योग दूसरी पद्धतियो के मुकाबले सस्ती है। इसके लिए ज्यादा इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नही पड़ती। मौजूदा स्वास्थ्य ढाचे के जरिये ही इन्हे भी लागू किया जा सकता है। इससे न सरकार पर ज्यादा बोझ आएगा और न जनता पर, बल्कि स्वास्थ्य बीमा का विस्तार होने से देश की कुल चिकित्सा लागत मे कमी ही आएगी।

स्वस्थ रखने में मदद | देश मे लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारिया तेजी से बढ़ रही है। फोब्र्स की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत मे non-communicable diseases से हर साल लगभग 58 लाख लोगो की मौत होती है। इनसे बचाव मे पारपरिक चिकित्सा पद्धति कारगर साबित हो सकती है। केंद्र ने कुछ अरसा पहले ही PM-JAY मे 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गो को भी शामिल करने की मजूरी दी थी। पारपरिक चिकित्सा बुजुर्ग आबादी की जरूरतो को भी पूरा कर सकती है।

रोजगार के मौके | आयुर्वेद पर भरोसा और दुनिया मे इसकी माग, दोनो मे इजाफा हुआ है। बाजार के लिहाज से देखे, तो इसकी ग्रोथ रेट 15% से अधिक है। साल 2014 मे आयुष का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 2.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2020 मे बढ़कर 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। 100 से अधिक देशो मे भारत के हर्बल प्रॉडक्ट पहुच रहे है। आयुष्मान भारत के तहत इसे लाने से इसमे और तेजी आएगी। इससे इस क्षेत्र मे रोजगार के मौके बनेंगे।

सरकार का फोकस | पारपरिक चिकित्सा पद्धति को पूरी दुनिया मे ज्यादा स्वीकार्य बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। विश्व स्वास्थ्य सगठन (WHO) के साथ मिलकर यह भी देखा जा रहा है कि किस तरह से भारत का पारपरिक ज्ञान दुनिया को सेहतमद रखने मे योगदान दे सकता है। इस दिशा मे रिसर्च और इनोवेशन पर फोकस है। याचिका मे उठाई गई माग को पूरा करके सरकार अपने काम को ही आगे बढ़ाएगी।

इन दिनों

युद्ध का क्या होगा

मृत्युंजय राय

डॉनल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने के बाद यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की पहल शुरू हुई, लेकिन पश्चिम एशिया में भी इसाइल-हमास-हिजबुल्लाह के बीच एक युद्ध चल रहा है, जिसके अंजाम को लेकर कई तरह की अटकलें हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पश्चिम एशिया को लेकर अमेरिकी नीति में बदलाव आना तय है। इस पर दुनिया के जानकारों में सहमति है, लेकिन यह बदलाव क्या होगा और पश्चिम एशिया को लेकर ट्रंप की नीति क्या होगी, इसकी तस्वीर साफ नहीं है। या यूं कहें कि एक्सपर्ट्स के बीच इस पर आम राय नहीं है।

इसाइली पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू दुनिया के उन नेताओं में शामिल हैं, जिन्होंने ट्रंप को चुनाव जीतने के बाद बधाई देने में देर नहीं लगाई। नेतन्याहू को लगता है कि ट्रंप के आने के बाद उन्हें युद्ध अपने हिसाब से जारी रखने की छूट मिल जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले कार्यकाल में ट्रंप ने वेस्ट बैंक में इसाइली सेटलमेंट को समर्थन दिया था। तब उनके दामाद जेरेड कुशनर ने पश्चिम एशिया के लिए शांति समझौते का मसौदा तैयार किया था, जो इसाइल की ओर झुका हुआ था।

लेकिन दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने इस इलाके में शांति की अपील की थी। चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने कहा कि वह इस युद्ध को भी रुकवाएंगे। पिछले साल अक्टूबर में हमास के इसाइल पर हमले के बाद अमेरिका ने इसाइल को 18 बिलियन डॉलर की मदद दी है। ऐसे खर्च से बचने के लिए वह इसाइल से युद्ध रोकने को कह सकते हैं। आखिर, यूक्रेन मामले में भी उनकी दलील यही है। लेकिन यहां पेच ईरान की वजह से फंस सकता है। पहले कार्यकाल में ट्रंप ने जॉइंट कॉम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, (JCPOA), 2015 समझौते को रद्द कर दिया था। इसके तहत न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की एवज में अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियों में ढील दी थी। बाइडन इस समझौते को दोबारा लागू कराना चाहते थे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। ईरान अब ऐसा यूरेनियम तैयार करने के बेहद करीब है, जिसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में किया जा सकता है। ऐसे में ट्रंप को या तो ईरान से नया समझौता करना पड़ सकता है या वह ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने का फैसला कर सकते हैं। ट्रंप यह वादा कर चुके हैं कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। लेकिन यह भी सच है कि वह ईरान के साथ तनाव बढ़ाने के मूड में नहीं हैं। पश्चिम एशिया और ईरान को लेकर उनकी नीति समय के साथ स्पष्ट होगी और जानकार यह भी मानते हैं कि इसमें उनके करीबी सलाहकारों की भूमिका हो सकती है।

एकदा

तोते की आज़ादी

पंडित जवाहरलाल नेहरू बचपन में चंचल स्वभाव के थे। उन्हें खेलना बहुत पसंद था, लेकिन साथ ही वह बेहद संजीदा भी थे। घर का माहौल ऐसा था, जिससे आजादी की भावना सहज ही उनमें पैदा हो गई। बालक जवाहर ने जब से होश संभाला, तब से वह अंग्रेजों के अत्याचार के बारे में सुन रहे थे। उनके साथ खेलने वाले बच्चे भी कहा करते कि हम गुलाम हैं, इसलिए अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। इन बातों ने बालक जवाहर के मन में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश भर दिया। एक बार उनके एक दोस्त ने उनसे कहा कि अंग्रेज भारतीय किसानों पर बहुत अत्याचार करते हैं। उस दिन जब जवाहर स्कूल से लौटे, तो बेहद उदास थे। उनके दिमाग से दोस्त की बात निकल ही नहीं रही थी। उनके घर में एक तोता था, जिसे उनके पिता मोतीलाल नेहरू बहुत पसंद करते थे। जवाहर उस तोते के पिंजरे के पास जाकर खड़े हो गए। उन्हें देखकर तोता उछल-कूद करने लगा। तोते की बेचैनी देखकर जवाहर ने झट से पिंजरा खोल दिया। तोता तुरंत खुले आसमान में उड़ चला। कुछ देर बाद पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गया। यह देखते ही माली ने कहा, 'बेटा, तुमने यह क्या किया? पिताजी बहुत गुस्सा करेंगे। उन्हें यह तोता बहुत पसंद था।' इस पर बालक जवाहर ने मासूमियत से कहा, 'माली काका, पिताजी को कह दीजिएगा कि जब हमें आजादी प्यारी है तो क्या इस तोते को नहीं?' यह बात मोतीलाल नेहरू ने सुन ली। उन्होंने अपने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, 'मुझे बहुत गर्व है कि तुम मेरे बेटे हो।' माली बोला, 'साहब, देखना एक दिन आपका बच्चा पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन करेगा।'

Subrata Dhar

संकलन : रेनू सैनी

अमेरिका में ट्रंप की जीत ने दुनिया भर में उदारवादी राजनीति के तौर-तरीकों पर उठाए सवाल

क्या अपनी धार खो रहीं लिबरल ताक़तें

नरेन्द्र नाथ

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डॉनल्ड ट्रंप की जीत के बाद एक बार फिर पूरी दुनिया में उदारवादी दलों के नैरेटिव और जनता से कनेक्ट करने की उनकी क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव के दौरान वहां दोनों उम्मीदवारों ने अपने हिसाब से नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी। लेकिन चुनाव परिणाम ने साबित किया कि डेमोक्रेटिक पार्टी और कमला हैरिस ज्यादातर लोगों तक अपनी बात प्रभावी अंदाज में नहीं पहुंचा सकीं।

सभी तबकों से समर्थन | आंकड़े बताते हैं कि ट्रंप को दक्षिणपंथी खेमे ही नहीं, उन तबकों से भी अच्छे-खासे वोट मिले, जिनके बारे में अनुमान था कि वे लिबरल ताकतों का समर्थन करेंगे। लैटिन अमेरिकी मूल के लोगों ने ही नहीं, अश्वेत पुरुषों ने भी ट्रंप को कमला हैरिस से अधिक वोट किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने वोट देकर ट्रंप की नीतियों का सपोर्ट किया। उनके सामने 'आज की रात बचेंगे तो सहर देखेंगे' वाली स्थिति थी।

महंगाई और रोजगार | अधिकतर अमेरिकी मानते हैं कि उनका मौजूदा जीवन चुनौतियों से भरा है। पिछले कुछ बरसों में महंगाई ने उनके घरों का बजट बिगाड़ दिया है। उनके लिए नौकरी के मौके कम हुए हैं। वे आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वे सबसे पहले इन मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं। इन वोटरों ने वैचारिक तौर पर कमला हैरिस के साथ दिखने की बात कही, लेकिन आखिरकार वोटिंग पैटर्न अलग रहा।

तात्कालिकता | जानकारों के मुताबिक, यह सामान्य ट्रेंड रहा है कि जब लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो वे तात्कालिक तौर पर अपनी वैचारिक लड़ाई को विराम दे देते हैं। वे पहले अपने जीवन की प्राथमिक दिक्कतों को दूर करने का रास्ता तलाशते हैं। अमेरिका में इस बार के चुनाव में ऐसा ही हुआ। कई बोर डेमोक्रेट्स समर्थकों ने भी इस चुनाव में ट्रंप को वोट दे दिया। वे तत्काल अपने जीवन में आर्थिक चुनौतियों के मोर्चे पर हल चाहते थे और उन्हें लगा कि कमला हैरिस के लिए इसे दूर करना प्राथमिकता में नहीं है।

हालिया ग्लोबल ट्रेंड | अमेरिका में जो हुआ वह हाल के वर्षों में ग्लोबल ट्रेंड के रूप में भी उभरा है। लिबरल राजनीति अपने नैरेटिव को आम जन की जरूरतों, उनकी अपेक्षाओं के साथ कनेक्ट करने में विफल साबित हो रही है। इसका मूल कारण है आयडियॉलजिकल मुद्दों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर इसी के इर्द-गिर्द चुनाव लड़ने की रणनीति। वे जनता को यह बताने-समझाने में या तो देरी कर जाते हैं या कहीं न कहीं विफल हो जाते हैं कि कुनियादी मुद्दों को सुलझाने के लिए उनके पास भी कोई ब्लू प्रिंट है।

अबॉर्शन एकमात्र मुद्दा नहीं | यह सही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अबॉर्शन एक बड़े मुद्दे के रूप में सामने आया था। कमला हैरिस और उनकी टीम ने इसे प्रमुखता से उठाया भी। वह इस उम्मीद के साथ चुनावी मैदान में थीं कि इस पर उन्हें सभी महिलाओं का समर्थन मिलेगा। महिलाओं ने इस मुद्दे पर कमला हैरिस को मुखर समर्थन दिया भी। लेकिन जैसा कि ग्राउंड जीरो पर महिलाओं से हुई NBT की बातचीत में स्पष्ट हुआ, उनके लिए यह एक मुद्दा तो जरूर था, लेकिन सिर्फ यही मुद्दा नहीं था। एक महिला ने कहा, 'हमें अपने बच्चों की शिक्षा, घर के बढ़ते बजट, कम होते नौकरी के मौके के बारे में भी तो सोचना होगा। ये मुद्दे भी तो हमारे ही हैं।' ऐसी सोच वाली कई महिलाओं ने अबॉर्शन के मुद्दे पर हैरिस को समर्थन दिया, लेकिन वोट नहीं।

कोई हनीमून पीरियड नहीं | शानदार जीत के बावजूद ट्रंप की आगे की राह आसान नहीं है। लिबरल नैरेटिव में आई शून्यता का लाभ उठाकर उन्होंने सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन अब उनके सामने उन वादों पर अमल करने की चुनौती होगी। उनके पास कोई हनीमून पीरियड नहीं होगा। आर्थिक मोर्चे और रोजगार जैसे मुद्दों पर आम लोगों को राहत देने के साथ ही उन पर अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान चलाने का भी दबाव होगा। ध्यान रहे, ये दोनों काम साथ-साथ करना बहुत कठिन होगा। दोनों मकसद परस्पर विरोधी दिशा में हैं।

परस्पर विरोधी वादे | अधिकतर लोग मानते हैं कि ट्रंप को इस चुनाव में जनादेश वास्तव में देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मिला है। उन्होंने कई ऐसे वादे किए हैं, जिन्हें पूरा करना खासा मुश्किल साबित हो सकता है। कई मुद्दे ऐसे हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ बैठते हैं। मसलन- वे बड़ी कंपनियों के लिए टैक्स कम करने, बड़े रेट कट की बात करते हैं और साथ में महंगाई कम करने की भी बात कर रहे हैं। जाहिर है, दोनों मकसद एक साथ नहीं साधे जा सकते। देखना होगा कि इन स्थितियों में कमला हैरिस और डेमोक्रेट्स आने वाले दिनों में अपनी राजनीति को किस तरह आगे बढ़ाते हैं।

नई बहस | कुल मिलाकर डॉनल्ड ट्रंप की जीत ने ग्लोबल राजनीति में नई बहस की शुरुआत की है और उदारवादी राजनीतिक दलों के आगे के रोडमैप पर सवाल उठा दिया है। इसका जवाब काफी हद तक आने वाले समय के घटनाक्रम पर निर्भर करेगा।

(अमेरिका में डिपलोमैट ऑफ स्टेट के फॉरेन प्रेस सेंटर ने इस चुनाव में कवरेज के लिए NBT को भी खास आमंत्रण दिया था)

AI image

क्या कहते हैं नतीजे

- ट्रंप को अश्वेत पुरुषों के भी वोट मिले
- वैचारिकता पर भारी पड़े बुनियादी मुद्दे
- वोट में नहीं बदला अबॉर्शन पर सपोर्ट
- महिलाओं को महंगाई की ज्यादा चिंता

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

ये सांसें मिली हैं असली बिजनेस बढ़ाने के लिए

प्रेम रावत जी

आपने अपने जीवन में कई दरवाजे खोले हैं। आप स्कूल गए, पढ़ाई की। कॉलेज खत्म कर करियर बनाया, शादी हो गई, बच्चे हुए। लेकिन क्या वास्तव में यही जीवन है? क्या बस इतना ही होता है और फिर एक दिन सब खत्म हो जाता है? या आपके जीवन में कोई और द्वार है जिसे जानने की जरूरत है, उस द्वार को खोलने की जरूरत है?

जवाब है हां, आपके जीवन में एक और दरवाजा है, आत्म-ज्ञान का दरवाजा। स्वयं को समझने के लिए यह ऐसा दरवाजा है, जो शांति के महल में खुलता है। एक ऐसा दरवाजा, जो ज्ञान के ब्रह्मांड के लिए खुलता है। यह दरवाजा एक ऐसी दुनिया के लिए खुलता है, जहां हर कोई जीवन पाकर धन्य महसूस करता है। हर किसी को अस्तित्व के लिए आभारी होना चाहिए। हर इंसान ज्ञान की सहजता महसूस करता है। वह आनंद जो बस वहां है, वह सरलता जो हर जटिलता का जवाब है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। वह एक ऐसी दुनिया है, जहां इंसान बस इंसान बनकर खुश है। यहां आनंद का सागर है जिससे वह कुछ और बनने के लिए नहीं लड़ता, वह सिर्फ इंसान बनना चाहता है।

उस दुनिया में अपने आप को जानना ही अपने साथ एक गहरा अर्थ लेकर चलता है। यह स्वयं जीवन के उत्सव का संदेश देता है, जिसको ढूंढने के लिए लोगों ने अपनी सारी जिंदगी लगा दी। आज भी उसकी तलाश कर रहे हैं। जिसकी चर्चा के लिए हजारों-हजार किताबें लिखी गईं। जिसका गुणगान नहीं किया जा सकता है और न इसकी कोई जरूरत है। बस महसूस करने की जरूरत है। वह चीज तो हमारे-आपके अंदर पहले से है। वह इंतजार कर रही है कि हम उसे देखें और अपने हृदय के अंदर संतुष्टि प्राप्त करें। आपके जीवन में सब कुछ विधान के अनुसार होता है। उसी विधान के अनुसार सांसें आती-जाती हैं। हरेक श्वास के अंदर सुख-शांति का खजाना भरा गया है। अगर आप उस खजाने के ताले को ज्ञान की चाबी से खोल दें तो जीवन सफल हो जाएगा।

क्या आपने कभी अपने अंदर झांक कर देखा? अगर नहीं देखा है तो एक बार अपने हृदय के अंदर झांक कर देखें। आपके अंदर की दुनिया ही आपकी सच्ची दुनिया है। आपका असली बिजनेस क्या है? इस भवसागर से पार होना ही आपका असली बिजनेस है। इसीलिए भगवान ने आपको ये सांसें दी हैं। क्या आपको आत्मा का ज्ञान है? लोग आत्मज्ञान को अलग रखते हैं और कहते हैं कि आत्मा क्या है? बात आत्मा की नहीं है। बात है आत्मज्ञान की क्योंकि बिना ज्ञान पाए कोई कैसे समझ सकता है कि वह कौन है?

आप अपने आपको जो समझते हैं, हकीकत में वह है नहीं। आप क्या हैं? इसे समझने के लिए आपके अंदर जो चीज है उसको जानना होगा। बात विश्वास करने की नहीं, अनुभव करने की है। हमारा हृदय एक ऐसी शांति का अनुभव करना चाहता है, एक ऐसी खुशी का अनुभव करना चाहता है, जो सदा-सदा बनी रहे। यह ख्वाहिश न तो हमारे दिमाग की है और न मन की। यह ख्वाहिश है हमारे हृदय की। वह जीवन में हर दिन उस आनंद का अनुभव करना चाहता है।

प्रस्तुति : आर.डी. अग्रवाल 'प्रेमी'

ख़तरा सिर पर, क्या बचा पाएगा COP 29

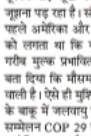

भाषा सिंह

जलवायु परिवर्तन से जुड़े खतरों को नजरअंदाज करने की कीमत अब सभी को चुकानी पड़ रही है। दुनिया लगातार गर्म हो रही है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और भीषण तूफान-बाढ़-सूखे की मार से सभी देशों को जूझना पड़ रहा है। संकट अब अस्तित्व पर है। पहले अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों को लगता था कि क्लाइमेट चेंज से केवल गरीब मुल्क प्रभावित होंगे, लेकिन समय ने बता दिया कि मौसम की मार सभी पर पड़ने वाली है। ऐसे ही मुश्किल वक्त में अजरबैजान के बाकू में जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन COP 29 हो रहा है।

अमेरिका का रवैया | तकनीक में बदलाव कर क्लाइमेट चेंज को किस तरह नियंत्रित किया जा सकता है, यह एक बड़ी चुनौती है। क्लीन एनर्जी, कार्बन फुटप्रिंट घटाने की रणनीति जितनी मजबूत और सर्वसम्मति से बनेगी, उतना ही हमारा-आपका और दुनिया का भविष्य सुरक्षित रहेगा। इसमें सबसे बड़ी अड़चन अमेरिका है।

ट्रंप से खतरा | डॉनल्ड ट्रंप की वापसी से लग रहा है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर अमेरिका का रुख फिर से नकारात्मक रहने वाला है। ट्रंप क्लाइमेट चेंज के खतरों को अस्वीकार नहीं मानते। 2016 में राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने पेरिस समझौते से अमेरिका को अलग कर दिया था। इस बार भी अमेरिकी रेस्पॉन्स पर कई चीजें निर्भर करेंगी। पश्चिमी देश अपने जिम्मेदारी से बचने का रास्ता तलाशते हैं और इसकी वजह से COP 29 का राजनीतिक महत्व लगातार कम हो रहा है।

तबाही का सिलसिला | इस बार लेकिन हालात अलग हैं, खासतौर से यूरोप के लिए। स्पेन में हुई तबाही से पूरा यूरोप सदमे में है। यहां के वेलेंसिया शहर में बीते 29 अक्टूबर को तीन घंटे के भीतर एक साल की बारिश हो गई। चिनाश आसमान से बारिश के रूप में आया, जिसने तुरंत ही सारी नदियों-नालों में उफान ला दिया। इस तबाही के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है क्लाइमेट चेंज। इस तरह की आपदा अब आम होती जा रही है। इराक में बाढ़ आई और सऊदी अरब में बर्फबारी हुई, जबकि गर्मी ने तो इस साल रेकॉर्ड ही बना दिया। इस सबसे जाहिर है कि प्राकृतिक तबाही का सिलसिला अभी और खतरनाक होने वाला है।

स्पेन में आपदा | स्पेन पर DANA की

कॉमन रूम

मार पड़ी। यह भूमध्य सागर का एक सिस्टम है। समुद्र के ऊपर की हवा गर्म होती है और जब उत्तर से ठंडी हवा आती है तो चक्रवात जैसी स्थिति बन जाती है। इससे आसपास के इलाकों में भीषण तबाही होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के ऊपर की हवा अब ज्यादा गर्म हो रही है। ऐसे में डिस्टर्बेंस का असर एक बड़े इलाके पर पड़ रहा है। स्पेन इसी का शिकार हुआ।

ऐतिहासिक अभियान | स्पेन की सरकार ने इसे यूरोप की दूसरी सबसे जानलेवा बाढ़ कहा है। लोगों को बचने का भी मौका नहीं मिला। सैकड़ों लोगों की जान गई। मदद के लिए सेना के जवानों को उतारना पड़ा। पूरी तरह से तबाह शहर को कीचड़-गंदगी-लाशों से मुक्त करने के लिए स्पेन के इतिहास का सबसे बड़ा पीसटाइम मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 7500 सैनिक लगे।

दोष किसका | COP 29 के समय यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या कोई भी देश अकेले इस तरह की प्राकृतिक आपदा का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इससे बचा जा सकता था? क्या यह इस शहर का, इस शहर में हुए निर्माण या विकास कार्यों का दोष था कि उसे इतनी बड़ी तबाही का शिकार होना पड़ा? बिल्कुल नहीं। इस तबाही की वजह स्पेन और उसका शहर वेलेंसिया नहीं थे। इसका दोष दुनियाभर में हो रहे जलवायु परिवर्तन के सिर जाता है।

समय की मांग | स्पेन के बाद साइप्रस, सऊदी अरब और दूसरे कई देशों को भी मौसम के सख्त रुख का सामना करना पड़ा। इस साल आर्मेन्या, चेक गणराज्य, क्रोएशिया, जर्मनी, हंगरी, इटली, पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकिया में बाढ़ से तबाही हुई है। इस पूरे इलाके में जलवायु परिवर्तन के खतरे के खिलाफ सक्रिय हस्तक्षेप करने की मांग उठा रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि COP 29 में इस दिशा में क्या ठोस प्रगति होती है।

80 प्रतिशत स्वास्थ्यगत समस्याएं और एक तिहाई मौतें जल-जनित बीमारियों के कारण होती हैं भारत में, एक अनुमान के अनुसार।

रोहित कौशिक
वरिष्ठ पत्रकार

आजकल

स्वच्छ गंगा का लंबा होता इंतजार

एनजीटी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन लाखों लीटर गंदा पानी गंगा और उसकी सहायक नदियों में गिर रहा है। कई जगहों पर गंगा का जल आचमन के लायक भी नहीं रह गया है। कटु सत्य यह है कि गंगा को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने में अभी तक अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी है। करोड़ों रुपये खर्च करने और अनेक योजनाएं आरंभ करने के बावजूद यदि अभी तक गंगा को प्रदूषण झेलना पड़ रहा है तो हमें इस विषय पर गंभीरतापूर्वक चिंतन करना होगा

गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए समाज को आना होगा आगे। फाइल

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन लाखों लीटर गंदा पानी गंगा और उसकी सहायक नदियों में गिर रहा है। प्रयागराज में गंगा का जल आचमन के लायक भी नहीं रह गया है। उत्तर प्रदेश के 326 नालों में से 247 नालों के पानी का शोधन नहीं किया जा रहा है। एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में 41 स्थानों पर गंगा के पानी की गुणवत्ता की निगरानी से यह पता चला है कि जल में फीकल कोलीफार्म बैक्टीरिया का स्तर 16 स्थानों पर मानक से अधिक है। केंद्र सरकार द्वारा 2014 में शुरू की गई नमामि गंगे परियोजना के तहत जून 2024 तक चालीस हजार करोड़ रुपये की योजनाएं शुरू की गई थीं। दुखद है कि इस परियोजना में अनेक स्तरों पर लापरवाही देखने को मिल रही है। हालांकि समय-समय पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस संबंध में कुछ प्रयास करता दिखाई देता है, लेकिन कटु सत्य यह है कि गंगा को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने में अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी है। करोड़ों रुपये खर्च करने और अनेक योजनाएं बनाने के बावजूद यदि अभी तक गंगा को प्रदूषण झेलना पड़ रहा है तो हमें इस विषय पर गंभीरतापूर्वक चिंतन करना होगा। हालांकि जलशक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट यह संकेत करती है कि साल 2018 से 2021 के बीच गंगा नदी के जल में उतना प्रदूषण नहीं रहा, जितना पहले था।

अगर गंगा के प्रति भारतीय समाज की आस्था सच्ची होती तो न गंगा प्रदूषित हुई होती और न ही हमें गंगा की स्वच्छता के लिए सरकारी नीतियों के भरोसे रहना पड़ता। गंगा हमें विभिन्न तौर-तरीकों से सुख-समृद्धि प्रदान करती रही, लेकिन हम गंगा को वह आदर नहीं दे पाए, जिसकी वह हकदार थी। भारतीय समाज ने आस्था की आड़ में गंगा पर जो कहर ढाया, वह अंततः समाज के लिए ही घातक सिद्ध हुआ। दरअसल अंध आस्था में हम अपनी आंखें इस कदर बंद कर लेते हैं कि हमें हमारी आंखें खोलने वाली चीजें दिखाई नहीं देती हैं। गंगा की स्वच्छता के लिए न जाने कितनी योजनाएं बनीं, लेकिन गंगा आज भी कराह रही है। गंगा की आरती में नारे लगाने वाला समाज जब तक इस मुद्दे पर जागरूक नहीं होगा, तब तक गंगा यूं ही प्रदूषण से कराहती रहेगी।

सेंटर फार साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) के विशेषज्ञों ने कुछ समय पहले कहा था कि गंगा की सफाई का अभियान इसी तरह चलता रहा तो आने वाले 30 वर्षों में भी गंगा साफ नहीं हो पाएगी। गौरतलब है कि गंगा के किनारे अनेक शहर, कस्बे और हजारों गांव स्थित हैं। प्रतिदिन इस आबादी का लगभग 1.3 बिलियन लीटर अपशिष्ट गंगा में गिरता है। गंगा के आस-पास स्थित सैकड़ों फैक्ट्रियां भी गंगा को प्रदूषित कर रही हैं। एक अनुमान के अनुसार प्रतिदिन लगभग 260 मिलियन लीटर औद्योगिक अपशिष्ट गंगा में जहर घोल रहा है। गंगा में फेंके जाने वाले कुल कचरे में लगभग अस्सी प्रतिशत नगरपालिका का कचरा होता है जबकि पंद्रह प्रतिशत औद्योगिक कचरा। नगरपालिका का कचरा विभिन्न तौर-तरीकों से गंगा के प्राकृतिक स्वरूप को नष्ट कर रहा है। वहीं औद्योगिक कचरा विभिन्न रसायनों के माध्यम से गंगा को जहरीला बना रहा है। पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या विस्फोट के कारण गंगा किनारे की आबादी तेजी से बढ़ी है। विडंबना यह है कि गंगा किनारे बसी इस आबादी ने भी गंगा को साफ-सुथरा रखने की कोई सुध नहीं ली, बल्कि इसे प्रदूषित ही किया। इस प्रदूषण के कारण ही आज हैजा, पीलिया, पेचिश और टायफाइड जैसी जल-जनित बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 80 प्रतिशत स्वास्थ्यगत समस्याएं और एक तिहाई मौतें जल-जनित बीमारियों के कारण ही होती हैं।

ऋषिकेश से प्रयागराज तक गंगा के आस-पास लगभग अनेक औद्योगिक इकाइयां स्थित हैं। इनमें चीनी मिल, पेपर फैक्ट्री, फर्टिलाइजर फैक्ट्री, तेलशोधक कारखाने, फार्मा कंपनियां तथा चमड़ा उद्योग प्रमुख हैं। इन सभी औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला कचरा और रसायनयुक्त गंदा पानी गंगा के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्ट में मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पारा, भारी धातुएं, कीटनाशक तथा पालिक्लोरिनेटिड बाइफिनाइल जैसे खतरनाक रसायन होते हैं। ये रसायन जानवरों एवं मनुष्यों की कोशिकाओं में जमा होकर बहुत सी बीमारियां उत्पन्न करते हैं। चमड़ा उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट में विभिन्न कार्बनिक पदार्थ, क्रोमियम, अमोनियम तथा कुछ अन्य तत्व होते हैं। ज्यादातर चमड़ा उद्योग में चर्मशोधन की प्रक्रिया के लिए क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में लगभग चालीस प्रतिशत क्रोमियम अपशिष्ट के रूप में बाहर निकलता है। पानी के साथ बहकर आने वाले रसायनिक उर्वरक एवं डीडीटी जैसे कीटनाशक भी गंगा के प्राकृतिक स्वरूप को नष्ट कर रहे हैं। जहरीला होने और कैंसर पैदा करने वाले प्रभावों को देखते हुए अमेरिका में डीडीटी का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। गंगा किनारे होने वाले दाह-संस्कार, श्रद्धालुओं द्वारा विसर्जित फूल, पालिथीन और अन्य सामग्रियां तथा जले-अधजले शव भी गंगा को बीमार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि एक ओर गंगा का प्रदूषण किसी न किसी रूप में बढ़ता जा रहा है तो दूसरी ओर गंगा का उद्गम स्थल भी प्रदूषण की चपेट में है। गंगोत्री ग्लेशियर की सतह पर कार्बन और कचरे की काली परत जमा हो गई है। प्रदूषण के कारण 144 वर्ग किमी में फैले गंगोत्री ग्लेशियर का रंग काला पड़ता जा रहा है। तापमान बढ़ने के कारण यह ग्लेशियर 18 मीटर प्रति वर्ष की गति से सिकुड़ता जा रहा है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार गंगा विश्व की उन दस नदियों में से एक है जिन पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। गंगा में मछलियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। अभी हाल में हुए एक अध्ययन में पता चला है कि गंगा को स्वच्छ बनाने में सहायक मछलियों की अनेक प्रजातियां प्रदूषण के कारण विलुप्त हो चुकी हैं। हमें यह समझना होगा कि केवल सरकारी योजनाओं के भरोसे ही गंगा को स्वच्छ नहीं बनाया जा सकता है। गंगा को प्रदूषण-मुक्त बनाने के लिए एक जन-जागरण अभियान की भी जरूरत है।

बिगड़ते पर्यावरण और मौसम के हम ही हैं दोषी

देवेंद्रराज सुथार
स्वतंत्र टिप्पणीकार

नवंबर का महीना आमतौर पर ठंड की शुरुआत का समय माना जाता है। यह वह समय होता है जब हल्की ठंडी बयार चलने लगती है और लोग रजाइयों, स्वेटर और गर्म कपड़ों को बाहर निकालते हैं, मगर इस बार नवंबर आ गया है और ठंड का कहीं नामोनिशान नहीं है। उल्टा घरों में अब भी पंखे, कूलर और कहीं-कहीं तो एसी भी चल रहे हैं। इस असामान्य गर्मी के कारण लोग हैरान हैं और मौसम में इस बदलाव ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आमतौर पर अक्टूबर के अंत तक ठंड की शुरुआत हो जानी चाहिए, लेकिन इस साल नवंबर के पहले हफ्ते में भी तापमान में खास गिरावट नहीं आई। सूरज की किरणों में वही तीखापन है और दोपहर के समय बाहर निकलना अभी भी चुनौतीपूर्ण लगता है। मौसम का यह बदलाव कोई संयोग नहीं है, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष परिणाम है। औद्योगिक गतिविधियों, वनों की कटाई और प्रदूषण के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। ग्रीनहाउस गैसों का स्तर बढ़ रहा है, जिससे गर्मी अधिक समय तक रहती है और ठंड के मौसम में देरी हो रही है। इसी कारण नवंबर जैसे ठंडक के प्रतीक्षित महीने में भी गर्मी का असर बना हुआ है।

ग्लोबल वार्मिंग के असर से केवल हमारे मौसम ही प्रभावित नहीं हो रहे हैं, बल्कि इसका प्रभाव हमारी कृषि, पेयजल उपलब्धता और स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। फसलों के लिए जरूरी ठंड का न होना और बढ़ता तापमान किसानों के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा है। गेहूं और सरसों जैसी रबी फसलों को ठंड की जरूरत होती है, लेकिन ठंड में हो रही देरी से इनकी पैदावार पर असर पड़ सकता है। गर्मी का लंबा खिंचना हमारी जीवनशैली को भी प्रभावित कर रहा है। सर्दियों की शुरुआत में लोग अपनी दिनचर्या और खानपान में बदलाव करते हैं, लेकिन इस बार गर्मी के कारण न तो हम गरम कपड़े पहन पा रहे हैं, न ही गर्म खाने का आनंद ले पा रहे हैं। लोग गर्मागर्म सूप या हल्दी दूध जैसे पेय पदार्थों का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, मगर इन सबका स्वाद लेने में अब भी गर्मी आड़े आ रही है।

स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मौसम में यह बदलाव चिंताजनक है। बदलते मौसम से लोगों में बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। गर्मी और ठंड के बीच की इस असमान्य स्थिति में सर्दी-खांसी, वायरल इंफेक्शन और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इन बदलावों को झेलने में कमजोर होता है। कहीं न कहीं हम ईश्वर ही इस बदलते मौसम के लिए अहम जिम्मेवर हैं। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग, जंगलों की कटाई और प्रदूषण ने मौसम के संतुलन को बिगाड़ दिया है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन अब केवल खबरों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। यदि समय रहते हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो यह स्थिति और भी विकट हो सकती है।

खरी-खरी

जिधर दम उधर हम

राजेंद्र बज

यदि हम जीवन में पूर्ण रूप से सुरक्षित तरीके के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो 'जिधर दम उधर हम' के ध्येय वाक्य को आत्मसात कर लेना चाहिए। जब दम के साथ हम होंगे, तब किसी भी परिस्थिति में बेदम नहीं हो सकेंगे। आज के इस घोर प्रतिस्पर्धात्मक युग में अपना बिकेट बचाते हुए चौकों-छक्कों की बरखत करने का यही एक माध्यम है। कहने को तो देश की राजनीति में आयाराम गयाराम की परंपरा को काफी हद तक कानूनी रूप से नियंत्रण में कर लिया गया है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है एक कानून बनता है तो दस गलियां बचाव की निकाल ली जाती हैं।

वैसे भी क्षणभंगुर मानव जीवन में एक सांस खींची है तो उसे छोड़ पाएंगे या नहीं-एक सांस छोड़ी है तो वापस खींच पाएंगे या नहीं? यह सब विधि के विधान के अधीन है। ऐसे में सक्रिय राजनीति करते हुए एक ही खूंटे से बंधे रहकर कब तक अपनी बारी का इंतजार किया जाए। इसलिए समय रहते समझदारी से काम लिया जाए। ऐसा नहीं है कि इधर से उधर या उधर से इधर होना अपनी निष्ठा को बदलने का सूचक होता है। जब व्यापक जनहित के प्रति समर्पित भूमिका के निर्वहन करने का संकल्प ले लिया जाता है, तो इस संकल्प को पूरा करने के लिए दल की प्राथमिकता अपने स्वयं के विवेक पर निर्भर होती है। जाहिर है हमारा विवेक अपने अच्छे-बुरे का खयाल रखते हुए ही काम किया करता है। इस दृष्टि से इधर से उधर या उधर से इधर होना हमारा मूलभूत अधिकार होता है। सौ की सौ बात है कि जब तक हम अपने स्वर्णिम भविष्य के प्रति निश्चिंत नहीं हो सकते, तब तक आखिर जनहित के प्रति समर्पित भूमिका का निर्वहन किस प्रकार कर सकेंगे?

दरअसल बात केवल राजनीति की ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में हमें दमदारी से खड़े होने के लिए दम के साथ होना जरूरी होता है। राजनीति में दम से आशय 'सत्ता का साथ' होता है। दफ्तर में बास के साथ खड़ा होना, समाज में बड़े गुट से जुड़ना, मोहल्ले में दमदारों की संगत में रहना और धनवान से नाता रखना यही बेहतर जीवन का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया करते हैं।

पोस्ट

बांग्लादेशी घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। नकली आधार, नकली पासपोर्ट आसानी से बंगाल के बाजार में बनता है।
अखिलेश सिंह@akhileshsi1

कमला हैरिस की हार में यही सबक छिपा है कि जब मीडिया हद से ज्यादा पक्षपाती होकर एक पार्टी के साथ जुड़ जाए तो वह उस पार्टी को ही छलने का काम करता है। अमेरिकी मीडिया ने फतासी भरा ऐसा जाल बुना, जिसका स्वाभाविक तौर पर जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं था।
ब्रह्म चेलानी@Chellaney

माइकल वाल्ट्ज अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनते ही तो यह भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। उनका भारत के प्रति बहुत सकारात्मक रुख रहा है और यह सशक्त भारत-अमेरिकी रणनीतिक साझेदारी की बात करते आए हैं।
कंवल सिबल@KanwalSibal

आविष्कार-नवाचार में अमेरिका के अग्रणी रहने का एक कारण उसकी सरकार गठन व्यवस्था भी है, जो राष्ट्रपति को प्रशासन चुनने की आजादी देती है, जिसमें अवसर नस्ल-राजनीति पर योग्यता को प्राथमिकता मिलती है।
शिव कांत@shivkant

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में जसप्रीत बुमराह को कप्तानी की जिम्मेदारी देने का फैसला सही है?

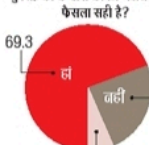

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या दीवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध से वायु प्रदूषण रोकने में मदद मिल रही है?

परिणाम जागरण ईस्टर्न्ट संस्करण के घंटकों का मत है।

जनपथ

तीखा होता जा रहा अब चुनाव अभियान,
है तलवारें खिंच रहीं खड़ाक रहे हैं म्यान।
खड़क रहे हैं म्यान चुनावी है यह मेला,
ध्वनीकरण का आजकी रहा खुलकर खेला।
जमता नहीं चुनाव अगर रहो पीका-फीका,
अच्छाहै आरोप लगाओ तीखा-तीखा।
- ओमप्रकाश तिवारी

पंजाब डायरी

इन्द्रप्रीत सिंह
ब्यूरो प्रमुख, पंजाब

उपचुनाव नतीजे तय करेंगे भाजपा की राह

हाल में भाजपा के पंजाब के वर्तमान प्रमुख सुनील जाखड़ ने पार्टी हाईकमान को पंजाब का कोई नया प्रमुख चुनने के लिए कहा। अब नया प्रमुख कौन हो? इसको लेकर पार्टी में मंथन शुरू हो गया है। शिरोमणि अकाली दल से संबंध विच्छेद होने के बाद से भाजपा अपने दम पर पंजाब में सरकार बनने को आतुर है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक उसे इस दिशा में सफलता नहीं मिली है। इसके लिए पार्टी तरह-तरह के प्रयोग भी कर रही है, लेकिन अभी तक उसको कोई भी कोशिश कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले दिनों ही सुनील जाखड़ ने अपने फेसबुक पेज पर शिरोमणि अकाली दल के साथ फिर से गठजोड़ करने की बात दोहराई थी।

पंजाब की चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। भाजपा ने इनमें चार बड़े सिख चेहरे उतारे हैं। इसके पीछे पार्टी का एक बड़ा मकसद यह है कि वह शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनके जरिये अपना विस्तार करना चाहती है। भाजपा उपचुनाव में पूर्व मंत्री मनप्रीत बादल, पूर्व मंत्री सोहन सिंह ठंडल, पूर्व विधायक केवल ढिल्लों और पूर्व स्पीकर निर्मल सिंह काहलों के बेटे रवि किरण काहलों को उतारकर एक बड़ा संदेश तो दे ही रही है कि उसकी नजर 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव पर है। इसके साथ भाजपा पंजाब के लोगों में यह मैसेज भी सेट कर रही है कि उन्होंने अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकारों को देख लिया है, उन्हें एक मौका भाजपा को भी देना चाहिए। शिरोमणि अकाली दल के साथ साल 1997 से लेकर 2021 तक भाजपा ने पंजाब में गठबंधन में तीन सरकारें बनाईं, लेकिन इनमें भाजपा सिर्फ नाम की हिस्सेदार थी, शासन में वह कहीं नहीं थी। तीन कृषि सुधार कानूनों को लेकर शिरोमणि अकाली दल से टूटे गठबंधन के बाद वर्ष 2022 का पंजाब विधानसभा चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव, भाजपा ने ये दोनों चुनाव अपने दम पर लड़े हैं जिसमें उसे क्रमशः 6.60 प्रतिशत और 24 प्रतिशत वोट मिले हैं। अब इस उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार कितना वोट हासिल कर पाते हैं इसके बाद पंजाब में भाजपा की बहुत हद तक दिशा तय होगी।

पंजाब में जनधार बढ़ाने को आतुर भाजपा। फाइल

दरअसल भाजपा ने कांग्रेस के तेज तर्रार नेता रहे सुनील जाखड़ को अपने में लाकर पंजाब में जो प्रयोग किया, वह ज्यादा सफल नहीं हो सका। सुनील जाखड़ के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सहित उनकी कैबिनेट में रहे आधा दर्जन मंत्री भी भाजपा में शामिल हुए, लेकिन इनमें से कई वापस लौट गए हैं, क्योंकि भाजपा के मूल कार्यकर्ताओं और अन्य पार्टियों से आए नेताओं में संतुलन नहीं बन पा रहा था। भाजपा के मूल कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि अन्य पार्टियों से लाए हुए लोगों को उन पर थोपा जा रहा है। उन्होंने पार्टी तो नहीं छोड़ी, लेकिन वे निराश होकर अपने-अपने घरों में बैठ गए। अब जबकि भाजपा में एक बार फिर से नए पंजाब प्रमुख बनाने की बात चल रही है तो पार्टी में इस सवाल पर मंथन शुरू हो गया है कि क्या नए प्रमुख का चुनाव पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं में से ही किया जाए या बाहर से कोई बड़ा चेहरा लाया जाए?

दूसरी पार्टियों से भाजपा में आए दो चेहरे मनप्रीत बादल और केवल ढिल्लों इस समय उपचुनाव लड़ रहे हैं। दोनों जीत के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं। उनकी जीत के लिए भाजपा के कई बड़े नेता भी प्रचार के लिए मैदान में कूदे हुए हैं। मनप्रीत बादल की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अच्छी तालमेल है। मनप्रीत बादल भाजपा के लिए एक ऐसा चेहरा हैं जिसे वह सिख चेहरे के रूप में भी प्रचारित कर सकती है। इनकी किसानों में भी अच्छी पकड़ है, लेकिन पार्टी का एक बड़ा वर्ग संगठन से किसी हिंदू चेहरे को आगे करने की बात कर रहा है। उसकी दलील है कि तीन कृषि सुधार कानूनों के बाद से भाजपा के प्रति पंजाब के एक बड़े किसान वर्ग की नाराजगी अभी दूर नहीं हो पाई है। इसलिए उनका वोट पार्टी को किसी भी तरह नहीं मिलेगा। ऐसे में पार्टी को अपना ध्यान हिंदुओं और अनुसूचित जातियों के वोटों को हासिल करने पर ही फोकस करना चाहिए। शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस समय किसानों को ही साधने में लगे हुए हैं और इसी को फोकस करके चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर भाजपा भी उसी राह पर चलती है तो उसके हाथ कुछ नहीं आने वाला।

हरियाणा डायरी

ईवीएम की आड़ में गुटबाजी छिपाती कांग्रेस

अनुराग अग्रवाल
राज्य ब्यूरो प्रमुख, हरियाणा

हरियाणा में कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले तो गुटबाजी का शिकार थी ही, अब नतीजों के बाद भी गुटबाजी का शिकार है। राज्य में कांग्रेस के कई नेता इस गुटबाजी को खत्म करने की दिशा में गंभीर नहीं हैं। कांग्रेस की ओर से चुनाव नतीजों के बाद हार का दोष ईवीएम पर डालने की लाख कोशिश हुई, मगर उसे कामयाबी नहीं मिली। चुनाव आयोग के पास राज्य की 20 विधानसभा सीटों पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत की गई थी, पर चुनाव आयोग ने ईवीएम के संचालन की पूरी प्रक्रिया समझाते हुए 1642 पेज का जो जवाब कांग्रेस नेताओं को थमाया है, उससे उनकी सांस फूली हुई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ईवीएम को किस तरह से कांग्रेस की हार का जिम्मेदार ठहराया जाए। कांग्रेस को भाजपा के इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं मिल रहा कि जिन 37 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की जीत हुई है, वहां ईवीएम खराब थी या नहीं। अगर वहां ईवीएम खराब नहीं थी तो फिर कांग्रेस द्वारा जिन 20 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम की खराबी का दावा किया जा रहा है, वह कैसे सच हो सकता है?

कांग्रेस को इस बार उम्मीद थी कि वह सत्ता में लौटेगी, लेकिन कांग्रेस नेताओं का अति आत्मविश्वास, चुनाव प्रबंधन में खामियां, टिकटों का गलत आवंटन तथा पार्टी नेताओं की आपसी गुटबाजी ने कांग्रेस के सारे सपनों पर पानी फेर दिया। कांग्रेस खासकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थकों को अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि भाजपा तीसरी बार राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है। इस बात को कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी मानने लगा है कि यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा मिलकर चलते तो राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती, मगर दोनों के आपसी मनमुटाव दूर करने की दिशा में कोई प्रयास सिरे नहीं चढ़ा पाया। गत दिनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक आंतरिक संवाद में बड़े ही मजाकिया लहजे में कहा कि कांग्रेस वालों ने तो चंडीगढ़ के विश्राम गृहों पर कब्जा कर लिया था। हमने आकर उन्हें कहा, कांग्रेस की नहीं, भाजपा की सरकार बनी है। आप वापस जाओ।

कांग्रेस हाईकमान के समानांतर राज्य कांग्रेस कमेटी ने पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के नेतृत्व में आठ सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, जो चुनाव हारे सभी उम्मीदवारों से हार के कारण जान रही है। इस कमेटी के सामने अभी तक जो तथ्य आए हैं, उनके मुताबिक हुड्डा और सैलजा की आपसी खींचतान हरियाणा में कांग्रेस की हार का बड़ा कारण बनी है, लेकिन कहा जा रहा है कि दलाल कमेटी की जो रिपोर्ट तैयार होगी, उसमें ईवीएम को ही हार के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, ताकि इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय चुनाव आयोग को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में घसीटा जा सके। केंद्रीय चुनाव आयोग ने हरियाणा से पहले भी कई राज्यों में चुनाव कराए हैं। हाल में लोकसभा चुनाव हुए हैं। अब महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हो रहे हैं। हर बार कांग्रेस समेत भाजपा विरोधी दल ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करते हैं, मगर उसे साबित नहीं कर सके हैं। करण सिंह दलाल के नेतृत्व वाली कमेटी एक बार फिर पार्टी नेताओं की आपसी गुटबाजी और उनके राजनीतिक स्वार्थ को छिपाने की मंशा से ईवीएम के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है।

ईवीएम के विरुद्ध छेड़ी जा रही इस लड़ाई से अतिरिक्त हरियाणा में एक दूसरे पर दोषारोपण का खेल अलग से चल पड़ा है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया अपनी अस्वस्थता का हवाला देकर पद छोड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। पार्टी हाईकमान ने उनकी मदद के लिए जितेंद्र बघेल को सह प्रभारी नियुक्त कर दिया है, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, जो कि होडल विधानसभा सीट से स्वयं चुनाव हार गए हैं, उन्होंने राज्य में संगठन नहीं बनने का दोष दीपक बाबरिया पर डाल दिया है। राज्य में पिछले 11 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं है। इस अवधि में डा. अशोक तंवर, कुमारी सैलजा और अब उदयभान प्रदेश अध्यक्ष हैं। संगठन नहीं बन पाने में जितना दोष प्रभारी का है, उतना दोष प्रदेश अध्यक्ष और उन प्रमुख नेताओं का है, जो कोटा सिस्टम के माध्यम से अपने समर्थकों को पार्टी संगठन में शामिल कराना चाहते थे। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष उदयभान राज्य में हुई कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं। कांग्रेस की आपसी गुटबाजी का ही नतीजा है कि 13 नवंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस पहली बार बिना विधायक दल के नेता के सरकार का सामना करती नजर आएगी।

कुमारी सैलजा एवं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आपसी खींचतान में फंसी कांग्रेस। फाइल

****

दैनिक जागरण
जो विचार व्यवहार में न आ पाए वह व्यर्थ है

असहाय नगर निकाय

इस पर हैरानी नहीं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग ने यह पाया कि देश के अधिकांश नगर निकाय न तो अपने स्रोतों से धन जुटाने में समर्थ हैं और न ही आवंटन के जरिये मिले पैसे का पूरा उपयोग कर पाने में। स्पष्ट है कि ऐसे में शहरों की स्थिति सुधरने की जो आशा की जा रही है, वह पूरी होने वाली नहीं है। कैग की रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि राज्य सरकारें अपने नगर निकायों को वंछित अधिकार देने को तैयार नहीं। वे इस पर भी ध्यान नहीं दे रही हैं कि नगर निकाय कर्मचारियों की कमी का सामना कर रहे हैं। यह विचित्र है कि जो राज्य सरकारें संघीय ढांचे का हवाला देकर केंद्र पर यह आरोप लगाती रहती हैं कि वह उन्हें पूरी स्वतंत्रता से काम नहीं करने देती, वे अपने नगर निकायों को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मिलीं आवश्यक शक्तियां देने को तैयार नहीं। आखिर आवश्यक अधिकारों के अभाव में नगर निकाय अपना काम सही तरह से कैसे कर पाएंगे? ऐसा लगता है कि राज्य सरकारें यह बुनियादी बात समझने को तैयार नहीं कि शहरी निकाय एक तरह से शासन की तीसरी इकाई हैं और उनका समर्थ होना आवश्यक है। निःसंदेह उन्हें समर्थ बनाने के साथ ही इसकी भी आवश्यकता है कि उन्हें उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाया जाए। यह ठीक नहीं कि राज्य सरकारें इनमें से भी कोई काम नहीं कर रही हैं। उचित यह होगा कि केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेशों के जरिये राज्यों के समक्ष ऐसा कोई उदाहरण पेश करे कि शहरी निकायों को किन अधिकारों से लैस होना चाहिए, उन्हें अपना काम कैसे करना चाहिए और खुद को आर्थिक रूप से सक्षम कैसे बनाना चाहिए?

यह समझा जाना चाहिए कि शहरों की सूरत तब तक नहीं संवर सकती, जब तक नगर निकाय प्रशासनिक और आर्थिक रूप से सक्षम बनने के साथ ही शहरों के विकास की ऐसी योजनाएं बनाने में समर्थ नहीं होते, जो दीर्घकालिक और भविष्य की जरूरतों को पूरी करने वाली हों। चूंकि आम तौर पर शहरी विकास की ज्यादातर योजनाएं समस्याओं का फौरी समाधान करती दिखती हैं, इसलिए तमाम विकास कार्यों के बाद भी शहरों में विभिन्न समस्याएं सदैव सिर उठाए हुए दिखती हैं। क्या यह किसी से छिपा है कि किस तरह नए बने रास्ते, फ्लाईओवर, बाईपास आदि किस तरह कुछ समय बाद अपर्याप्त सिद्ध होने लगते हैं? पता नहीं क्यों आज भी शहरी योजनाएं यह ध्यान में रखकर नहीं बनाई जातीं कि आज से 50-60 साल बाद आबादी क्या होगी और उसके लिए कैसा आधारभूत ढांचा चाहिए होगा? कभी-कभी तो यह लगता है कि इस पर कोई विचार ही नहीं करता कि आज जो बुनियादी ढांचा बनाया जा रहा है, वह भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकेगा या नहीं? यह स्थिति तब है, जब देश के सभी छोटे-बड़े शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है।

ताकि सुरक्षित रहे घर

हिमाचल प्रदेश में चोरी की बढ़ती घटनाओं के बीच शिमला पुलिस ने नागरिकों को व्यावहारिक सुझाव दिया है कि वे कुत्ता पालें। व्यावहारिक इसलिए कि पुलिस सब स्थानों पर नहीं हो सकती। परामर्श और भी हैं किंतु यह इसलिए ध्यान खींचता है, क्योंकि इससे आवारा कुत्तों के आतंक की समस्या भी हल हो सकती है। हालांकि शहर का पर्याप्त क्षेत्र सीसीटीवी कैमरों से जुड़ा है किंतु सीसीटीवी में घटना होने के बाद दिखती है। पुलिस का काम बढ़ता है। तब तक हानि हो चुकी होती है। परामर्श ठोस है किंतु यह तब तक परामर्श की अवस्था में ही रहेगा जब तक इसे अंतरविभागीय विषय न माना जाए। इसमें नगर निगम, शहरी विकास विभाग, स्वास्थ्य और पशुपालन या पशुचिकित्सा विभाग के साथ समाज में गंभीरतापूर्वक विचार करे। आलम यह है कि नगर निगम के पास 277 कुत्तों का पंजीकरण हुआ है जबकि आवारा कुत्तों की कोई गणना नहीं तो गणित भी नहीं। कुत्ता वफादार पशु है किंतु देशभर की हालिया घटनाएं बताती हैं कि कतिपय ब्रीडेशी प्रजातियों के कुत्ते पालकों के लिए भी समस्या बन रहे हैं। उन्हें जुड़ाव नहीं होता। गलियों के कुत्तों को अपना कर आवारा आतंक कम किया जा सकता है यदि समाज प्रजाति के हिसाब से मेरा कुत्ता, उसके कुत्ते से बेहतर हो की मानसिकता से ग्रसित न हो। यदि कुत्तें से पहरे का काम लेना है तो उनकी क्वैरलीनेशन और नीगर होने पर उचित उपचार की सुविधाएं भी उतनी ही आवश्यक हैं। कुत्तें की संख्या कम करने के प्रति भी स्थानीय निकायों को गंभीर होना होगा। शौक समझें या विवशता, कुत्ता पालना जिम्मेदारी से किया जाने वाला कार्य है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आवारा कुत्तों को मारा जाना अपराध है। यदि आवारा कुत्तों को अपनाया जाए तो वे काम भी आएंगे और आतंक भी कम होगा। आशा की जानी चाहिए कि इस परामर्श पर सभी पक्ष मंथन करेंगे। मंथन से ही सही रास्ता मिलेगा।

सरकारी मनमानी को रोकने वाला फैसला

विकास सारस्वत

समाजवाद के नाम पर विधायिका द्वारा व्यक्तिगत अधिकारों के हनन का जो प्रयास अनवरत चला, उस पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी

अवधेश राजपूत

गत पांच नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने संपत्ति के अधिकार को लेकर दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में लंबे समय से चली आ रही कानूनी विसंगति को सैमित मायने में ही सही, परंतु ठीक कर दिया। इस निर्णय के पहले विभिन्न कानूनों और निर्णयों के चलते सरकारों के पास निजी संपत्ति को 'सार्वजनिक हित' का उल्लेख कर अधिग्रहण करने का व्यापक अधिकार मिल गया था। साथ ही, उन्हें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संपत्तियों को सामुदायिक संसाधन की श्रेणी में डालने का भी मनमाना अधिकार मिला हुआ था। यह ऐतिहासिक निर्णय प्रापर्टी ओनर्स एसोसिएशन आफ मुंबई बनाम महाराष्ट्र सरकार के 1992 से चले आ रहे उस वाद में आया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण एक्ट (म्हाडा) के चैप्टर आठ को चुनौती दी थी। 1976 में पारित और 1986 में संशोधित यह एक्ट संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत 39(बी) का हवाला देकर निजी संपत्ति के सरकारी अधिग्रहण को उचित ठहरा रहा था। अनुच्छेद 39 (बी) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से वितरित करने की बात करता है, जिसमें लोक हित की पूर्ति सर्वोत्तम रूप से हो सके। उपरोक्त वाद में म्हाडा द्वारा संपत्ति के अधिकार के हनन के अलावा अनुच्छेद 39 (बी) पर स्पष्टीकरण की मांग थी। याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय से जानना चाहा कि क्या निजी संपत्ति सामुदायिक संसाधन के दायरे में आती है? साथ ही इस वाद से बेंच के समक्ष यह प्रश्न भी खड़ा हुआ कि क्या कालांतर में आए संशोधनों के बाद भी अनुच्छेद 31(सी) की प्रासंगिकता बनी रहती है?

यह उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में किए गए बैंकों के राष्ट्रीयकरण को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त करने के बाद 25वें संवैधानिक संशोधन से अनुच्छेद 31(सी) को लाया गया था। इस अनुच्छेद का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना था कि अनुच्छेद 39(बी) और 39(सी) को न्यायिक समीक्षा से परे रखा जा सके और सरकार द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण करने की सूरत में अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार और अनुच्छेद 19(1) (एफ) में दिए गए संपत्ति के मौलिक अधिकार को आधार बना कर न्यायिक चुनौती न दी जा सके। लोकलुभावन राजनीति और वैचारिक चेष्टा से प्रेरित इस संशोधन को केशवानंद भारती केस में चुनौती मिली और सर्वोच्च न्यायालय की 13 सदस्यीय बेंच ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में अनुच्छेद 31(सी) को वैध तो ठहराया, परंतु अधिग्रहित संपत्तियों को न्यायिक समीक्षा के दायरे में रहने दिया। इससे पहले भूमि वितरण के लिए बढ़ते दबाव में नेहरू सरकार द्वारा लाए गए प्रथम और चौथे संशोधनों पर सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। इसमें विधायिका द्वारा संपत्ति के अधिकार सहित अन्य मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने वाले संशोधनों पर रोक लगा दी गई।

यह तत्कालीन भारतीय राजनीति पर छाए समाजवादी प्रभाव का ही नतीजा था कि जिन मोरारजी देसाई ने 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विरोध में इंदिरा कैबिनेट से इस्तीफा दिया, उन्हीं के कार्यकाल में 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन की बदौलत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बदलकर महज एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में गठित बेंच ने अनुच्छेद 31(सी) को तो केशवानंद भारती निर्णय के अनुरूप आंशिक रूप से बहाल रखा, परंतु निजी संपत्ति के सरकारी नियंत्रण पर अंकुश लग दिया। अपने आदेश में न्यायालय ने लिखा है कि प्रत्येक निजी संपत्ति समुदाय का भौतिक संसाधन नहीं हो सकती। साथ ही न्यायालय ने 1983 के सीजीव कोक बनाम भारत कोकिंग कोल मामले में जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय पीठ के उस निर्णय पर भी प्रतिकूल टिप्पणी की, जिसमें जस्टिस रेड्डी की पीठ ने धीमित रूप से समाजवादी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सार्वजनिक-निजी क्षेत्र के सभी उपक्रमों को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया था। वर्तमान पीठ ने 1983 समेत अन्य निर्णयों को एक विशेष आर्थिक विचार से प्रेरित बताकर न्याय को वैचारिक चेष्टाओं से मुक्त रखने की बड़ी बात कही है।

संपत्ति का अधिकार सभी कालखंडों में सभ्य समाजों की आधारशिला रहा है। संपत्ति के अधिकार के बिना मनुष्य की स्वतंत्रता अकल्पनीय है। किसी भी कारगर राजनीतिक व्यवस्था से अपेक्षा रहती है कि वह इस अधिकार की सुरक्षा करेगी, परंतु इस विषय में भारतीय विधायिका की भूमिका निराशाजनक रही है। आपत्तिजनक तरीके से अर्जित और समरसता में बाधा बनने वाली जमींदारी संस्तियों को छोड़ भी दें तो समाजवादी राजनीति ने व्यवस्था से लेकर मठ- मंदिरों की निजी संस्तियों को भी अनेक कानून बनाकर अधिग्रहित किया। सक्रिय राजनीति से न्यायपालिका में आए जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर के समाजवादी दृष्टिकोण से दिए गए निर्णयों ने भी कई स्तरों पर न्यायपालिका को प्रभावित किया और फलस्वरूप संपत्ति का अधिकार रौंदा जाता रहा।

संपत्ति के स्वामी को अलग रखकर सरकार या कब्जेदार किसी निजी संपत्ति का निर्णय आपस में कर लें, ऐसी कल्पना कानून के राज पर प्रश्नचिह्न लगाती है। हालांकि उपरोक्त वाद को ही लें तो म्हाडा का चैप्टर आठ इसकी अनुमति देता था कि यदि संपत्ति के 70 प्रतिशत कब्जेदार सहमति दे दें तो वह संपत्ति उनके द्वारा बनाई गई सहकारी समिति के नाम स्थानांतरित की जा सकती है। पांच नवंबर के निर्णय के बावजूद अभी वह स्थिति बहाल नहीं हुई है, जिसमें संविधान सभा ने लंबी बहस के बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार का रूप दिया था, लेकिन इससे सरकारों की मनमानी पर रोक अवश्य लगेगी। यह विषय न्यायपालिका और विधायिका के बीच सबसे लंबे संघर्ष का कारण बना। एक छोटे कालखंड को छोड़ दें तो समाजवाद के नाम पर विधायिका द्वारा व्यक्तिगत अधिकारों के हनन का जो प्रयास अनवरत चला है, उसे रोकने में न्यायपालिका की भूमिका सराहनीय रही है। इसी क्रम में आए हालिया निर्णय के लिए देश न्यायपालिका का आभारी है।

(लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

समस्या पर शोर मचे तो समाधान भी हो

राजीव सचान

आखिर बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ पर चिंता जताते रहने वाली केंद्र सरकार उस पर रोक कब लगाएगी?

अहमदाबाद में गिरफ्तार बांग्लादेशी घुसपैठिए। प्रेट्र

त्रिपुरा, असम और बंगाल में जब भी चुनाव होते हैं, तब अन्य अनेक मुद्दों के साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा अवश्य उठता है। इस बार ऐसा झारखंड में भी हो रहा है। बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ विधानसभा चुनावों में बड़ा मुद्दा बन गई है। जहां भाजपा इस पर जोर देने में लगी हुई है कि बांग्लादेश से बंगाल के रास्ते आने वाले बांग्लादेशी न केवल झारखंड की जनसांख्यिकी (डेमोग्राफी) बदल रहे हैं, बल्कि आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं और उनकी जमीन भी हड़प रहे हैं, वहीं सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की मानें तो भाजपा जो कुछ कह रही है, वह सही नहीं। झामुमो नेताओं का कहना है कि यदि बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है तो फिर जवाबदेह केंद्र सरकार है, क्योंकि सीमा सुरक्षा उसके हो कंधों पर है। पता नहीं चुनाव में झारखंड की जनता किसकी बातों को महत्व देगी, मगर इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है।

दो वर्ष पहले झारखंड हाई कोर्ट में जमशेदपुर के सैयद दानियाल दानिश की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा आदि जिलों में आदिवासी आबादी घट रही है, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों को आदिवासियों की जमीन पर बसाया जा रहा है। वास्तव में भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर जो कुछ कह रही है, वह मोटे तौर वही है, जिसका उल्लेख दानिश की याचिका में किया गया है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सितंबर में झारखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का पता लगाने के लिए केंद्र और राज्य के अधिकारियों की एक तथ्य खोजी यानी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए। झारखंड सरकार पहले तो इसके लिए तैयार हो गई, लेकिन फिर पीछे हट गई और हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखने को कहा है। पता नहीं, सुप्रीम कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचेगा, लेकिन यह एक सच्चाई है कि बांग्लादेश से घुसपैठ होती है। यदि बंगाल के रास्ते घुसे बांग्लादेशी झारखंड आकर बस गए हों तो हैरानी नहीं। वैसे भी यह सच है कि झारखंड के आदिवासी बहुल इलाकों में डेमोग्राफी बदली है। यह असम, त्रिपुरा और बंगाल में भी बदली है और अब तो टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में भी बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के चलते आबादी का संतुलन बिगड़ रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार यदि यही हाल रहा तो 2051 तक मुंबई में हिंदू आबादी घटकर 54 प्रतिशत से भी कम हो जाएगी और बांग्लादेशी घुसपैठियों एवं रोहिंग्याओं के कारण मुस्लिमों की आबादी 30 प्रतिशत हो जाएगी। इस रिपोर्ट के अनुसार 2011 में मुंबई में हिंदुओं की आबादी 66 प्रतिशत और मुसलमानों की 21 प्रतिशत थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ राजनीतिक संगठन वोट बैंक की राजनीति के लिए अवैध अप्रवासियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव के चलते भाजपा ने इस रिपोर्ट का जोर-शोर से उल्लेख करना शुरू कर दिया है, लेकिन क्या इतना ही पर्याप्त है?

बांग्लादेश से भारत में तबसे घुसपैठ हो रही है, जब वह पूर्वी पाकिस्तान था। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बन जाने के बाद भी वहां से घुसपैठ जारी रही और अब भी हो रही है। बंगाल, असम, त्रिपुरा के रास्ते अवैध रूप से भारत आए बांग्लादेशी घुसपैठिए आए दिन देश के विभिन्न हिस्सों में पकड़े जाते हैं। कुछ समय पहले पुणे में 21 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए। इनके पास नकली आधार, पैन और वोटर आइडी भी थे। इसी तरह हाल में अहमदाबाद में करीब 50 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए। इनमें से कई के पास फर्जी पहचान पत्र थे। इस पर चकित होने की जरूरत नहीं कि भारत में घुसने वाले बांग्लादेशी पुणे, अहमदाबाद तक कैसे पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा में घुसकर रोहिंग्याओं ने दिल्ली, जम्मू, हैदराबाद तक में अपने ठिकाने बना लिए हैं। कहना कठिन है कि देश में कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, लेकिन यह पक्का है कि वे ठीक-ठाक संख्या में हैं। प्रश्न यह है कि उनकी घुसपैठ थम क्यों नहीं रही और उन्हें बाहर निकालने में सफलता क्यों नहीं मिल रही है? केवल इतना ही पर्याप्त नहीं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुनावी मुद्दा बनाया जाए। इस मुद्दे का समाधान भी होना चाहिए और वह भी प्राथमिकता के आधार पर।

भाजपा बंगाल और झारखंड के मुख्यमंत्रियों पर यह आरोप लगाती रहती है कि वे बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर उदार हैं और उन्हें अपना वोट बैंक बनाने की ताक में रहते हैं। ऐसा ही आरोप रोहिंग्याओं को लेकर भी लगता है। इस नतीजे पर पहुंचने के पर्याप्त कारण हैं कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की घुसपैठ कराकर उन्हें सुनियोजित तरीके से भारतीय नागरिक बनाया जा रहा है, लेकिन इस सवाल में भी दम है कि आखिर केंद्र सरकार घुसपैठ रोकने के लिए क्या कर रही है? सीमाओं की सुरक्षा के साथ घुसपैठियों की पहचान करना और उन्हें निकालना तो उसका ही काम है।

पिछले दस वर्षों में गृहमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री कई बार बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन उनकी घुसपैठ रोकने और उन्हें निष्कासित करने के मामले में नतीजा ढाक के तीन पात वाला है। घुसपैठ एक राष्ट्रघाती समस्या है। इस समस्या पर शोर मचाने से ज्यादा जरूरी यह है कि उसका समाधान हो। घुसपैठिए यानी अवैध अप्रवासी पश्चिमी देशों में भी एक बड़ा मुद्दा बन गए हैं, लेकिन वे उनकी आमद रोकने और उन्हें निकाल बाहर करने को लेकर गंभीर हैं। दुर्भाग्य से अपने देश में घुसपैठिए केवल चुनावी मुद्दे तक सीमित हैं।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आत्मशुद्धि का उपाय

ब्रह्मांड में जितने भी उपक्रम हो रहे हैं उनमें हमारा अंशदान अत्यंत सीमित या फिर नगण्य है। संसार हमारे आने से पहले भी चलता था, हमारे चले जाने के उपरांत भी चलता रहेगा। संसार का भला करने की इच्छा मन में आए तो सर्वप्रथम परोपकार करने का अहं भाव त्यागना होगा। वास्तव में वह पर-उपकार है ही नहीं, अपितु हम स्वयं पर ही उपकार कर रहे हैं। यदि ईश्वर को किसी का भला करना है तो वह किसी को भी निमित्त बना सकते हैं। यदि ईश्वर ने हमें निमित्त बना लिया तो समझना चाहिए कि यह हमारा सौभाग्य है।

हमें इस बात के लिए ईश्वर का कृतज्ञ होना चाहिए कि उसने करुणा का भाव हृदय में संचारित किया, जिससे परोपकार की भावना उपजी और इस प्रकार पवित्र होने का अवसर मिला। यह समझना कि संसार को हमारी सहायता की आवश्यकता है, यह घोर इंसानिंद है। देखा जाए तो ईश्वर को हमारी नहीं, हमें ईश्वर की आवश्यकता है। परोपकार का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे चित्तशुद्धि होती है, जो आध्यात्मिकता के लिए परम आवश्यक है। इसलिए ईश्वर का कार्य करने का जो भी अवसर मिले उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। उसमें अहं भाव कतापि न आने पाए। जिस प्रकार हमें लगता है कि हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ वह हमारा पुरुषार्थ या भाग्य था, उसी प्रकार यदि हम किसी दान या धन या मदद के वाहक बन पा रहे हैं तो वह भी किसी का भाग्य था। इसमें हमारी भूमिका ही क्या है। समुद्र को एक लोटा जल अर्पित करके हम समुद्र को कितना समृद्ध कर सकते हैं? अग्नि को यह वरदान प्राप्त है कि वह किसी भी शुद्ध-अशुद्ध वस्तु को जलाए, वह स्वयं पवित्र बनी रहेगी। उसी प्रकार जब स्वार्थ को त्यागकर देह को परमार्थ में उत्सर्ग करने का हवन ठान लिया जाता है, तो विदेह की उच्चावस्था प्राप्त होती है। अतः जो कुछ संसार से मिला, उसे संसार को ही अर्पित कर देना श्रेयस्कर है।

दिर्बकल तोमर सिंह

कार्बन उत्सर्जन का बढ़ना चिंताजनक

सुधीर कुमार

कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना जरूरी है

विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट बताती है कि वायुमंडल में कार्बन डाईआक्साइड का सैकिंग कम होने के बजाय तेजी से बढ़ता जा रहा है। 2023 में वातावरण में ग्रीनहाउस गैस की मात्रा रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई, जिसे 420 पार्ट्स प्रति मिलियन (पीपीएम) दर्ज किया गया है। पिछले दो दशक में यह अभिवृद्धि 11.4 प्रतिशत तक हुई है। वातावरण में जमा होती ग्रीनहाउस गैसों की मोटी परत वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी का खतरा का खतरा पैदा कर रहा है। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए त्वरित कदम उठाने की जरूरत है, अन्यथा पर्यावरण और समाज पर इसके विनाशकारी प्रभाव होंगे।

ग्रीनहाउस गैसें सूर्य से आने वाली गर्मी को अवशोषित कर वायुमंडल को गर्म बनाती हैं। पृथ्वी के औसत ताप में वृद्धि की यह प्रक्रिया न सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग, बल्कि उसके माध्यम से बाढ़, सूखा, ग्लेशियर का पिघलना, जैव विविधता की हानि, दावानल, कठोर जीवन दशाओं के लिए उत्तरदायी है। कार्बन डाईआक्साइड, मीथेन और नाइट्रस आक्साइड तीन ऐसी ग्रीनहाउस गैसें हैं, जो जलवायु परिवर्तन के जैविक पदार्थों के अपघटन और पराली जलाने से ग्रीनहाउस गैसों का सैकिंग बढ़ जाता है। भूमि पर बिखरे अपशिष्ट भी इसके लिए कसूरवार हैं।

कार्बन उत्सर्जन की तुलना में अवशोषण की धीमी गति जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देती है। इसे संतुलित करने के लिए अनेक देशों ने 'नेट जीरो' हासिल करने लक्ष्य निर्धारित किया है। कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा, सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल पर जोर देना तथा महासागर और वन जैसी प्राकृतिक कार्बन अवशोषक तंत्रों को स्वस्थ रखना जरूरी है।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

राष्ट्रवाद पर जनता की मुहर

'कमला हैरिस की हार से सबक ले कांग्रेस' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में ए. सूर्यप्रकाश ने कांग्रेस और अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी की हार में समानता का बहुत ही तार्किक विश्लेषण किया है। कांग्रेस और डेमोक्रेटिक पार्टियों निहित राजनीतिक स्वार्थों के चलते व्यापक राष्ट्रीय हितों की अनदेखी में लगी रहीं। यह किसी से छिपा नहीं रहा कि चुनाव जीतने के लिए दोनों ही दलों ने झूठे नैरेटिव का भी सहारा लिया। जिन वामपंथी विचारों को पूरी दुनिया ने खारिज कर दिया ये दल अभी तक उस दर्रे से चिपके हुए हैं। दोनों देशों का जनादेश यही दर्शाता है कि अमेरिका में डेमोक्रेट कमला हैरिस और भारत में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जनता की नब्ज पकड़ने में असफल रहे। चुनावों ने स्पष्ट कर दिया कि देश का आम जनमानस राष्ट्रभक्त होता है। आज भारत और अमेरिका दोनों आतंकवाद, कट्टरपंथ और अवैध घुसपैठ जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अतः ऐसे कृत्यों का समर्थन कर आम जनता का वोट कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भारत तथा अमेरिका दोनों ही देशों की जनता ने राष्ट्रवाद को प्राथमिकता देकर उसे समर्थन देने वालों को चुना।

विपिन गेयल, हापुड़

कांग्रेस को नसीहत

'कमला हैरिस की हार से सबक ले कांग्रेस' शीर्षक आलेख में ए. सूर्यप्रकाश ने कांग्रेस को नसीहत दी है कि वह वामपंथी विचारधारा का त्याग कर राष्ट्र एवं जनता के हित में कार्य करे तभी वह पुनः सत्ता तक पहुंच सकती है। अब पूरी दुनिया में वामपंथी विचारधारा नकारा साबित हो रही है। दरअसल अमेरिका में संरक्ष राष्ट्रपति के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत वहां की जनता की जीत है, क्योंकि अमेरिकी मतदाताओं की विचारधारा ट्रंप की विचारधारा से मिलती-जुलती है। चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की मुख्य प्रतिद्वंद्वी कमला हैरिस उसी पटकथा को पढ़कर आगे बढ़ रही थीं जिस तरह भारत के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस भाजपा के विरोध में झूठ की राजनीति की पटकथा लिखी थी। झूठ की राजनीति अस्थिर एवं मतदाताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने वाली होती है। कमला हैरिस ने झूठ की राजनीति का सहारा लेकर पूरे अमेरिकियों में डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में चुनाव प्रचार किया जैसा कि भारत में कांग्रेस करती है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने राष्ट्र हित के मुद्दों को बेहतर तरीके से उठाया। उन्होंने अपने बारे में जायज-नाजायज हर तरह की बातें खुलकर मतदाताओं के सामने रखा। जैसा की भारत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चुनावी सभाओं में करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपनी महिला विरोधी छवि को सुधारने में जुटे हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के चीफ आफ स्टाफ के लिए अपने अभियान की प्रमुख हस्तियों में से एक सूसी विल्स को चुना। यह पहला मौका है जब कोई महिला व्हाइट हाउस के इस शक्तिशाली और प्रभावशाली पद पर काबिज होगी। वहीं ट्रंप ने सोमवार को एलिस स्टेफनिक को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का पक्ष रखने के लिए चुना है। 40 साल की स्टेफनिक न्यूयार्क की प्रतिनिधि हैं। वह डोनाल्ड ट्रंप की मजबूत सहयोगी हैं।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

व्यापार जगत का महत्व

आज देश में करोड़ों की संख्या में जो हमारे नौजवान दिग्भ्रमित होकर बेरोजगारी की स्थिति में पहुंच गए हैं, उसका निश्चित और सर्वमान्य हल व्यापार ही है। सार्वजनिक या सरकारी नौकरियों में एक सीमित संख्या में ही अवसर होते हैं जिससे इस समस्या का समाधान कभी नहीं होगा। वास्तव में व्यापार जगत के माध्यम से शोषित, वंचित और पिछड़े लोगों को निष्पक्ष एवं समान अवसर भी दिलाया जा सकता है। आज भारत के लोगों को टाटा, बिड़ला, अदानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों से प्रेरित होना जरूरी है। साथ ही हमें नियामक एजेंसियां जैसी की आयकर, सीबीआइ और ईडी जैसी निष्पक्ष, संवैधानिक संस्थाओं के दायरे में रहना भी होगा, लेकिन राजनीतिक दलों को यह रखना चाहिए कि देश के उद्योगपतियों को लांछित कर व्यापार जगत को पुष्पित और पल्लवित नहीं किया जा सकता।

सैपूर्णानंद वर्मा, हेतिमपुर, देवरिया

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
बी- 210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा ए-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

कल्पमेधा

सत्य का सबसे बड़ा मित्र समय है। उसका सबसे बड़ा शत्रु पूर्वाग्रह है। और उसका स्थायी साथी विनम्रता है।

- चार्ल्स कैलब कार्लटन

नशे की उम्र

आम राय यही है कि नाबालिगों को शराब की लत से दूर रखा जाना चाहिए। इस क्रम में देश भर में शराब खरीदने के लिए न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई है, हालांकि किसी राज्य में इसके लिए पच्चीस वर्ष की उम्र निर्धारित है, तो किसी राज्य में इक्कीस। कम से कम अठारह वर्ष की सीमा हर जगह तय की गई है कि इससे कम उम्र के बच्चों को शराब नहीं बेची जाएगी। मगर हालत यह है कि कई बार इससे भी कम आयु के बच्चे शराब खरीदते दिख जाते हैं। शराब की दुकानों पर शायद ही कहीं इस बात की व्यवस्था होती है कि शराब खरीदने वाले की उम्र जांची जाए। इसी मसले पर एक स्वयंसेवी संगठन की याचिका में उठाए गए सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें शराब की दुकानों और अन्य विक्रय स्थलों पर उम्र की जांच के लिए एक प्रभावी नियमावली और एक सुदृढ़ नीति बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है।

दरअसल, शराब की बिक्री और उसका सेवन करने को लेकर नियम-कायदे तो बना दिए गए हैं, मगर उस पर अमल को लेकर गंभीरता शायद ही कहीं दिखती है। इतना तय है कि अगर शराब पीने की न्यूनतम आयु का निर्धारण किया गया है तो इसके पीछे यह धारणा काम करती है कि इससे कम उम्र में शराब के सेवन से सेहत को नुकसान पहुंचेगा। इस तरह की शर्तों के पीछे मुख्य भावना यह है कि बच्चों को शराब के दायरे से दूर रखा जाए। विचित्र है कि इस पर अमल के लिए किसी तरह की नियमावली और नीति तय नहीं की गई है कि अगर दुकान पर कोई व्यक्ति शराब खरीदने गया है तो उसकी उम्र की जांच हो। नतीजतन, दुकानदारों को सिर्फ बेचने से मतलब होता है और शराब के शौकीन या लती बेहिचक खरीदते हैं, वे निर्धारित उम्र की शर्त पालन करते हों या नहीं। एक तरफ यह बच्चों या किशोरों में शराब की लत को बढ़ावा देता है या इसकी अनदेखी करता है, दूसरी ओर इस तरह सरेआम इससे संबंधित कानून को भी धता बताया जाता है।

इसीलिए याचिका में सुझाव दिया गया है कि शराब बेचने वाले सभी स्थानों पर ऐसे लोगों की उम्र की जांच करने की व्यवस्था की जानी चाहिए जो तीस वर्ष से कम उम्र के लग रहे हों। इसके लिए सरकार की ओर से जारी आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड या अन्य पहचान प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा, पार्टी में बच्चों को शराब मुहैया कराने वाले आयोजकों की जिम्मेदारी तय करने और जुर्माना लगाने की भी सलाह दी गई है। विडंबना यह है कि चूंकि शराब की बिक्री सरकारों के लिए राजस्व का एक बड़ा जरिया है, इसलिए वे इससे संबंधित कई नियम-कायदों की अनदेखी करती हैं। कई जगहों पर राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे शराब की दुकानों की शृंखला जैसी दिखती है। यहां तक कि मांग के आधार पर शराब घर तक पहुंचाए जाने का चलन बढ़ रहा है। आसान तरीके से शराब मिल जाना नई पीढ़ी के लिए उसकी ओर आकर्षित होने का एक बड़ा कारण है। सेहत पर असर और सड़क हादसों में इसकी भूमिका की वजह से पहले भी शराब के सेवन को नियंत्रित करने की बात कही जाती रही है। जरूरत इस बात की है कि सरकार इससे संबंधित एक स्पष्ट नीति और नियमावली तैयार कर उस पर अमल सुनिश्चित करे।

पारदर्शिता का सवाल

प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता मानो संदिग्ध होती जा रही है। अक्सर पर्चाफोड़ की घटनाएं उजागर हो जाती हैं। इसके चलते परीक्षाएं निरस्त करनी पड़ती हैं। परीक्षार्थियों का सारा श्रम बेकार जाता है। दुबारा परीक्षाएं आयोजित कराने में सरकारों का दम फूलने लगता है। जहां परीक्षाएं बिना पर्चाफोड़ के संपन्न हो भी जाती हैं, उनमें उत्तर पुस्तिकाओं में हेराफेरी कर चहेते लोगों को नियुक्त कर देने के आरोप लगने लगते हैं। ऐसे में प्रयागराज में छात्रों के आक्रोश को समझा जा सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा दो पालियों में कराने के फैसले से छात्र नाराज हैं। हालांकि आयोग लगातार आश्वासन दे रहा है कि उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, मगर छात्रों का उस पर भरोसा नहीं बन पा रहा है। उनका तर्क है कि अगर पहली पाली में प्रश्नपत्र सरल आया और दूसरी पाली में कठिन आ गया, तो इससे दूसरी पाली के अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। मगर आयोग इसके लिए मानकीकरण की व्यवस्था को व्यावहारिक बता रहा है। यह बात किसी के गले नहीं उतर रही कि आखिर राज्य लोकसेवा आयोग करीब सात लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा एक पाली में करा पाने में असमर्थ क्यों है।

दरअसल, ताजा आक्रोश पारदर्शिता न होने की वजह से है। पिछले सात वर्षों में करीब सत्तर परीक्षाओं में पर्चाफोड़ की शिकायतें आ चुकी हैं। पिछले वर्ष हुई राज्य सेवा आयोग की परीक्षा भी पर्चाफोड़ के चलते रद्द करनी पड़ी, जो अब तक नहीं कराई जा सकी है। अपराध मिटाने और सुशासन का दम भरने वाली उत्तर प्रदेश सरकार अब तक प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता नहीं ला पाई है। इससे लाखों युवाओं के सपनों पर पानी फिर जाता है। सवाल यह भी उठता रहा है कि लोकसेवा की परीक्षाओं में गणित और विज्ञान जैसे विषयों में विद्यार्थी अधिक अंक अर्जित कर अच्छे पद प्राप्त कर लेते हैं, जबकि मानविकी विषयों के छात्र पिछड़ जाते हैं। ऐसे में दो पालियों में परीक्षा करा कर मानकीकरण के जरिए न्याय का तर्क भला छात्रों के गले कैसे उतरेगा। जिन परिस्थितियों में छात्र मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं, अगर सरकार को उसकी फिक्र होती, तो परीक्षा प्रणाली में ऐसे प्रयोगों से परहेज करती।

बिगड़ता पारिस्थितिकी तंत्र, बढ़ता संकट

बीती आधी सदी में वन्यजीव आबादी का औसत आकार तिहत्तर फीसद तक घट गया है। वैसे तो समूची दुनिया ही वन्यजीवन की कमी से प्रभावित हो रही है, लेकिन कुछ हिस्सों पर गंभीर असर देखा गया है।

जयप्रकाश त्रिपाठी

प्रकृति के उद्भव के साढ़े तीन अरब साल का ज्ञान जैव विविधता में संचित है। इस जैविक पूंजी का लगातार कम होना पूरी मानवता के लिए खतरा है, क्योंकि अगर यह एक बार खत्म हुई, तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। विश्व के पचास से अधिक शीर्ष विशेषज्ञों के एक समूह ने चेतावनी दी है कि इस समय जैव विविधता और कई वन्य-समुद्री प्रजातियों के विलुप्त होने के जिस संकट से दुनिया गुजर रही है, उससे निपटने के लिए प्रकृति संरक्षण के उपाय अभी अपर्याप्त हैं। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र का, जलवायु परिवर्तन पर विज्ञान सलाहकार समूह भी इसी तरह की चेतावनी जारी कर चुका है। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का समूह चाहता है, इसकी शुरुआत खाद्य उत्पादन और प्रकृति के दोहन के तौर-तरीकों में बदलाव के साथ हो।

धरती पर पाई जाने वाली तमाम प्रजातियां मानव जीवन के लिए अपरिहार्य हैं। इस जैव विविधता पर ही टिका है, साफ पानी, ईंधन, दवा, आवासीय सृजन की सामग्री, स्वास्थ्य, पोषण, खाना, कपड़ा और पूरे रहन-सहन का दारोमदार। दो तिहाई से ज्यादा फसलें परागण के लिए कीटों पर निर्भर हैं। जैव विविधता के बिना फसलों का परागण संभव नहीं है। आज स्थिति यह है कि इन कीटों की लगभग एक तिहाई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। चिकित्सा वैज्ञानिकों का भी मानना है कि जैव विविधता खत्म होने से चिकित्सा क्षेत्र में भूचाल आ सकता है, क्योंकि ज्यादातर दवाओं की प्रमुख स्रोत प्राकृतिक संपदा है। कैंसर के उपचार की सत्तर फीसद दवाएं प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं।

मानव संस्कृति जैव विविधता का हिस्सा है। दिखने वालों से लेकर सूक्ष्मतर जीव, पेड़-पौधे और फंगी आदि अपने तमाम रूपों में फैले विविध जीवन का विस्तार जैव विविधता है। अगर किसी भी जीव की आबादी अपनी स्वाभाविक मौजूदगी की तुलना में काफी गिर जाती है, तो खाद्य शृंखला पर उसका असर पड़ता है। यह प्रजाति अपने प्राकृतिक दायित्व पूरे नहीं कर पाती है। बीती आधी सदी में वन्यजीव आबादी का औसत आकार तिहत्तर फीसद तक घट गया है। वैसे तो समूची दुनिया ही वन्यजीवन की कमी से प्रभावित हो रही है, लेकिन कुछ हिस्सों पर गंभीर असर देखा गया है। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में सबसे ज्यादा 95 फीसद तक की गिरावट आई है। अफ्रीका में यह कमी 76 फीसद, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 60 फीसद है। कुदरती परिवेश का लुप्त होना, प्रकृति को हो रहे व्यापक नुकसान में सबसे ज्यादा चिंताजनक है। खाद्य व्यवस्था को इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है।

पारिस्थितिकीय गुणवत्ता मापने की मेडक, तितली, गौरैया, मधुमक्खी, उल्लू और मूंगे की चट्टानें आदि कई एक संकेतक हैं। इनसे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की सेहत का पता चलता रहता है। ये संकेतक बता रहे हैं कि प्रकृति अत्यंत चिंताजनक रफ्तार से सिकुड़ती जा रही है। मूंगे की चट्टानें खत्म होने से मछलियां नष्ट हो जाएंगी। भोजन और रोजगार के लिए मछलियों पर निर्भर करोड़ों लोग प्रभावित हो सकते हैं। खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। बर्फीली परतों के पिघलने से

समुद्र का स्तर तो कई मीटर बढ़ेगा ही, कार्बन और मीथेन का अकूत उत्सर्जन हो सकता है। समुद्री बर्फ में तेजी से बदलाव, जलवायु परिवर्तन और खाद्य पदार्थों की कमी से बीते तीन दशक में पेंगुइन की आबादी 61 फीसद तक घट गई है।

> **आज जैव विविधता संरक्षण नियमों और कानूनों को कठोर बनाना बहुत जरूरी है। जैव-विविधता बचाने के लिए, एक अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2030 तक हर वर्ष कम से कम 824 अरब डालर खर्च करना जरूरी हो गया है, जिसके लिए दुनिया अमीर देशों का मुंह ताक रही है। हालांकि भारत में कुल वन क्षेत्र में लगभग एक फीसद की वृद्धि बताई जा रही है, लेकिन कई जगह जंगल उजाड़े जा रहे हैं। विकास के नाम पर प्रकृति के लगातार दोहन, तेज औद्योगिकी और शहरीकरण के कारण देश के वनक्षेत्रों में गिरावट आ रही है।**

यह भी उल्लेखनीय है कि लगभग तीस करोड़ लोग जंगलों में रहते हैं और करीब 1.6 अरब लोगों की आजीविका का सहारा भी जंगल हैं। इंसानों के साथ-साथ धरती पर जैव विविधता में वनों का अस्सी फीसद से अधिक योगदान होता है। करीब अस्सी फीसद उभयचर और पचहत्तर फीसद पक्षी इन पर आश्रित हैं। पृथ्वी पर मौजूद आधे से ज्यादा कशेरुकी जीव जंगलों से ही पलते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जब काटे जाते हैं, तो हर दिन लगभग सौ प्रजातियों के विलुप्त होने का जोखिम मंडराने लगता है। इस तरह इंसानों के अस्तित्व के लिए जैव विविधता बुनियादी जरूरत है।

तापमान नियंत्रण के लिए जंगलों को बचाना जरूरी है। कभी पृथ्वी की पचास फीसद से अधिक जमीन घने जंगलों से आच्छादित होती थी। बीती एक शताब्दी से इस कटाई में नाटकीय तेजी आई है। जैव विविधता को इतना ज्यादा नुकसान पहले कभी नहीं हुआ। वैज्ञानिक आगाह कर रहे हैं कि अगर जंगल इसी तरह सिकुड़ते रहे, तो यह पृथ्वी इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगी। औद्योगिक देशों में इस दिशा में बहुत ही कम प्रभावी कदम उठाए गए हैं। लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाना है, इस बारे में भी काफी अस्पष्टता है।

जलवायु आपदा और जैव विविधता पर खतरा, एक-दूसरे से जुड़े हैं। जलवायु आपदा से उत्पन्न हालात के कारण भी कई प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर हैं। जंगल काटे जा रहे हैं, नदी किनारे की गीली जमीन खाली हो रही है। यह न सिर्फ प्रजातियों के लिए खतरा है, कार्बन सोखने की उनकी शक्ति भी समाप्त हो रही है। वैज्ञानिक लगातार आगाह कर रहे हैं कि वर्ष 2030 तक जमीन और समुद्री क्षेत्र के तीस फीसद हिस्से को संरक्षित किया जाना जरूरी है, लेकिन अभी तक संरक्षण शब्द ही पूरी तरह रेखांकित नहीं। इसी से जुड़ा वित्तीय संरक्षण भी एक अहम मसला है। अमीर देशों में औद्योगीकरण के कारण प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र बहुत कम बचा है, जबकि गरीब देशों में अभी भी काफी जैव विविधता शेष है। गरीब देशों की मांग है कि इनके बेहतर संरक्षण के लिए अमीर देश वित्तीय सहायता को 160 अरब डालर से बढ़ा कर 700 अरब डालर करें।

'फारेस्ट सर्वे आफ इंडिया' की एक रपट बताती है, भारत में 721 वर्ग किलोमीटर जंगलों की वृद्धि हुई है। इसका अर्थ है कि इस दौरान वृक्ष आवरण में कोई भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये आंकड़े कितने विश्वसनीय हैं, यह बात अब भी सवालों में है। बीते चालीस वर्षों में देश के जंगलों की 9.9 लाख हेक्टेयर जमीन गैर-वनीय कार्यों में उपयोग की गई है। बीते डेढ़ दशक में वनों की लगभग 60 हजार हेक्टेयर जमीन कोयला और खनिज खनन के लिए, 45 हजार हेक्टेयर जमीन सड़क के लिए, 36 हजार हेक्टेयर जमीन सिंचाई परियोजनाओं और 26 हजार हेक्टेयर जमीन ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए दी गई। इस तरह जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा इतर कार्यों में इस्तेमाल किया गया है।

आज जैव विविधता संरक्षण नियमों और कानूनों को कठोर बनाना बहुत जरूरी है। जैव-विविधता बचाने के लिए, एक अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2030 तक हर वर्ष कम से कम 824 अरब डालर खर्च करना जरूरी हो गया है, जिसके लिए दुनिया अमीर देशों का मुंह ताक रही है। हालांकि भारत में कुल वन क्षेत्र में लगभग एक फीसद की वृद्धि बताई जा रही है, लेकिन कई जगह जंगल उजाड़े जा रहे हैं। विकास के नाम पर प्रकृति के लगातार दोहन, तेज औद्योगिकी और शहरीकरण के कारण देश के वनक्षेत्रों में गिरावट आ रही है।

दर्द न जाने कोय

चैतन्य नागर

प्रेम पाने और देने की क्षमता का खत्म हो जाना एक बड़ी मानवीय त्रासदी है, पर इससे भी बड़ी त्रासदी है लोभ के सहारे और भय दिखाकर प्रेम बटोरने की कोशिश, या फिर प्रेम की जगह सम्मान पाने की कोशिश। इस कोशिश में लगे लोग आखिरकार बड़े मायूस, लाचार और उग्र भी हो जाते हैं। प्रेम पाने के ये रास्ते बहुत दूर तक ले ही नहीं जाते। बेहतर यही है कि विनम्रता के साथ घटते हुए प्रेम को देखा जाए, इसे स्वीकार किया जाए, उसके कारणों की पड़ताल की जाए। उसकी जगह ऐसा कुछ न रखा जाए जो प्रेम है ही नहीं। प्रेम का कोई विकल्प नहीं।

जिसे हम प्रेम कहते हैं, उसमें अनगिनत पेचीदगियां हैं। प्रेम पाने, प्रेम व्यक्त करने, बांटने की तलब सभी के मन में कुलबुलाती है। यह चाहत बड़ी स्वाभाविक और कुदरती है। कई तरह की विरोधाभासी भावनाओं के गलियारों में टहलते मन में भी प्रेम की ख्वाहिश कहीं न कहीं रेंगती रहती है। बच्चों में भी मां-बाप और अपने हमउम्र बच्चों के साथ रहने, उनके सान्निध्य में रहने की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। आशिक और माशूका में तो विसाले-यार की चाहत होती ही है। हर देश का साहित्य प्रेम कविताओं से लबालब भरा पड़ा है। यह भौतिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और आत्मिक, हर स्तर पर महसूस होने वाली भावना है, जो हमारी समूची मनोदैहिक संरचना को प्रभावित करती है। कुछ लोग एकतरफा प्रेम की आग में भी जलते हैं और दोपहर की धूप में माशूका को नंगे पांव देख कर ही खुश हो जाते हैं। किसी जमाने में बस इतना ही काफी हुआ करता था।

प्रेम के बारे में एक और खास बात यह है कि इसमें सिर्फ आनंद की अवस्था नहीं बनी रहती। जल्दी ही यह एक लत सरीखा बन जाता है। पहले और अधिक सुख पाने की कामना और फिर उसके न मिलने पर दुख, गुस्सा और ईर्ष्या पैदा होती है और आखिर में कुंठा, क्रोध, हिंसा और प्रतिशोध का भाव आता है। कई बार दोनों लोग बच जाते हैं और प्रेम वहां से खिसक लेता है। प्रेम भी एक किस्म के विरह या अलगाव से ही शुरू होता है। विभाजन, अलगाव, दूरी, करीब जाने की तड़प का भाव जितना गहरा होगा, उतनी ही तीव्रता से 'प्रेम' का अनुभव होगा।

एक और बात गौरतलब है कि बेहतरीन प्रेम कविताएं प्रेम के दौरान नहीं, प्रेम की स्मृति में या उसकी कल्पना में लिखी गई हैं। प्रेम करना, उसे जीना एक पूर्णकालिक कार्य है। उसके बारे में लिखना तो बस स्मृति पर पड़ी उसकी खरोंचों को जीना है। प्यार पर बुद्धिजीवियों को बहस करते हुए नहीं देखा जाता। दरअसल, अधिक बौद्धिकता इंसान को एक ठूंठ में बदल देती है। प्रेम फिर उसे अ-बौद्धिक लगने लगता है। अकबर इलाहाबादी कहते हैं- 'इश्क नाजुकमिजाज है बेहद, अक्ल का बोझ उठा नहीं सकता'। शारीरिक तौर पर दिमाग से दिल की भौतिक दूरी सिर्फ अठारह इंच के करीब होती है, पर उसे पूरा करने में अक्सर जिंदगी बीत जाया करती है। प्रेम क्या है, यह अंतिम तौर पर बताना बड़ा मुश्किल है। 'इब्तिदा में ही रह गए सब यार, इश्क की कौन इंतिहा लाया', मीर ने बड़ी नफासत से यह बात कह दी है।

प्रेम की शुरुआत में तो लोग बड़े सतर्क रहते हैं, जैसे शीशे के टुकड़ों से भरे फर्श पर चल रहे हों। पर समय प्यार का बड़ा दुश्मन होता है। बाद में जिसका पसीना भी गुलाब हुआ करता था, वह बस कोने में पड़ी बासी समोसे की प्लेट बनकर रह जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने प्रिय पर अधिकार जमाने लगते हैं। देरों अपेक्षाएं होती हैं उससे। हम यह मानकर चलते हैं कि वह जैसा कल था वैसा आज भी है और कल भी रहेगा। पर किसी जीते-जागते इंसान को कब्जे में रखना नामुमकिन है। हमारा सामाजिक ढांचा और संस्थाएं इसी नामुमकिन को मुमकिन बनाने की उम्मीद पर टिके हैं। विवाह की संस्था में पाखंड के मवेशी निर्भीक होकर चरते हैं। ज्यादातर प्रेम संबंध भ्रामक छवियों के बीच के रिश्ते बनकर रह जाते हैं। प्यार को कोई भी सामाजिक, कानूनी कमीज फिट नहीं बैठती, पर मन यह मान नहीं पाता कि जो आपसे कल प्यार करता था वह अब नहीं करेगा। दरअसल प्यार एक अजनबी, अनाम परिंदे की तरह आता है और उड़ जाता है। फिर कभी भूला-भटका हमारी मुंडेर पर आकर बैठता है।

प्रेम और ईर्ष्या के संबंधों पर गौर किया जाना चाहिए। जब कोई हमारे प्रिय को हसरत से देख भी ले, तो जलन होती है। इसे किसी धर्म, दर्शन और साहित्य का ज्ञान खत्म नहीं कर सकता। पहली मुलाकात का टेडीबेयर एक कटखने चौपाये की तरह नोचने-खसोटने लगता है। क्या प्यार की कठोर शर्तें होती हैं? जैसे ही लिखित या अलिखित समझौता टूटता है, भीतर का घायल, ईर्ष्या में जलता 'आथेलो' चिंघाड़ने लगता है। इसी को गालिब ने आग का दरिया कहा होगा! इसमें डूबकर फिर बाहर निकलना प्यार की चुनौती है।

जो भी हो, यह तो सच है कि प्रेम का अभाव जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है और इसकी सुरभि के बगैर जीवन निरर्थक है। इसे बुद्धि से समझने की ज्यादा जरूरत नहीं, अपनी देह में, मांस-मज्जा में महसूस करने की दरकार है। अकबर इलाहाबादी लिखते हैं: 'बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है, तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता'। प्रेम के बारे में शायद यही कहा जा सकता है। प्रेम जितना भी मिल जाए, मन नहीं भरता।

दुनिया मेरे आगे

> **बेहतरीन प्रेम कविताएं प्रेम के दौरान नहीं, प्रेम की स्मृति में या उसकी कल्पना में लिखी गई हैं। प्रेम करना, उसे जीना एक पूर्णकालिक कार्य है। उसके बारे में लिखना तो बस स्मृति पर पड़ी उसकी खरोंचों को जीना है। प्यार पर बुद्धिजीवियों को बहस करते हुए नहीं देखा जाता।**

बदलाव से उम्मीद

डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद राजनीतिक विश्लेषक अमेरिका में और अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर व्यापक बदलाव की संभावना देख रहे हैं। वहीं अब अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को देखना है कि बड़े-बड़े चुनावी वादे पूरे होते हैं कि नहीं। माना जा रहा है कि दूसरे कार्यकाल में ट्रंप पर दबाव कम होगा। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने कहा था कि वे अपने खेल में शीर्ष पर हैं, चाहे आप उन्हें पसंद करें या न करें। व्यावसायिक हेराफेरी और कुछ दूसरे मामलों में दोषी पाए जाने के बावजूद अमेरिका में राष्ट्रपति के पद पर बैठने वाले वे पहले व्यक्ति बन जाएंगे। दूसरी ओर नाटो से जुड़े यूरोपीय देशों में भी ट्रंप की नीतियों को लेकर अनिश्चितता है। यूक्रेन युद्ध में नाटो अमेरिका के साथ मिल कर लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है, हालांकि आने वाले समय में इस मुद्दे पर अमेरिका का क्या रुख होगा, इसे लेकर असमंजस है। नाटो का मानना है कि ट्रंप का शासन कठिन होने वाला है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। वे कम से कम नई ऊर्जा जरूर डालेंगे। ट्रंप के पहले दौर में यूरोप में कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। कई ऐसे देश हैं, जिस पर ट्रंप का काफी असर है।

- युगल किशोर राही, छपरा

सैनिक को सम्मान

विडंबना है कि देश की सुरक्षा करने वाले सैनिकों के शहीद होने पर अक्सर उनके परिवार को सरकारी सहायता और अन्य मदद के लिए वर्षों तक दर-दर भटकना पड़ता है। यह सचमुच दुखद है। यहां तक कि उस शहीद जवान की शहीद का दर्जा भी आसानी से नहीं मिलता है। हमारे देश के सरकारी तंत्र की यह अजीब विडंबना है। सवाल है कि संबंधित जवान के परिवार को उसका हक सहजता से और जल्दी क्यों नहीं दिया जाता। जिस सैनिक ने देश के लिए अपना प्राण न्योछावर कर दिया हो और उसका परिवार परेशान हो, भटकता फिरे, यह तो उस शहीद का एक तरह से अपमान है। इस दिशा में सरकारी तंत्र को प्रयास करना चाहिए और उसे आगे रह कर स्वतः ही आवश्यक कार्रवाई करते हुए शहीद के परिवार को जल्द से जल्द वह सब सहायता देना चाहिए जो नियम के मुताबिक निर्धारित है। आखिर शहीदों के परिवार दर-दर क्यों भटके?

- आशीष सकलेचा, रतलाम

युवाओं की उपेक्षा

राजनीति में जब तक युवाओं की भागीदारी अधिक नहीं होगी, तब तक भारत का विश्वगुरु बनने का सपना साकार नहीं हो सकता। जब चुनाव की बात आती है, तो युवाओं को अक्सर इनसे दूर रखने की कोशिश की जाती है। राजनीति केवल वरिष्ठ नेताओं तक सीमित होकर रह गई है। विडंबना है कि हमारा समाज ही युवाओं को राजनीति से दूर रखता रहा है। यहां तक कि अगर कोई युवा राजनीति में कदम रखने की सोच भी लेता है, तो कथित बुद्धिजीवी उसके पीछे पड़ जाते हैं। विधानसभा और लोकसभा में आज भी युवाओं की भागीदारी सीमित है। कुछ युवा किसी पार्टी के सहारे विधानसभा और संसद तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं, तो उन्हें मंत्री पदों से दूर रखा जाता है। जो युवा निर्वाचित जीतते हैं, उन्हें तरह-तरह के प्रपंचों में फंसाने की कोशिश की जाती है, जिसका आलम यह होता है कि उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता पक्ष की विचारधारा का दामन थामना पड़ता है, जिससे उनकी राजनीतिक मौलिकता नष्ट हो जाती है।

- अर्जुन प्रताप सिंह, जोधपुर

आयकर का बोझ

भारत में कई तरह के कर नागरिकों से वसूले जाते हैं, जिनमें सेवा कर, आयकर और संपत्ति कर प्रमुख हैं। सरकार को सबसे ज्यादा आय प्रत्यक्ष करों से मिलती है। सरकार के राजस्व के दो प्रमुख स्रोत जीएसटी और आयकर हैं, जो कुल राजस्व का करीब 90 फीसद हिस्सा हैं। भारत में कर्मचारियों की पेंशन को भी आयकर योग्य माना गया है जो उचित नहीं है। पेंशन, कर्मचारियों की आय नहीं, वरन जीवन निर्वाह भत्ता है। नीदरलैंड, जर्मनी और मलेशिया में पेंशन को आय नहीं माना गया है। जबकि बरमूडा, मोनाको और यूएई ऐसे कुछ देश है, जहां व्यक्तिगत आय पर कर नहीं लगता है। भारत में केवल कृषि योग्य आय कर मुक्त है। समय की मांग है और यह न्यायोचित भी है कि सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आयकर नियमों में संशोधन कर कर्मचारियों की पेंशन को आयकर से मुक्त करना चाहिए।

- नलिन खोईवाल, इंदौर

सम्पादकीय

व्यापार समझौतों का पुर्नपरीक्षण

गत सप्ताह नई दिल्ली में एक औद्योगिक संस्था के मंच से बोलते हुए सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम ने इस बात की हिमायत की कि भारत को बहुपक्षीय व्यापार समझौतों में शामिल होने पर विचार करना चाहिए। वह क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) और प्रशांत पार साझेदारी के लिए व्यापक एवं प्रगतिशील समझौते (सीपीटीपीपी) का जिक्र कर रहे थे। यह बात अतिरिक्त महत्त्व की है क्योंकि सुब्रमण्यम पहले वाणिज्य सचिव रह चुके हैं। यह उम्मीद की जा सकती है कि इस वक्तव्य का संदेश यह है कि देश आरसेप और सीपीटीपीपी जैसे बड़े व्यापारिक समझौतों के लाभ को लेकर नए सिरे से विचार कर रहा है।

सुब्रमण्यम की दलील एकदम साधारण है। ऐसे बड़े कारोबारी धड़े का हिस्सा बनना महत्त्वपूर्ण है। सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रमों के लिए तो यह खास महत्त्व रखता है जो देश के निर्यात में 40 फीसदी की हिस्सेदारी रखते हैं। उन्होंने संकेत किया कि भारत में स्थित बड़े कॉरपोरेट हाउस निर्यात के मोर्चे पर कमजोर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से यह देखा गया है कि छोटी कंपनियों का सामना जब बड़े बाजार से होता है तो उनका प्रदर्शन बेहतर रहता है। ऐसा इसलिए कि वे नए प्रकार की मांग से समायोजन को लेकर बेहतर स्थिति में होती हैं। वास्तव में ऐसा व्यापार खुलापन अक्सर जरूरी होता है ताकि उनका विकास हो और वे स्थिर कारोबारी ढांचे में प्रवेश कर सकें जहां बड़ी घरेलू कंपनियों का दबदबा है। जब घरेलू बाजार भारत जैसा बड़ा और मुनाफे वाला हो तो प्रभाव काफी बढ़ जाता है।

कंपनियां अपने बाजार तक पहुंच कम करने के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं, बजाय कि विदेशों में बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के। यह उनके निजी हित में हो सकता है लेकिन इससे व्यापक कल्याण में इजाफा नहीं होता है और न ही घरेलू मूल्यवर्धन और वृद्धि होती है। वैश्विक मूल्य श्रृंखला में शामिल होने के लिए ऐसे व्यापार समझौतों का हिस्सा बनना जरूरी हो चला है। भारतीय कंपनियों के लिए अवसरों का दायरा बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है। आरसेप और सीपीटीपीपी में प्रवेश की दो बाधाएं क्रमशः चीन और घरेलू सुधार हैं। आरसेप में कई ऐसे देश शामिल हैं जिनके साथ भारत पहले ही मुक्त व्यापार समझौता कर चुका है, इनके अलावा चीन भी इसमें शामिल है। भारतीय नीति निर्माताओं के मन में उचित ही यह भय है कि इससे भारतीय बाजार चीन के निर्यात से पट जाएंगे। परंतु नीति निर्णय के इससे भयभीत नहीं होने की दो वजह हैं। पहली, आरसेप पहले से मौजूद है और आरसेप में शामिल देशों से भारत में होने वाले आयात में बड़ी संख्या में चीनी वस्तुएं भारत आती हैं। फिर चाहे वे दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हों या कोरिया। दूसरी वजह यह है कि आरसेप के देश भी अन्य सदस्य देशों के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम हैं। हाल के वर्षों में व्यापक भूराजनीतिक विवाद के रूप में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध चीन की एकपक्षीय कार्रवाई इसका उदाहरण है। सीपीटीपीपी का प्रश्न ज्यादा जटिल हो सकता है। यह व्यापार समझौता एक 'स्वर्णिम मानक' है क्योंकि इसमें 'सीमा से परे' नियामकीय सुसंगतता बतौर सिद्धांत शामिल है। दूसरे शब्दों में यह मामला न केवल टैरिफ का है बल्कि गैर टैरिफ गतिरोधों में कमी का भी है।

पहला महाकुंभ जिसमें नेविगेशन के लिए अस्थायी टेंट सिटी गूगल मैप्स पर दिखाई देगी

महाकुंभ की महा तैयारी, संगम नगरी में जुटेंगे लगभग 45 करोड़ श्रद्धालु

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के मुताबिक 4,000 हेक्टेयर में हो रहे महाकुंभ में लगभग 40-45 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इस आयोजन का अनुमानित बजट लगभग 6,382 करोड़ रुपये है,जिसमें से 5,600 करोड़ रुपये से ज्यादा पहले ही आयोजन और संबंधित परियोजनाओं के लिए अलग रखे जा चुके हैं। सपा सरकार में 2012 में हुए कार्यक्रम बजट 1,152 करोड़ रुपये था, जिसमें लगभग 12 करोड़ लोग शामिल हुए थे।

संजुला सिंह

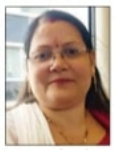

गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी के संगम तट पर 13 जनवरी 2025 में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले का आयोजन होने जा रहा है।संगम नगरी सांस्कृतिक जश्न का केंद्र बनने जा रही है। महाकुंभ पूरे 45 दिन का होगा,जो 14 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। 2012 में हुए महाकुंभ से इस बार महाकुंभ लगभग तीन गुना बड़ा होने वाला है।महाकुंभ की तैयारी जोर-शोर से चल रही हैं।योगी सरकार ने 15 से ज्यादा विभागों को तैयारी के प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी सौंपी है।तैयारी में 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पूरा करने का टारगेट रखा गया है।

महाकुंभ के लिए जोरदार तैयारी

उत्तर प्रदेश जल निगम मेला क्षेत्रों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए 1,249 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाएगा। इसके अलावा 200 वाटर एटीएम और 85 वाटर पंप लगाया जाएगा।राज्य सड़क विभाग प्रयागराज से जुड़ने वाले तमाम राजमार्गों पर 7,000 बसें चलाई जाएंगी।प्रयागराज से मेले वाली जगह तक लगभग 550 शटल बसें भी चलाई जाएंगी। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने 15 लाख वर्ग फीट में फैली सार्वजनिक दीवारों और इमारतों पर चित्र बनाने के लिए आठ अलग-अलग एजेंसियों को हायर किया है।प्रयागराज एयरपोर्ट का नवीनीकरण एक नए टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण और विमानों के पार्क होने वाले एप्रन एरिया का विस्तार करके किया जाना है। इंडियन रेलवे भी अपने स्तर पर तैयारियों में जुट गया है।ट्रेन सफर को और ज्यादा बेहतर बनाने के मकसद से एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रयागराज रेलवे डिवीजन प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर होने वाले रेलानों को कई भाषाओं मे शुरू करने जा रहा है।इससे पूरे हिंदुस्तान से आने वाले अलग-अलग भाषाओं वाले यात्रियों को अपनी मातृभाषा में ट्रेन से संबंधित जानकारी मिलेगी,जिससे उनका सफर का एक्सपीरिएंस बेहतर होगा और जानकारी समझ में आएगी।

रोजगार और टूरिज्म

करोड़ों लोगों के इस मेले में लगभग 45,000 से अधिक परिवारों को रोजगार मिलेगा।इसके अलावा इससे न केवल प्रयागराज बल्कि बनारस,अयोध्या,मथुरा और विंध्यवासिनी धाम में भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि इन स्थानों पर सुविधाओं और सुरक्षा उपायों की लगातार समीक्षा की जाए और उन्हें बेहतर बनाया जाए, जिससे राज्य को इस आयोजन से फायदा मिल सके और श्रद्धालु अच्छा एक्सपीरिएंस लेकर जा सकें।समीक्षा बैठक में सीएम ने इस बात पर जोर दिया कि महाकुंभ सूबे के लिए एक बड़ा मौका है।

श्रद्धालुओ को बेहतर सुविधाओं हेतु सर्विस प्रोवाइडर्स को ट्रेनिंग

राज्य पर्यटन विभाग मौजूदा समय में कई सर्विस प्रोवाइडर्स को ट्रेनिंग दे रहा है,जिसमें टूर गाइड,नाविक,स्ट्रीट वेंडर और ड्राइवर शामिल हैं।इनकी सेवाएं महाकुंभ के दौरान दी जाएंगी। ट्रेनिंग लखनऊ के मान्यवर कांशीराम पर्यटन प्रबंधन एजेंसी और प्रयागराज में चल रही है।यह यूपी की 2022 की पर्यटन नीति द्वारा पर्यटन को दिए गए प्रोत्साहन का हिस्सा है।नीति का उद्देश्य 10 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराना और इस क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश करना है।

लोकल मैपिंग के लिए गूगल के साथ समझौता

यह पहला महाकुंभ होगा,जिसमें नेविगेशन के लिए अस्थायी टेंट सिटी गूगल मैप्स पर दिखाई देगी।हाल ही में गूगल के प्रतिनिधियों और महाकुंभ मेला प्राधिकरण के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आज कई दिशा स्थानों को छुए रहेगी। तथा आज यह संकल्प करने है कि अपने जीवन के हर क्षेत्रों को देख है, तथा अपनी किसी कुशल होने और दूसरों तरफ, अपने चित बातों से सकारात्मक रखना पड़ेगा। तथा ने दिखे हमारे वाहन में और स्थिति हुई को सुनाइये तथा सकारात्मक ऊर्जा को सहयुक्त करेंगे, बंधित उपस्थिति लक्ष्यों में भी, जहां तक सकारात्मकता हमें संतोष और बातचीत में तथा प्रदान रहेगा

मेष
आज आपका दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। आयात निर्यात से जुड़े व्यापारियों को धंधे में लाभ और सफलता मिलेगी। आपकी खोई हुई वस्तु वापस मिलने की संभावना है। प्रवास आर्थिक लाभ और वाहन सुख की संभावना है।

वृष
कार्य सफलता और विरोधियों पर विजय का नशा आपके दिलो-दिमाग पर छाया रहेगा, इससे प्रसन्नता अनुभव करेंगे। भाई-बहनों के साथ मिलकर घर पर कोई आयोजन करेंगे। मित्रों, स्नेहीजनों के साथ चाय करने का योग है।

मिथुन
आज आप आर्थिक लाभ के साथ समाज में आदर प्राप्त कर सकेंगे। आपके परिवार में सुख और संतोष बना रहेगा। आपकी आय बढ़ेगी और व्यापार में भी लाभ होगा। प्रिय व्यक्ति के साथ सुखद समय बिताएंगे।

कर्क
आज संतान और जीवनसाथी के संबंध में चिंता होगी। वाद-विवाद या चर्चाओं में गहरे न उतरना हित में रहेगा। आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। मित्रों के लिए खर्च की संभावना है। पेट संबंधी बीमारियों से तकलीफ होगी। नौकरीपेशा वर्ग को नौकरी में लाभ होगा।

सिंह
पारिवारिक जीवन में उत्साह का वातावरण रहेगा। संतान की प्रगति से आपको संतोष का अनुभव होगा। आज आपको बेचैनी, थकान का अनुभव होगा। शरीर में ताजगी का अभाव रहेगा। इससे काम करने का उत्साह नहीं रहेगा।

कन्या
परिवार में आज आनंद का वातावरण रहेगा। वाणी की मधुरता और न्यायप्रिय व्यवहार से आप लोकप्रियता प्राप्त करेंगे। आर्थिक लाभ होने की संभावना है। स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। विद्यार्थियों के विद्याध्ययन के लिए अनुकूल समय है। बीमारी में राहत महसूस होगी।

तुला
आमोद-प्रमोद की प्रवृत्तियों में पैसे खर्च होंगे। दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ निकटता के पल व्यतीत कर सकेंगे। कोर्ट-कचहरी के मामलों में संघलकर कार्य करना उचित रहेगा। ऑफिस में स्त्री वर्ग से लाभ होने की संभावना है।

वृश्चिक
निर्धारित काम सफलता से पूरे होंगे। अधूरे काम पूरे होंगे। नन्हिहाल पक्ष से आनंददायक समाचार मिलेंगे। नौकरीपेशा वर्ग को नौकरी में लाभ होगा। ऑफिस तथा काम-काज की जगह अधिकारियों की नाराजगी का शिकार होना पड़ेगा।

धनु
शारीरिक- मानसिक अस्वस्थता का अनुभव होगा। छाती में दर्द या किसी विकार से परिवार में अशांति होगी। महिलाओं के साथ मनमुटाव और तकरार होने की संभावना है। सार्वजनिक रूप से मानहानि होने से दुख होगा।

मकर
अपनी कला को बाहर लाने के सुनहरे अवसरों को हाथ से न जाने दें। आपकी रचनात्मक और कलात्मक शक्ति अधिक निखरेगी। मनोरंजन की प्रवृत्ति में दोस्तों तथा परिजनों के साथ भाग लेंगे। समय से भोजन नहीं मिलेगा।

कुंभ
अविवाहित लोगों के विवाह के योग बनेंगे। आपको पत्नी अथवा संतान से लाभ हो सकता है। व्यापार के लिए होने वाला प्रवास लाभदायक साबित होगा। आपके उच्च अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। पदोन्नति होने की संभावना है।

मीन
सुंदर भोजन, वस्त्र और वाहन सुख की प्राप्ति होगी। प्रिय व्यक्ति की मुलाकात तथा काम में सफलता का योग है। आज आपके विदेश में बसने वाले स्नेहीजन या मित्रों से शुभ समाचार मिलने की संभावना है। दांपत्य जीवन में विशेष मधुरता रहेगी। शारीरिक, मानसिक स्वस्थता बनी रहेगी।

शख्सियत

बढ़ता राजस्थान

नमस्कार दोस्तों हमारी आज की शख्सियत कॉलम के स्टार हैं वन विभाग के शानदार व जाँबाज अधिकारी शंकर सिंह शेखावत जोकि सरिस्का बफर रेंज के रेंजर हैं। अलवर में टाईगर विलुप्त होने के बाद अलवर की बाघविहीन भूमि को बाघों की दहाड़ व दर्शन से सुशोभित करने वाले एक मात्र वन्यजीवों के संरक्षण व वन संरक्षण में अपनी अलग पहचान बनाने वाले एक मात्र अधिकारी के रूप में नजर आते हैं। कब पैदा हुए कहां हुए इनके लिए इससे अधिक ये क्या कर रहे हैं या फिर क्या किया है ये मायने रखता हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इस अधिकारी को जानता हूँ। अब चाहे वन्य जीव या वनस्पति के संरक्षण व संवर्धन की बात हो रेंजर शंकर सिंह पूर्णत्या समर्पित हैं इनके लिए। आज अलवर शहर से मात्र पाँच किलोमीटर की दूरी पर बाघ नजर आ रहे हैं ये किसी भी सूरत में वन्यजीव प्रमियों के लिए सपने से कम नहीं। अलवर के बालाकिला क्षेत्र को समाजकंटकों से बचाने व क्षेत्र में बाघों की संख्या बढ़ाए जाने व उनके विचरण के लिए सारा श्रेय इस शानदार अधिकारी को जाता है। अलवर शहर में तीन बार बघेरा आ जाने से उन्हें टूक्यूलाईज कर उनकी जान बचाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। यही नहीं जहां भी जंगली या हिंसक वन्यजीवों के टूक्यूलाईज करने का मामला आया वहां इन्हीं के द्वारा उनकी रक्षा कर उन्हें सुरक्षित वन्यक्षेत्र में छोड़ा जाता है। वन को समर्पित इस शख्श का शानदार व्यक्तित्व की इन्हें शख्सियत बनाती है। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।

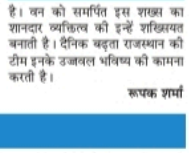

शंकर सिंह शेखावत
(रेंजर बफर जोन, सरिस्का)

रूपक शर्मा

सबरी या शबरी

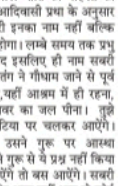

राम भक्त शबरी का जिक्र तो सभी ग्रंथों में सभी धार्मिक आयोजनों में होता है। हम उनका भजन भी शायद कहीं ना कहीं और कभी ना कभी गुनगुना भी लेते हैं 'रामा रामा रटते-रटते बीती रे कमरीया..' लेकिन क्या कभी शबरी के जीवन दर्शन को जानने का प्रयास किया है। भीतर से आवाज आऐगी,नहीं..

मेरा अपना विचार है कि इस भील जाति की महिला का नाम शबरी नहीं था इसका नाम को आदिवासी प्रथा के अनुसार बाई वगैहरा होना चाहिए था। शबरी इनका नाम नहीं बल्कि इनका गुण ही इनका नाम बन गया होगा। लम्बे समय तक प्रभु के आ जाने का सबर किया , शायद इसलिए ही नाम सबरी पड़ गया होगा। इनके गुरू ऋषि मतंग ने गौधाम जाने से पूर्व कहा कि बिटिया तू कहीं जाना मत,यहीं आश्रम में ही रहना, कंदमूल फल खाना और पम्पा सरोवर का जल पीना। तुझे खोजते हुए खुद राम यहीं तेरी कुटिया पर चलकर आऐंगे। देखिये शबरी का जीवन दर्शन उसने गुरू पर आस्था जताई,श्रृद्धा जताई,निष्ठा जताई। उसने गुरू से ये प्रश्न नहीं किया कि कब आऐंगे। गुरू ने कहा है आऐंगे तो बस आऐंगे। सबरी ने लगभग 6 दशकों तक सबर रखा कि आज नहीं आए तो कोई बात नहीं कल तो जरूर आऐंगे और दूसरे दिन पहले दिन से अधिक प्रेम,भाव-भक्ति व वात्सल्यता पैदा करती गई। उम्र के साथ शरीर साथ दे ना दे पर आत्मा और विश्वास इतना साथ दे रहा था कि ईश्वर के प्रति विश्वास ओर बढ़ता गया। हमारा बिल्कुल उल्टा है। मान लीजिए आज हमारे गुरू यदि ये कह दें,पहली बार तो कहेंगे ही नहीं फिर भी यदि गुरूजी कह दें कि तुम्हे अलवर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं भगवान खुद अलवर आऐंगे तो हमारा दुसरा प्रश्न यही होगा कि कब आऐंगे गुरूजी ? मित्रों बात थोड़ी अटपटी जरूर है पर सत्य हमेशा कड़वा ही होता है। हमें सबर नहीं है इसलिए हम कभी भी सबरी बन ही नहीं सकते। हमें तो गुरू भी हाईटेक चाहिए जो इधर तो गुरू मंत्र दे उधर दूसरे दिन से ही कुबेर रोज डायरी लेकर खड़े नजर आएं कि बताओं वत्स आज क्या-क्या आईटम चाहिए। हम सबरी जैसा सबर जीवन में नहीं कर सकते क्योंकि 80 साल भगवान के इंतजार की क्या बात कहें हम तो सिरदर्द में भी नुकसान भले ही करे लेकिन दर्दनिवारक अंग्रेजी दवा इसलिए ले लेते हैं कि आयुर्वेद दवा का असर थोड़ी देर से होता है। हमें सबर ही नहीं है, तो हम सबरी के जीवन दर्शन को ना तो समझ सकते हैं ना ही उसे जी सकते हैं।

रूपक शर्मा
दैनिक बढ़ता राजस्थान,
अलवर संस्करण

सामान्य झगड़े में हो रहे हत्या जैसे जघन्य अपराध

हत्या जैसे जघन्य अपराध को लेकर आम धारणा यही होती है कि इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। मगर पिछले कुछ समय से जिस तरह बेहद मामूली बातों पर भी लोगों में आक्रामकता देखी जाने लगी है, झगड़े होने लगे हैं और कई बार गुस्से में उपजी हिंसा का अंत किसी की हत्या तक के साथ होने लगा है, वह हैरान करता है। यह बहुत धीमी रफ्तार से विकास की कोशिश करते समाज के लिए बेहद चिंताजनक है कि जिन बातों को सामान्य बातचीत से सुलझाया जा सकता है, उसमें नाहक ही किसी की जान तक चली जाती है। कुछ दिन पहले दिल्ली के ज्वाला नगर इलाके में एक व्यक्ति ने अपने एक साथी की पत्थर से हमला कर सिर्फ इसलिए हत्या कर दी कि उसने उससे बीड़ी मांगी थी और इस पर झगड़ा हो गया। प्रथम दृष्टया ऐसी वजह से एक जघन्य अपराध के घटित होने पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। मगर हाल के वर्षों में बहुत सारे लोगों में एक विचित्र किस्म की आक्रामकता देखी जाने लगी है, जिसका कोई मजबूत आधार नहीं होता। निश्चित रूप से यह समाज में बढ़ती हताशा और उससे उपजे गुस्से का उदाहरण है, जिस पर देश और समाज के कर्तधार्ताओं को सोचने की जरूरत है। अब यह कोई छिपा तथ्य नहीं है कि अर्थव्यवस्था की चमकती तस्वीर में ये एक बड़ा तबका गायब रहता है, जो कई तरह की आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक स्तर पर चुपचाप पसरते संकटों का शिकार होता है।

विशेष आलेख

कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाती नमो ड्रोन दीदी योजना

नमो ड्रोन दीदी योजना, पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने का एक अग्रणी प्रयास है। यह पहल महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करती है, जिससे वे ड्रोन संचालित करने और स्थानीय किसानों को आवश्यक कृषि सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम हो जाती हैं। कृषि आधुनिकीकरण के साथ महिला सशक्तिकरण को जोड़कर, यह योजना सामाजिक प्रगति और आर्थिक विकास दोनों को बढ़ावा देती है। इस योजना में भाग लेने वाली महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया जाता है, जहाँ वे हवाई सर्वेक्षण, सटीक कृषि तकनीक और कीटनाशक छिड़काव सहित ड्रोन संचालन में कौशल हासिल करती हैं। ये ऑपरेशन न केवल फसल की पैदावार में सुधार करते हैं, बल्कि महिलाओं को एक स्थायी आय भी प्रदान करते हैं, लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हैं और उनकी वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ाते हैं। जैसे-जैसे ये महिलाएँ ड्रोन तकनीक को अपनाती हैं, वे बढ़ते कृषि-तकनीक क्षेत्र में सक्रिय योगदानकर्ता बन जाती हैं।

प्रियंका सौरभ

नमो ड्रोन दीदी सटीक कृषि और संसाधन अनुकूलन में योगदान दे सकती है। भारत का कृषि क्षेत्र प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों के एकीकरण के साथ परिवर्तन के शिखर पर है। ड्रोन प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करने वाली नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएँ सटीक कृषि और संसाधन अनुकूलन के माध्यम से खेती को आधुनिक बनाने की क्षमता प्रदान करती हैं, जो कृषि में प्रमुख चुनौतियों का समाधान करती हैं। ड्रोन उर्वरकों और कीटनाशकों के सटीक अनुप्रयोग को सक्षम करते हैं, अपव्यय को कम करते हैं और समान वितरण सुनिश्चित करते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन रासायनिक उपयोग में 30त्न तक की कमी सुनिश्चित करते हैं। ड्रोन फसलों की वास्तविक समय की निगरानी की अनुमति देते हैं, फसल के स्वास्थ्य, मिट्टी की स्थिति और समय पर हस्तक्षेप के लिए प्रारंभिक रोग का पता लगाने पर डेटा प्रदान करते हैं। आंध्र प्रदेश में, ड्रोन ने कीटों के हमलों का समय पर पता लगाने के कारण फसल के नुकसान को 20त्न तक कम करने में मदद की। ड्रोन फसल के विकास पैटर्न, मिट्टी के स्वास्थ्य और उपज के अनुमान पर सटीक डेटा प्रदान करते हैं, जिससे खेत प्रबंधन और निर्णय लेने में सुधार होता है। वैश्विक स्तर पर, ड्रोन तकनीक ने कृषि सहित कई उद्योगों में क्रांति ला दी है। भारत में, ड्रोन में अपार संभावनाएं हैं- वे बड़े क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर सकते हैं, फसलों की निगरानी कर सकते हैं, बीमारियों या कीटों का पहले से पता लगा सकते हैं, और कीटनाशकों और उर्वरकों के सटीक उपयोग की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। यह सटीक खेती का तरीका पारंपरिक खेती के तरीकों से जुड़ी लागत और बर्बादी को कम करते हुए फसल की पैदावार को बढ़ाता है। हालांकि, भारतीय कृषि में ड्रोन को अपनाना धीमा रहा है। उच्च लागत, सीमित जागरूकता और ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त तकनीकी बुनियादी ढांचे ने व्यापक कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न की है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, नमो ड्रोन दीदी योजना न केवल ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देती है बल्कि ग्रामीण महिलाओं को सशक्त भी बनाती है। महाराष्ट्र में तैनात ड्रोन ने किसानों को पैदावार का बेहतर अनुमान लगाने और उत्पादकता बढ़ाने में सक्षम बनाया। ड्रोन पोषक तत्वों जैसे इनपुट के परिवर्तनीय दर अनुप्रयोग की अनुमति देते हैं, विशिष्ट क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार समायोजन करते हैं, इनपुट दक्षता को अधिकतम करते हैं। उत्तर प्रदेश में, ड्रोन-सहायता प्राप्त खेती ने किसानों को मिट्टी की उर्वरता भिन्नताओं के आधार पर उर्वरकों को सटीक रूप से लागू करने में सक्षम बनाया, जिससे पोषक तत्वों के उपयोग की दक्षता में वृद्धि हुई। ड्रोन तकनीक में स्वचालन कीटनाशकों या उर्वरकों के छिड़काव जैसे कार्यों में मानवीय त्रुटि को कम करता है, जिससे अधिक प्रभावी संचालन होता है। मध्य प्रदेश में एक पायलट परियोजना ने कीटनाशक छिड़काव में कम त्रुटियों को दिखाया, जिससे फसल की उपज में 15त्न सुधार हुआ। ड्रोन मिट्टी में नमी के स्तर का आकलन करने में मदद करते हैं, जिससे सटीक सिंचाई की सुविधा मिलती है, जिससे पानी का संरक्षण होता है और यह सुनिश्चित होता है कि केवल आवश्यक क्षेत्रों में ही पानी मिले। ड्रोन-सहायता प्राप्त सिंचाई ने गुजरात के जल-दुर्लभ क्षेत्रों में पानी के उपयोग को 15त्न तक कम कर दिया। इनपुट लागत में कमी- उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे इनपुट के सटीक उपयोग से, किसान लागत बचाते हैं, जिससे बेहतर संसाधन प्रबंधन में योगदान मिलता है। पंजाब में स्वयं सहायता समूह ने नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन का उपयोग करके इनपुट पर 20त्न लागत बचत की सूचना दी। ड्रोन कीटनाशकों और उर्वरकों के छिड़काव जैसे कार्यों में मैनुअल श्रम की आवश्यकता को कम करते हैं, जिससे किसानों को श्रम लागत में कटौती करने और परिचालन दक्षता में सुधार करने में मदद मिलती है। नमो ड्रोन दीदी के तहत ड्रोन सेवाओं को अपनाने के बाद हरियाणा के किसानों ने श्रम व्यय में 25त्न तक की कमी का अनुभव किया। ड्रोन तकनीक बड़े खेतों में छिड़काव और निगरानी जैसे कार्यों के लिए आवश्यक समय को काफी कम कर देती है, जिससे समग्र कृषि उत्पादकता में सुधार होता है। राजस्थान में, ड्रोन की सहायता से कीटनाशक के छिड़काव ने संचालन में लगने वाले समय को 7 दिनों से घटाकर 2 दिन कर दिया, जिससे उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ड्रोन सटीक कीट प्रबंधन में मदद करते हैं, कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग को कम करते हैं, जिससे दीर्घकालिक मिट्टी और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार होता है। तमिलनाडु के किसानों ने ड्रोन-सहायता प्राप्त कीट प्रबंधन प्रणालियों का उपयोग करके फसल की गुणवत्ता में 10त्न सुधार की सूचना दी। नमो ड्रोन दीदी योजना खेती को आधुनिक बनाने, सटीक कृषि को बढ़ाने और इष्टतम संसाधन उपयोग सुनिश्चित करने में प्रौद्योगिकी-आधारित कृषि की अपार क्षमता को प्रदर्शित करती है। उचित कार्यान्वयन और समर्थन के साथ, ऐसी पहल भारत के कृषि क्षेत्र को स्थिरता और बढ़ी हुई उत्पादकता की ओर ले जा सकती हैं। हालाँकि भारत कृषि में ड्रोन को एकीकृत करने वाला पहला देश नहीं है, लेकिन तकनीक के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर इसका ध्यान अद्वितीय है।

राष्ट्रीय
सहारा
पटना • बुधवार • 13 नवम्बर • 2024
www.rashtriyasahara.com

प्राथमिकताएं बदलिए

बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के तीन महीने बाद भी राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता का दौर जारी है। अमेरिका के जो बाइडन प्रशासन के समर्थन से सत्ता की बागडोर संभालने वाले मोहम्मद यूनुस प्रभावशाली ढंग से चुनौतियों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस राजनीति में लोकतांत्रिक और मानवतावादी मूल्यों की स्थापना नहीं कर पा रहे हैं। अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे यूनुस प्रतिशोध की राजनीति में लिप्त हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उनके कारनामों की जांच करने के बाद उन्हें हाशिये पर कर दिया था। अब यूनुस को शेख हसीना से प्रतिशोध लेने का अवसर मिला है। उनकी अंतरिम सरकार अपदस्थ

प्रधानमंत्री हसीना और प्रशासन के अन्य लोगों को भारत से वापस लाने के लिए इंटरपोल से मदद मांगने की तैयारी में है। सरकार का विश्वास है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान करीब 753 लोग मारे गए। इस घटना को यूनुस ने मानवता के विरुद्ध अपराध करार दिया है और हसीना और उनकी पार्टी के नेताओं के विरुद्ध 60 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई गई हैं दूसरी ओर, हसीना के देश छोड़ने के तीन महीने बाद उनकी पार्टी अवामी लीग एकजुट होने के प्रयास कर रही है। इसी क्रम में अवामी लीग ने रविवार को ढाका के नूर हुसैन स्कवायर पर विरोध मार्च निकालने का आह्वान किया था। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात-ए-इस्लामी के कार्यकर्ताओं ने सरकार और पुलिस प्रशासन की शह पर अवामी लीग के नेताओं और समर्थकों की पिटाई की। लोकतंत्र में जितना महत्वपूर्ण सत्ता पक्ष होता है, उतना ही विपक्ष भी होता है। अगर देश में लोकतंत्र स्थापित करना है तो यूनुस की सरकार को अपनी प्राथमिकताएं बदलनी होंगी। अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर हिन्दुओं पर होने वाले अत्याचार से विश्व समुदाय चिंतित है। अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मतदान से पहले दीवाली के अवसर पर कहा था कि 'मैं हिन्दुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की निंदा करता हूं, जिन पर बांग्लादेश में भीड़ द्वारा हमला किया जा रहा है और लूटपाट की जा रही है।' जाहिर है कि दुनिया के एक बड़े नेता की इस टिप्पणी से बांग्लादेश और यूनुस की छवि कलंकित हुई है। बांग्लादेश में शांति और राजनीतिक स्थिरता आवश्यक है। राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से न तो लोकतंत्र स्थापित होगा और न देश बचेगा।

देशहित में सख्ती

सरकार ने विदेशी फंडिंग लेने वाले गैर-सरकारी संगठनों यानी एनजीओ की कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि ऐसे किसी भी एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा जिसके विकास विरोधी गतिविधियों, धर्मांतरण, दुर्भावनापूर्ण इरादे से विरोध-प्रदर्शन भड़काने या आतंकवादी या कट्टरपंथी समूहों के साथ संबंध हैं। विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। कानूनन विदेशी चंदा हासिल करने के लिए एनजीओ को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है। बीते दो-तीन साल में किसी गतिविधि में शामिल नहीं रहने, पूर्णतः निष्क्रिय या जांच के दौरान उन गतिविधियों की पुष्टि नहीं की जा सकती, जिनका दावा किया

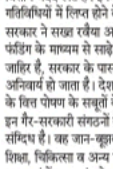

गया था। इस साल की पहली तिमाही में ही सरकार द्वारा कई बड़े एनजीओ के पंजीकरण निरस्त किए थे जिन पर नियमों के विरुद्ध गतिविधियों में शामिल होने व कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप था। केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान के अनुसार देश में तीसेक लाख एनजीओ काम कर रहे हैं जो समाज उत्थान व उपेक्षित वर्ग के लिए काम करते हैं। ये गैर-सरकारी व गैर-लाभकारी संगठन देसी-विदेसी संस्थाओं से वित्तीय मदद लेते हैं। इनमें से कई पर वित्तीय धांधली के अलावा देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप सिद्ध होते रहे हैं जिससे निपटने के लिए सरकार ने सख्त रवैया अपनाया। बीते वित्त वर्ष में इन संगठनों ने विदेशी फंडिंग के माध्यम से साढ़े पचपन हजार करोड़ रुपये की मदद प्राप्त की थी। जाहिर है, सरकार के पास इस धन के इस्तेमाल का सटीक ब्योरा होना अनिवार्य हो जाता है। देश-विरोधी गतिविधियों, धन शोधन और आतंकवादियों के वित्त पोषण के सबूतों के बाद सरकार का सतर्क होना बनता है। हालांकि इन गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों का आरोप है कि सरकार की मंशा संदिग्ध है। वह जान-बूझकर इनको अपनी गिरफ्त में रखना चाहती है। बेशक, शिक्षा, चिकित्सा व अन्य सार्वजनिक उपयोगिता उद्देश्यों को देश के जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम एनजीओ करते आए हैं मगर इसलिए उन्हें अतिरिक्त छूट नहीं दी सकती। आखिर, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। उन्हें सरकारी नियमों और पाबंदियों का खयाल रखना होगा क्योंकि कोताही होने पर अंततः सरकार और सुरक्षा व्यवस्था जवाबदेह माने जाते हैं।

दिल्ली/नीरज शर्मा 'भरथल'

प्रवेश और निकास मार्ग का संकट

आधुनिकता की चकाचौंध में राजधानी दिल्ली के पुराने बसे गांव उचित प्रवेश और निकास मार्गों लिए तरस रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल द्वारका एक्सप्रेस पर बसे भरथल गांव के साथ भी है। एशिया के सबसे बड़े एक्सपो सेंटर के सामने बसे इस गांव की हालत यह है कि कहने को तो इसको दो दिशाओं से आवागमन के लिए कई मार्ग प्रदान किए गए हैं परंतु काम का एक भी नहीं है। एक दिशा के प्रमुख रास्ते की हालत तो यह है कि वो टूटा-फूटा कंकर-पत्थरों, कीचड़ से भरा रहता है जिस पर बरसात में तो छोड़ो आम दिनों में भी चलना असंभव है। मार्ग दोनों ओर से झाड़ियों से घिरा है जिस पर गंदा पानी और बदबूदार काली गाद भरी रहती है। मजबूरी में लोग इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं, और आए दिन हादसों के शिकार होते हैं। मार्ग शराबी और नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। मार्ग पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है। परेशान ग्रामीणवासी रास्ते की शिकायत प्रशासन से कर चुके हैं परंतु अथॉरिटी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। यह मार्ग आगे जाकर ओल्ड मुखाम-बहादुरगढ़ मार्ग से मिलता है। असल में यह मार्ग दो नगर निगम पार्षदों, डीडीए की स्पष्ट तह सीमा में न होने की मार झेल रहा है। अभी तक पता नहीं लग सका है कि यह विजयासन के निगम पार्षद या द्वारका-सी के निगम पार्षद या डीडीए में से किसके अंडर आता है। गांव का एक निकासी मार्ग बिजवासन रेलवे स्टेशन की ओर से होते हुए मुकाम-बहादुरगढ़ मार्ग पर निकलता है, जो इतना संकरा है कि उस पर एक साथ दो छोटी गाड़ियां भी आसानी से नहीं निकल सकतीं। गांव के दूसरी दिशा के मार्ग की बात करें तो वो रास्ता सीधा द्वारका एक्सप्रेस वे पर जाकर निकलता है, जो आगे चल कर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से मिलता है।

भरथल पुराने समय से बसा हुआ गांव है। भरथल गांव में श्री दादा मोटे मंदिर धाम भी है। हर साल मन्दिर में बड़े मेला का आयोजन किया जाता है जहां हजारों की संख्या में लोग पहुंचते है। उनके लिए भी मन्दिर तक पहुंचना अब चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है। यह हाल सिर्फ एक गांव का नहीं है। दिल्ली देहात के ज्यादातर गावों के साथ अलग-अलग समय की सरकार यही व्यवहार करती आई हैं।

हाथी हमारा अब नहीं साथी

सामयिक

पंकज चतुर्वेदी

दीपावली के ठीक एक दिन पहले मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में एक साथ दस हाथियों के मारे जाने से दुनिया सन्न है। इनमें नौ मादा थीं और दो गर्भवती। और इस तरह दो हाथियों की मौत भ्रूण में भी हो गई। इसके ठीक तीन दिन पहले पास के छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले में तीन हाथी मारे गए तो कहा गया कि उन पर 11 केवीए की बिजली का तार गिर गया था। रविवार रात छत्तीसगढ़ में हाथियों के दल से 1 हाथी के बिछड़ने की जानकारी मिली और सोमवार सुबह जंगल के किनारे स्थित धान के खेत में हाथी का शव मिला। हाथी का शव मिलने के बाद वन विभाग ने जांच शुरू की तो खुलासा हुआ कि खेत के चारों तरफ बिजली का तार लगाया गया था।

खेत मालिक ने हाथी को मारने के लिए हाईवोल्टेज बिजली तार में क्लच वायर से जोड़ कर करंट लगाया था जिसकी चपेट में आने से नर हाथी की मौत हो गई। इस खुलासे के बाद वन विभाग ने आरोपी मुरका निवासी रामबक्स को गिरफ्तार कर लिया। इसी राज्य में 12 नवम्बर को बेहद मार्मिक घटना सामने आई जब रायपुर में सीतानदी-उदंती टाइगर रिजर्व में हाथी का एक बच्चा पेटाउ बम से घायल हो गया। उसके मुंह और पैर से खून बह रहा था और वह जलन से बचने को इधर-उधर पानी में शरीर डाल रहा था। यह बम जंगली सुअरों के शिकार के लिए उपयोग किया जाता है। दुर्भाग्य है कि बांधवगढ़ में इतनी बड़ी संख्या में हाथी की मौत के बाद भी प्रशासन सतर्क नहीं हुआ और गुस्साए हाथियों ने वहीं गांव के तीन लोग कुचल कर मार डाले। बीते कुछ सालों में कोई न कोई हाथी के पैरों तले कुचल कर मरने वालों की संख्या बढ़ी है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम, केरल, कर्नाटक सहित 16 राज्यों में बिगड़ैल हाथियों के कारण इंसान से टकराव बढ़ रहा है। इस झगड़े में हाथी भी मारे जाते हैं। यह बात तो स्पष्ट हो गई है कि बांधवगढ़ में बढ़ी संख्या में हाथियों की मौत कुछ विषाक्त खाने से हुई है। शक इस बात से खड़ा होता है कि राज्य सरकार के कुछ अफसर इसे तुरत-फुरत जहरीली कुटकी खाने से मौत निरूपित कर रहे थे लेकिन जब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बात से असहमति जताई कि जंगल का जानवर क्या किसी वन-उत्पाद खाने से मरेगा तो हड़बड़ाहट हुई। वन महकमे के अफसर सस्पेंड हुए।

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई), बरेली की ओर से मप्र वन विभाग को सौंपी गई रिपोर्ट में हाथियों के विसरा में माइक्रो टॉक्सिन साइक्लोपियाजोनिक एसिड मिलने की पुष्टि हुई है। एपीसीसीएफ और मप्र वन विभाग की ओर से गठित एसआईटी के प्रमुख एल कृष्णमूर्ति के मुताबिक, आईवीआरआई ने विसरा सैंपल की विषाक्तता रिपोर्ट से पता चलता है कि हाथियों ने वही मात्रा

में खराब कोदो पीपे/अनाज खाए थे। हालांकि, विसरा सैंपल में मिला साइक्लोपियाजोनिक एसिड कितना जहरीला था और कितनी मात्रा में था, क्या यही मौत का कारण हो सकता है- इसकी आगे जांच अभी जारी है।

दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश में जंगल और वनोपज आय के बड़े माध्यम हैं, लेकिन वाष के लिए जंग कर खर्च करने वाली सरकार हाथी के लिए लापरवाह रही है। प्रदेश में हाथियों के प्रबंधन के लिए सिर्फ एक करोड़ सालाना का बजट वन विभाग के पास है। प्रोजेक्ट टाइगर पर प्रदेश का बजट 200 से 300 करोड़ के बीच रहता है, लेकिन हाथियों के प्रबंधन पर प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए वन विभाग ने इस साल 66 लाख रुपये रखे। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी जो अभी देश के 16 राज्यों में चल रहा है। हाथियों की संख्या में बढ़ोतरी और इनके शिकार को रोकने के लिए शुरू की गई योजना में प्राकृतिक आवासों को सुधारना, हाथी-मानव संघर्ष को नियंत्रित करना सहित कई काम किए जाते हैं लेकिन वन विभाग के पास बजट होता नहीं है।

वन पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को सहेज कर रखने में गजराज की महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्यावरण-मित्र पर्यटन और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पूर्वानुमान में भी हाथी बेजोड़ हैं। जंगली हाथियों के बस्तियों में घुसने को किसी राज्य की सीमा से बांधा जा नहीं सकता। आंकड़ों पर गौर करें तो स्पष्ट होता है कि करीबी राज्य ओडिशा के हालात हाथियों को लेकर इतने खराब हैं कि दंतेल और गुरुसैल हो गए जंगली हाथी छत्तीसगढ़ और झारखंड में अपनी खोज मिटा रहे हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बैंगलुरु के एक अध्ययन में बताया गया था कि ओडिशा में उपलब्ध जंगल और संसाधन में अधिकतम 1700 हाथी भली प्रकार जी सकते हैं, जबकि आज वहां गजराज की संख्या 2100 से अधिक है। इस तरह 400 से अधिक हाथियों के लिए भोजन, पानी और आने पर्यावासीय संकट सामने दिख रहा है। सरकारी रिकार्ड में है कि 2017-18 और 4 नवम्बर, 2024-25, ओडिशा में 634 मारे गए, जिनमें 22 का शिकार हुआ, एक को जहर दिया गया 91 जानवूझकर बिजली के झटके से, 32 आकस्मिक बिजली करंट से मारे गए, जबकि 28 हाथी रेल से टकरा कर काल के गाल में गए। इसी साल 58 हाथियों की संदिग्ध मौत हुई, जिसकी जांच के लिए सरकार ने आदेश दिए हैं।

जानना जरूरी है कि हाथियों को 100 लीटर पानी और 200 किलो पत्ते, पेड़ की छाल आदि की खुराक जुटाने के लिए हर रोज 18 घंटों तक भटकना पड़ता है। हाथी दिखने में भले ही भारी-भरकम हैं, लेकिन उनका मिजाज नाजुक और संवेदनशील होता है। थोड़ी थकान या भूख उसे तोड़ कर रख देती है। ऐसे में थके जानवर के प्राकृतिक घर यानी जंगल को जब नुकसान पहुंचाया जाता है तो मनुष्य से उसकी भिड़ंत होती है। 2018 में पेरियार टाइगर कन्जर्वेशन फाउंडेशन ने केरल में हाथियों के हिंसक होने पर एक अध्ययन किया था। अध्ययन रिपोर्ट में पता चला कि जंगल में पारंपरिक पेड़ों को काट कर उनकी जगह नीलगिरी और बबूल बोने से हाथियों का भोजन समाप्त हुआ और यही उनके गुस्से का कारण बना। पेड़ों की ये किस्म जमीन का पानी भी सोखती हैं, सो हाथी के लिए पानी की कमी भी हुई। पर्यावरण-मित्र पर्यटन और और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पूर्वानुमान में भी हाथी बेजोड़ हैं। हाथी की उपस्थाति स्वस्थ जंगल की निशानी है, अच्छा जंगल धरती पर इंसान के लिए अनिवार्य है। अब सरकार और समाज, दोनों को हाथी की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनना होगा ।

(लेख में विचार निजी हैं)

जानना जरूरी है कि हाथियों को 100 लीटर पानी और 200 किलो पत्ते, पेड़ की छाल आदि की खुराक जुटाने के लिए रोजाना 18 घंटों तक भटकना पड़ता है। हाथी दिखने में भले भारी-भरकम हैं, लेकिन उनका मिजाज नाजुक और संवेदनशील होता है। थोड़ी थकान या भूख उन्हें तोड़ कर रख देती है। ऐसे में थके जानवर के प्राकृतिक घर यानी जंगल को जब नुकसान पहुंचाया जाता है तो मनुष्य से उसकी भिड़ंत होती है। सरकार और समाज, दोनों को संवेदनशील बनना होगा

भारत का स्मार्टफोन बाजार 7-8 फीसद बढ़ने का अनुमान

- एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के स्मार्टफोन बाजार में इस साल 7-8 फीसद की वृद्धि होने का अनुमान है
- साइबर मीडिया रिसर्च (सीएमआर) की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में फीचर फोन बाजार में तीसरी तिमाही में 14 फीसद की गिरावट देखी गई, जिसका मुख्य कारण 4जी फीचर फोन शिपमेंट में 46 फीसद की बड़ी गिरावट है

स्रोत : साइबर मीडिया रिसर्च

कुछ इस तरह के लेख जल्द ही देखने को मिलेंगे, खास तौर पर भारतीय मीडिया में कि-हार कर भी जीत गई कमला हैरिस, अमेरिकी नागरिकों में बढ़ती कट्टरता, कमजोर पड़ती अमेरिकी ताकत, दुनिया के लिए घातक दक्षिणपंथी उभार, चीन के आगे झुका अमेरिका वगैरह-वगैरह।

अखिलेश शर्मा, पत्रकार
@akhileshsharma1

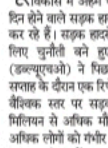

खड़े कर रहे सवालिया निशान

सड़क हादसे

अमित बैजनाथ गर्ग

यूं तो अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाली सड़कें देश के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं, लेकिन आए दिन होने वाले सड़क हादसे कई सवालिया निशान भी खड़े कर रहे हैं। सड़क हादसे भारत जैसे विकासशील देश के लिए चुनौती बने हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने पिछले साल वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसके अनुसार वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं में प्रति वर्ष 1.35 मिलियन से अधिक मौतें होती हैं, और 50 मिलियन से अधिक लोगों को गंभीर शारीरिक चोटें आती हैं। रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली कुल मौतों में से 11 प्रतिशत भारत में होती हैं।

सड़क दुर्घटनाओं के कारण भारत को होने वाले नुकसान को लेकर विश्व बैंक के आकलन के अनुसार, 18-45 आयु वर्ग के लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर सर्वाधिक 69 प्रतिशत है। इसके अलावा 54 प्रतिशत मौतें और गंभीर चोटें मुख्य रूप से संवेदनशील वर्गों जैसे पैदल यात्री, साइकिल चालक और दोपहिया वाहन सवार आदि में देखी जाती हैं। भारत में 5-29 वर्ष आयु-वर्ग के बच्चों और युवा वयस्कों में सड़क दुर्घटना मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। विश्व सड़क सांख्यिकी के अनुसार, 2018 में सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों की संख्या में भारत दुनिया में पहले स्थान पर था। इसके बाद चीन और अमेरिका का नंबर आता है।

केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, देश भर में होने वाली कुल सड़क दुर्घटनाओं में से 76 प्रतिशत दुर्घटनाएं ओवरस्पीडिंग और गलत साइड पर गाड़ी चलाने जैसे यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण होती हैं। कुल सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहनों और पैदल चलने वालों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके बावजूद सड़क यातायात इंजीनियरिंग और नियोजन के दौरान इस विषय पर ध्यान नहीं दिया जाता। यातायात इंजीनियरिंग और नियोजन सड़कों को विस्तृत करने तक ही सीमित है, जिसके कारण कई बार सड़कों और राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं। ब्लैक स्पॉट वे स्थान होते हैं, जहां सड़क दुर्घटना की आशंका सबसे अधिक रहती है। सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली 80 प्रतिशत मौतों के लिए वाहन चालक प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होते हैं। यह तथ्य देश में अच्छे ड्राइविंग स्कूलों की कमी की ओर भी इशारा करता

है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की भारत में सड़क दुर्घटनाएं' शीर्षक वाली रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना में लगभग 68 प्रतिशत मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में हुईं, जबकि कुल दुर्घटना मौतों में शहरी क्षेत्रों का योगदान 32 फीसद रहा। दुर्घटनाओं और मृत्यु दर, दोनों में दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी सर्वाधिक रही।

यूं तो सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए केंद्र सरकार अपने स्तर पर काफी प्रयास कर रही है, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे है। सड़क सुरक्षा के बारे में प्रभावी जन जागरुकता बढ़ाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से मीडिया के सभी माध्यमों द्वारा विभिन्न प्रचार उपाय एवं जागरुकता अभियान चलाए जा रहे है। इसके अलावा मंत्रालय सड़क सुरक्षा समर्थन के संचालन के लिए विभिन्न एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी योजना का संचालन कर रहा है। इंजीनियरिंग योजना स्तर पर सड़क सुरक्षा को सड़क डिजाइन का एक अभिन्न अंग बनाया गया है। सभी राजमार्ग परियोजनाओं का सभी चरणों में सड़क सुरक्षा ऑडिट अनिवार्यकिया गया है। इसके साथ ही मंत्रालय ने वाहन की अगली सीट पर ड्राइवर की बगल में बैठे यात्री के लिए एयरबैग के अनिवार्यप्रावधान को लागू किया है। इसके साथ ही कानूनों और प्रवर्तन में सुधार, ढांचागत परिवर्तनों के माध्यम से सड़कों को सुरक्षित बनाना और सभी वाहनों में जीवनरक्षक तकनीक उपलब्ध कराना जरूरी किया जाना चाहिए।

असल में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए जरूरी है कि लोगों के व्यवहार में परिवर्तन का प्रयास किया जाए। हेलमेट और सीट बेल्ट के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं इन्हीं कारणों से होती है। लोगों को शराब पीकर गाड़ी न चलाने के प्रति जागरूक करना होगा। वही दुर्घटना के बाद तत्काल प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना और पीड़ित को जल्द अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करने से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। दुर्घटना के बाद आस-पास खड़े लोग घायल की जान बचाने में अहम भूमिका निभा सकते है। सड़कों की योजना, डिजाइन और संचालन के दौरान सुरक्षा पर ध्यान देना सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को कम करने में प्रभावी योगदान दे सकता है। जब तक इन सुझावों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक सड़क दुर्घटनाओं को कम करना संभव नहीं होगा। जरूरी है कि सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार करते हुए आवश्यक उपायों की खोज की जाए।

शास्त्र ज्ञान

श्रीराम शर्मा आचार्य

जीवन में ज्ञान का विशेष महत्त्व है। ज्ञान ऐसा प्रकाश है जो हमारे भीतर से अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है और हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा देता है। इसलिए ज्ञान को दृष्टि कहा जाता है। हां, केवल आंखों से भौतिक रास्ता तय होता है, लेकिन ज्ञानचक्षु से जीवन का रास्ता तय होता है। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि ज्ञान जब तक हमारे आचरण में नहीं आता उसका अर्थ सिद्ध नहीं हो सकता। केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रहने से व्यावहारिक समस्याओं का समाधान भी कठिन हो सकता है। कभी-कभी तो किताबी ज्ञान दूसरों का अहित भी कर देता है। रामायण का राक्षसराज रावण चारों वेदों का ज्ञाता, निपुण, पंडित और भाष्यकार भी था। चारों वेद उसे कंठस्थ थे। यद्यपि वेद तो सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ हैं। उनमें दी गई शिक्षा भी उच्च कोटि की है। फिर भी रावण गलत पथ पर क्यों था? उसका पतन क्यों हुआ? स्पष्ट है कि शास्त्रों को पढ़ना और कंठस्थ करना अलग बात है, और उन उपदेशों और शिक्षा को जीवन में उतारना अलग बात। रावण को वेदों की नैतिकता और पवित्र जीवन की शिक्षा में दिलचस्पी नहीं थी। वह तो स्वर्णिय वैभव, स्त्री, धन, ऐश्वर्य आदि में आसक्त था। ऐसी भटकी बुद्धि से कैसे वह शास्त्र को आत्मसात कर सकता था? इसलिए गीता में अर्जुन को श्रीकृष्ण ने इस विपरीत परिणाम का कारण बताते हुए कहा था, '...जिनके मन उस वैदिक वाणी से भटक जाते हैं, और लौकिक सुख-धन से बहुत अधिक जुड़ जाते हैं, उन्हें परमात्मा की कोई निश्चित समझ नहीं होती।' भगवान स्वामिनारायण कहते हैं, 'जो लोग ऐसे विषयों के आसक्त होते हैं, वे धर्मशास्त्रों को लौकिक उपलब्धि का माध्यम बनाते हैं।' ठीक वैसे ही जैसे व्यसनी शराबी को मदिरा पान की तीव्र इच्छा होती है, तो कोई भी बहाना बना कर, चीजों को गलत तरीके से पेश करके, जिद करके, धोखा देकर भी वह अपनी हसरत पूरी करता रहता है। इसलिए गीता में बताया कि ऐसे लोगों की वाणी सुनने में मधुर या शायद शास्त्र सम्मत भी लगती है परंतु यह जन्म-मृत्यु के समान दुःख देने वाली है। इसके पालन से कभी भी परम मोक्ष नहीं होता।

रीडर्स मेल

छात्रों को राहत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव स्थगनगना की अनुमति दे दी और रेट याचिका निपटारा करते हुए जिस तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। उससे लगता है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार लिंग्दोह कमेटी की सिफारिश को पूर्ण रूप से माना जाना चाहिए क्योंकि लिंग्दोह कमेटी की रिपोर्ट में छात्र संघ चुनाव लेकर विभिन्न प्रकार की बातें कही गई हैं। यहां तक कि छात्र संघ चुनाव के दौरान छात्रों की 75% उपस्थिति तथा उसके सभी पेपर पास और अंकों का प्रतिशत भी निर्धारित किया गया है। यह बात भी कही गई है कि जो छात्रों का प्रतिनिधित्व करेगा वह शिक्षा के क्षेत्र में भी अव्वल होना चाहिए। छात्र संघ चुनाव के दौरान प्रचार के लिए भी खर्च की सीमा तथा गाड़ियों के काफिले पर सीमा रेखा निर्धारित की गई है। लगता कि है कि किसी भी छात्र संघ चुनाव के दौरान इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लिंग्दोह कमेटी की सिफारिश पूर्णरूप लागू हो तथा भविष्य में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव पर विश्वविद्यालय प्रशासनकी पूर्णरूप से ध्यान देना जरूरी है।

मीना धानिया, दिल्ली

यही तो पाखंडवाद है

पिछले पचास साल पहले वचपन से ही हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि संगठन में शक्ति है। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। यदि हम अनेक पंथ, मत, जाति, भाषा, वर्ग आदि में बंटे लोग ऐक्य भाव नहीं रखते तो देश की परतंत्रता अवश्यंभावी है। पर इसी भाव को जब योगी या मोदी बोलते हैं कि बंटेंगे तो कटेंगे तो इन्हीं गठबंधन की नजर में यह देश को बांटना हो जाता है। यही पाखंडवाद है।

मनोज श्रीवास्तव, सुलतानपुर

संगठित होना होगा अरब देशों को

अरब और मुस्लिम नेता गाजा और लेबनान में इस्राइल के संघर्षों को संबोधित करने के लिए एक शिखर सम्मेलन के लिए सऊदी अरब में एकत्रित हुए। सऊदी विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन, गाजा में इस्राइल की कार्रवाइयों की निंदा करने वाली इसी तरह की बैठक के एक साल बाद हो रहा है। नेताओं से उम्मीद की जाती है कि वे चल रही हिंसा और क्षेत्रीय घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे, साथ ही गाजा संघर्ष और इस्राइली सैन्य कार्रवाइयों को समाप्त करने का आह्वान करेंगे। ठीक एक साल पहले इसी तरह की औपचारिकता पूरा करते हुए बैठक करके इस्लामिक देश अपना कर्तव्य पूरा मान कर अपने घरों को चले गए थे, जबकि इस्राइली सेना ने अपनी बमबारी का दायरा और बढ़ा लिया है। इधर इस्राइल दावा कर रहा है ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। इसलिए पश्चिमी तट और गाजा पट्टी का अधिग्रहण इस्राइल अब करके रहेगा। क्या अरब देश इस्राइली दमन चक्र को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएंगे या फिर उसके समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करते रहेंगे? इस्राइल को पराजित करने के लिए अब अरब देशों का सैन्य ताकत एवं लड़ाकू सामग्रियों को बढ़ाना पड़ेगा। सभी को मिल कर इस्राइल से मुकाबला करना होगा। कोशिश यह होनी चाहिए कि ईरान जल्द से जल्द अणु शक्ति संपन्न देश बन जाए ताकि उसके साथ इस्राइल और उसके पश्चिमी सहयोगी देश आंख से आंख मिला कर बात करने की हिम्मत न कर सकें।

जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया काजमी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन द्वारा जिन्दुस्तान मेटिया नेक्सर्स लिमिटेड प्रेस, गौना-दरियापुर, पुलिस स्टेशन-सरमुर, थानसुर, पटना से मुद्रित तथा पशुर्भ तल, सहारा इण्डिया प्लिंट, मोरेन रोड क्रासिंग, पटना से प्रकाशित।
। साप्ताह संपादक - डॉ. विजय राय। स्वतंत्र संपादक - संजय त्रिपाठी ।
पटना कार्यालय- 3911448/417/454/422, फैक्स : 2535935,2520760 विज्ञापन-3911455/434, प्रसार- 3911451/428
वर्ष - 19, अंक 6470
आर.एन.आई. नं. बीआईएचएचएन/2006/18082 Postal Reg. No. : R-10/NP-50/06-07
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु उत्तरदायी

अमर उजाला
प्रवाह
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948
नई दिल्ली ■ बुधवार, 13 नवंबर 2024

एक मजबूत अर्थव्यवस्था राष्ट्र की ताकत का स्रोत है।
-योशिहिदे सुगा

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि चंडीगढ़ की जितनी आबादी है, देश में उससे भी ज्यादा लोग पिछले एक दशक में सड़क दुर्घटनाओं में मौत के शिकार हुए हैं। क्या सिर्फ पिछले दस वर्षों में दोगुने हो चुके वाहन या सड़कों की बढ़ती लंबाई ही इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं?

सड़क, सुरक्षा और सवाल

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं, जिनके अनुसार, पिछले करीब एक दशक (2014-23) में देश में सड़क दुर्घटनाओं में पंद्रह लाख से भी ज्यादा लोग मौत के शिकार हुए हैं। इससे देश में सड़कों की स्थिति, यातायात नियमों की अनदेखी और व्यवस्थागत कमियों का तो पता चलता ही है, सड़क सुरक्षा से जुड़े हर पहलू पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत भी महसूस होती है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में प्रति दस हजार किलोमीटर पर सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों की दर क्रमशः 57, 119 और 11 है, जबकि भारत में यह 250 के करीब है, जिससे स्थिति की गंभीरता समझी जा सकती है। बेशक सरकारी आंकड़े इसकी वजह पिछले दस वर्षों में सड़कों पर वाहनों की संख्या के दोगुने होने को इंगित करें, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। देखा गया है कि सड़क दुर्घटनाओं में ज्यादातर मौतें व्यक्तिगत लापरवाही या दुर्घटना के बाद विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी की वजह से होती हैं। खासकर, सड़कों पर तेज गति से गाड़ी दौड़ाने को 'कूल' मानने वाला युवा वर्ग इन बढ़ती दुर्घटनाओं का ज्यादा शिकार होता है। इसके अलावा, नशे की हालत में गाड़ी चलाना भी बड़ी दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है। कुछ समय पूर्व आईआईटी, दिल्ली द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में लगी चोटें देश में मृत्यु का तेरहवां प्रमुख कारण थीं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा व जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में सड़क दुर्घटनाओं में लगी चोटें शारीरिक नुकसान की शीर्ष दस वजहों में शुमार रहीं। चिंतित करने वाली बात अलबत्ता यह भी है कि देश के ज्यादातर राज्य 2030 तक यातायात से होने वाली मौतों को आधा करने के संयुक्त राष्ट्र के सड़क सुरक्षा कार्रवाई दशक के लक्ष्य को पूरा करने से काफी पीछे दिख रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अब तक

केवल आठ राज्य ही अपने राष्ट्रीय राजमार्गों का ऑडिट कर सके हैं और यातायात के बुनियादी सुरक्षा उपायों का भी ज्यादातर राज्यों में अभाव है। 2019 का मोटर वाहन अधिनियम राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड की स्थापना अनिवार्य बनाता है, लेकिन अब तक इसका गठन न हो पाना, इस दिशा में व्यवस्थित प्रयासों की कमी को ही दर्शाता है। दरअसल, जरूरी यह है कि घातक सड़क दुर्घटनाओं के लिए एक राष्ट्रीय डाटाबेस बने, जो सार्वजनिक पहुंच में भी हो। इससे लोगों में जागरूकता तो आएगी ही, राज्यों में लागू सड़क सुरक्षा संबंधी प्रावधानों की प्रभावशीलता भी बढ़ेगी। लेकिन पहले नीति नियंता सड़क सुरक्षा के विषय को अपनी प्राथमिकता में तो लें।

इतनी बेचैनी क्यों है भाई?

भारतीय शेयर बाजार क्यों घबराया हुआ है? त्योहार पर चमक क्यों नहीं दिखी? कंपनियों के नतीजों और सरकार के आंकड़ों में क्या दिख रहा है? अर्थव्यवस्था में ढलान को थामने की कमान कौन संभालेगा, सरकार या रिजर्व बैंक?

अंशुमान तिवारी
वरिष्ठ लेखक-पत्रकार

मनोहरलाल खुद से उलझे हैं। भारत में मजबूत सरकार है, नीतियों में निरंतरता है, युद्ध भी थीमे पड़े, जीडीपी तो खूब चमक रही, ब्याज दरों में बहुत भी रुक गई, तेल भी न खौल रहा, अमेरिका में पूंजीपतियों के चहेते ट्रंप आ गए, मगर शेयर बाजार में ये क्या हो रिया है! गिरे ही जा रहा! विदेशी निवेशक शेयर ऐसे बेच रहे हैं, जैसे किसी दूसरे गोले पर जा बसेंगे। बाल्टियों आंकड़े और गठरियों रिपोर्ट पढ़ने के बाद बड़बड़ाते हुए, मनोहरलाल ऊंघ गए, अर्थशास्त्र की किताब मुंह पर आ टिकी।

सपनों पर सवार मनोहरलाल ऐसी जगह पहुंच गए, जहां जॉन मेनार्ड केंज और मिल्टन फ्रीडमैन एक साथ बैठे थे। इन दोनों के सिद्धांतों पर ही बीते सौ साल में दुनिया की सरकारों ने आर्थिक नीतियां बनाई हैं। केंज ने सरकारों को मांग और रोजगार बढ़ाने के लिए बजट से खर्च करना सिखाया, जिसके दम पर फ्रेडी रूजवेल्ट ने 1930 की महामंदी को खदेड़ा। मिल्टन फ्रीडमैन ने सरकार के खर्च में कमी, महंगाई पर सख्ती और मौद्रिक आपूर्ति घटाने-बढ़ाने यानी कर्ज सस्ता-महंगा करने की राह दिखाई। 1980 के दशक में रीगन व थैचर के बाद 2023 तक पूरी दुनिया ने इसी मंत्र से आर्थिक बलाएं टालीं।

मनोहरलाल ने तत्काल सरकारों के आर्थिक गुरु, केंज और फ्रीडमैन को धर लिया। मेरी तो दिवाली धुआं-धुआं हो गई। शेयरों को पलीते लग गए साहब! कोई कहता है भारत में मांग नहीं है, कोई बोल रहा है बस, जिनकी जेब भारी उनकी शॉपिंग कार्ट भारी। कोई कह रहा कंपनियां निवेश ही नहीं कर रहीं। हो क्या रहा है आखिर? केंज और फ्रीडमैन ने क्या कहा, यह मनोहरलाल को याद नहीं, मगर उनके सपने में एक कंप्यूटर स्क्रीन नमूदार हुई, जिस पर सवालों के जवाब आने लगे।

पहली खबर कौंधी। इस साल की दूसरी तिमाही में करीब 44 फीसदी कंपनियां मुनाफे के अपने लक्ष्यों से चूक गईं। मनोहरलाल नींद में ही चिहुंक पड़े। जे एम फाइनेंशियल की ताजा रिपोर्ट बता रही है कि साधुन-

मंजन-फूड वाली एफएमसीजी कंपनियां हों या सुपरमार्केट वाली, कार और कार पुर्जे वाली कंपनियां हों अथवा केमिकल बनाने वाली या कि हों वोल्टास-हैवेल्स जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल वाले या फिर सीमेंट टाइल वाले... सभी कंपनियों के कुनबों में मुनाफे टूटने के दर्द भरे नग्मे बज रहे हैं। केवल कुछ बैंकों के नतीजे ढाढ़स बंधा रहे हैं।

दूसरी तिमाही में त्योहारी उत्पादन होता है। इस दौरान जो बना, वही धनतेरस-दिवाली वाली अगली तिमाही में बिकना था, सो यह आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। मनोहरलाल को याद आया कि त्योहारों के दौरान कारों के न बिकने की खबरें आई तो थीं। एफएमसीजी कंपनियों की बिक्री तो पहले से गिर रही है। मगर कीमतें बढ़ाकर और खर्च काटकर थामे गए मुनाफे भी अब खिसक रहे हैं। आंकड़ों में डुबकी से पता चलता है कि बिक्री और लाभ, दोनों ढलान पर हैं, इसलिए कॉरपोरेट टैक्स का संग्रह भी गिरेगा। तो शेयर बाजार की बेचैनी की वजह यह है? वैल्यूएशन कुछ और है और हकीकत (फंडामेंटल्स) कुछ और। मनोहरलाल नींद में बड़बड़ाए। मगर यह मांग का सूखा फैलता क्यों जा रहा है?

सपनों की स्क्रीन पर दो चार्ट उभरे। पहले चार्ट में दिखा कि चुनाव से पहले भारी सरकारी खर्च के बावजूद गांवों में कमाई सिकुड़ गई। शहरों में तो वेतन बढ़ोतरी ढलान पर ही है, क्योंकि रोजगार नहीं हैं, इसलिए भारतीय परिवारों की बैलेंस शीट और बिगड़ गई। बैंकों के उपभोक्ता कर्ज सिकुड़ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पर खर्च घटा, पर्सनल लोन भी कम हुए। सो दिवाली पर मांग नजर नहीं आई। स्क्रीन पर एक और आंकड़ा देखकर मनोहरलाल शेयर बाजार में घबराहट के मर्म के करीब पहुंच गए। सितंबर में जीएसटी का संग्रह 40 महीने के न्यूनतम स्तर पर था। कुल मासिक जीएसटी राजस्व इकाई में आ गया और शुद्ध राजस्व की सालाना बढ़त दर चार फीसदी से कम रह गई। सात राज्यों में टैक्स संग्रह सिकुड़ गया। अक्तूबर में भी जीएसटी राजस्व की रफ्तार बजट के लक्ष्य (11 फीसदी) से पीछे रह गई।

यह आंकड़ा भी गौरतलब है कि वित्त वर्ष की पहली छमाही में सरकार का खर्च घटा है। चुनाव खत्म तो खर्च में कमी लाजिमी है। घाटा और कर्ज कम जो करना है। अब अगर टैक्स संग्रह घटता (जीएसटी और कॉरपोरेट टैक्स) रहा, तो फिर सरकार चाह कर भी खर्च नहीं बढ़ा पाएगी। मनोहरलाल बुदबुदाए, अब समझे! शेयर बाजार, जीडीपी के आंकड़ों के भीतर झांक रहा है। जाहिर है, अर्थव्यवस्था में मांग का सूखा गहरा रहा है। निर्यात पिटे हुए हैं। खाद्य महंगाई खपत को सिकोड़ रही है। त्योहारी मांग का दौर निकल गया। अब कंपनियां अगले छह महीने गिरते घाटे को कैसे रोकेंगी। जब कंपनियां मुनाफे के लक्ष्य से चूकेंगी, तो शेयर तो पिघलेंगे ही। यही वजह कि दिवाली पर शेयर बाजार में बड़ी आतिशबाजी नहीं दिखी। बेचैनी के हिचकोले जारी रहेंगे।

मनोहरलाल आंकड़ों के बोल सुन रहे हैं...भारत सीमित मांग (भरी जेब वालों की) और महंगाई वाली सुस्ती (स्टैगफ्लेशन) में फंसा है। जब सरकार के पास खर्च को बढ़ाने की कुव्वत न हो और महंगाई के कारण कर्ज सस्ता करने की हिम्मत न हो, तो केंज और फ्रीडमैन, दोनों के फॉर्मूले काम नहीं करते। दरअसल, कंपनियों के मुनाफे की रिसाइकिलिंग यानी दोबारा निवेश नहीं हो रहा है। 2024 में प्रमुख 1,350 कंपनियों का कैश रिजर्व और बैंक बैलेंस 10 लाख करोड़ रुपये से ऊपर था, टैक्स रियायतें भी भरपूर मिलीं, मगर नया निवेश नहीं हुआ। इसके बिना रोजगार आने से रहे। सरकारी खर्च बढ़ाने की फाइलें फिर खुलने की खबर है। लेकिन टूटती मांग के बाद जीएसटी संग्रह घटेगा, तो सरकार की मुट्ठी भिंचती जाएगी। कर्ज सस्ता करने की पुकार लग रही है, मगर रिजर्व बैंक की टीम महंगाई से डर रही है। डर है कि यह सुस्ती ठंड बनकर अर्थव्यवस्था की हड्डी में घुस गई, तो फिर पूरा ढांचा ही लड़खड़ा (स्ट्रक्चरल स्लोडाउन) जाएगा। मनोहरलाल के सपनों में केंज और फ्रीडमैन धुंधला गए हैं। मुल्कों की अर्थव्यवस्था में बुनियादी चुनौतियों के विशेषज्ञ (स्ट्रक्चरल स्लोडाउन) रॉबर्ट जे गॉर्डन का संदेश सुनाई पड़ रहा है।

भविष्य को लेकर यह मुगालता बड़ा खतरनाक है कि तेज आर्थिक ग्रोथ हमेशा बनी रहेगी। इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। वक्त रहते नीतियां बदलनी होंगी। मनोहरलाल की नींद खुल गई है। वह अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में फिर से उलझ गए हैं।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

राही मासूम रजा

कृष्ण चंदर, भारती, कमलेश्वर जैसे दोस्त न होते, तो बंबई में मेरा रहना असंभव हो जाता। इन दोस्तों ने ऐसे वक्त में मदद की, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी। इनके एहसान से कभी बरी नहीं हो पाऊंगा।

कर्ज उतर जाता है एहसान नहीं उतरता

बंबई (अब मुंबई) में कई दोस्त मिले, जिनके साथ अच्छी-बुरी गुजरी। कृष्ण चंदर, भारती, कमलेश्वर, जो शुरू में मैं ये न मिल गए होते, तो बंबई में मेरा रहना असंभव हो जाता। शुरू में मेरे पास कोई काम नहीं था और बंबई में मैं अजनबी था। उन दिनों इन दोस्तों ने बड़ी मदद की। इन्होंने मुझे जिंदा रखने के लिए चंदा देकर मेरी तौहीन नहीं की। इन्होंने मुझे उलटे-सीधे काम दिए और उस काम की मजदूरी दी। पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं इन लोगों के एहसान से कभी बरी हो सकता हूं। मुझे वह दिन आज भी अच्छी तरह याद है, जब नैयर होली फैमिली अस्पताल में थीं। चार दिन के बाद अस्पताल का बिल अदा करके मुझे नैयर और मरियम को वहां से लाना था। सात-साढ़े सात सौ का बिल था और मेरे पास सौ-सवा सौ रुपये थे। तब कमलेश्वर ने 'सारिका' से, भारती ने 'धर्मयुग' से मुझे पैसे एडवांस दिलवाए और कृष्ण जी ने अपनी एक फिल्म के कुछ संवाद लिखवा के पैसे दिए और मरियम घर आ गईं। आज सोचता हूं कि जो यह तीनों न रहे होते, तो मैंने क्या किया होता? क्या मरियम को अस्पताल में छोड़ देता? वह बहुत बुरे दिन थे। कुछ दोस्तों से उधार भी लिया। कलकत्ते से ओपी टांटिया व राजस्थान से मेरी एक मुंहबोली बहन लतिका और अलीगढ़ से मेरे भाई मेहंदी रजा और दोस्त कुंवरपाल सिंह ने मदद की। कर्ज उतर जाता है, एहसान नहीं उतरता। और कुछ बातें ऐसी हैं, जो एहसान में नहीं आतीं, पर उन्हें याद करो, तो आंखें नम हो जाती हैं। जब मैं अलीगढ़ से बंबई आया, तो अपने छोटे भाई आहमद रजा के साथ ठहरा। छोटे भाई तो बहुतों के होते हैं, पर आहमद रजा यानी हद्दन जैसा छोटा भाई मुश्किल से होगा किसी की तकदीर में। उसने मेरा स्वागत यूं किया कि मैं यह भूल गया कि फिलहाल मैं बेरोजगार हूं।

हम हद्दन के साथ ठहरे हुए थे, पर लगता था कि वह अपने परिवार के साथ हमारे साथ ठहरे हुए हैं। घर में होता वह था, जो मैं चाहता था या मेरी पत्नी नैयर चाहती थी। वह घर बहुत सस्ता था। जिस फ्लैट में अब हूं, उससे बड़ा था। इसका किराया 600 दे रहा हूं। उसका किराया केवल 150 रुपये माहवार था। तो हद्दन ने सोचा कि वह घर उन्हें मेरे लिए खाली कर देना चाहिए। रिजर्व बैंक से उन्हें फ्लैट मिल सकता था, मिल गया। जब वह जाने लगे, तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ साजिश की कि घर का सारा सामान मेरे लिए छोड़ जाएं, क्योंकि मेरे पास तो कुछ था नहीं। जाहिर है कि मैं इस पर राजी नहीं हुआ। चुनांचे वह घर का सारा सामान लेकर चले गए और घर खाली हो गया। मेरे पास दो कुर्सियां भी नहीं थीं। हमने कमरे में दो गद्दे डाल दिए और वहीं दो गद्दोंवाला बेराग कमरा बंबई में हमारा पहला ड्राइंग रूम बना। उन दिनों मैं नैयर से शर्माने लगा था। मैं नैयर के बारे में सोचता था कि यह कैसी जिंदगी से निकाल कर कैसी जिंदगी में ले आया। मगर नैयर ने मुझे यह कभी महसूस नहीं होने दिया कि वह निम्न मध्यवर्गीय जिंदगी को झेल नहीं पा रही है। हम दोनों उस उजाड़ घर में बहुत खुश थे।

ऐसे मिलें कि आखिरी दिन हो

सूत्र

अक्सर लोग किसी के गुजरने के बाद उसके प्रति सदाशयता दिखाते हैं, लेकिन आप आज से ही, जिससे भी मिलें, उसके साथ ऐसा व्यवहार करें, जैसे कि आज आपका अंतिम दिन हो। उसके प्रति अपनी पूरी संवेदना, दयालुता और समझदारी दिखाएं, और ऐसा किसी लाभ के बारे में सोचकर न करें। आपका जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा।

दूसरा पहलू

बांकेबिहारी मंदिर के निकट 50 फुट ऊंचे टीले पर बना मदन मोहन मंदिर वृंदावन के प्राचीन सप्त देवालयों में शामिल है।

मंदिर, जिसे इतिहास का क्रूर शासक भी नहीं मिटा सका

यमुना तट से थोड़ी दूर और बांकेबिहारी मंदिर के निकट 50 फुट ऊंचे टीले पर बना मदन मोहन मंदिर वृंदावन के प्राचीन सप्त देवालयों में शामिल है। यहां भगवान श्रीकृष्ण की आराधना मदन मोहन के रूप में होती है। मंदिर में उनके साथ राधा और सखी ललिता की दिव्य मूर्तियां भी विराजमान हैं। पर बांकेबिहारी से अलग इस मंदिर का परिसर कुछ सूना-सा लगता है। यह मंदिर दूर से किले सरीखा दिखता है। वृंदावन के गिने-चुने मंदिर ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के तहत आते हैं। मदन मोहन मंदिर भी उनमें शामिल है। परिसर में ही मौजूद टिकट घर से जब सीढ़ियां चढ़कर भव्य मंदिर के प्रांगण में पहुंचते हैं, तो इक्का-दुक्का भक्त और बंदरों की धमा-चौकड़ी ही नजर आती है। मुख्य मंदिर में तीनों प्रतिमाएं और एक पुजारी हैं। पर इनकी कहानी भी बड़ी अजीब है।

भूपेंद्र कुमार

लगभग 350 साल पहले बना यह मंदिर कलिंग-नागर वास्तुकला की अनुपम मिसाल है। लोककथाओं के अनुसार, मंदिर करीब पांच हजार साल पुराना है। इसे भगवान श्रीकृष्ण के पड़पोते वज्रनाभ ने बनवाया था

लगभग 350 साल पहले बना यह मंदिर कलिंग-नागर वास्तुकला की अनुपम मिसाल है। लोककथाओं के अनुसार, यह मंदिर करीब पांच हजार साल पुराना है। इसे भगवान श्रीकृष्ण के पड़पोते वज्रनाभ ने बनवाया था, समय के साथ इसकी मूर्तियां भी कहीं विस्मृत हो गईं। 16वीं सदी में ये मूर्तियां गौड़िया-वैष्णव संप्रदाय के प्रणेता चैतन्य महाप्रभु के समकालीन अद्वैत आचार्य को वट वृक्ष के नीचे मिलीं। उन्होंने इन्हें अपने शिष्य पुरुषोत्तम चौबे को सौंप दीं। बाद में उन्होंने इन्हें चैतन्य के शिष्य सनातन गोस्वामी को दिया। 1580 ईस्वी में मंदिर का पुनर्निर्माण सनातन गोस्वामी ने मुलतान (अब पाकिस्तान) के व्यापारी कपूर राम दास की मदद से करवाया।

1670 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने मथुरा के मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाया। मदन मोहन मंदिर पर आक्रमण की सूचना मिलते ही राजा जय सिंह ने मूर्तियों को जयपुर भिजवा दिया, वहां की राजकुमारी ने इसे अपने मंदिर में रखा। बाद में जब उनका विवाह करौली के राजकुमार से हुआ, तब राजा गोपाल सिंह ने इन प्रतिमाओं को वहां स्थापित करवाया। अब मूल प्रतिमाएं राजस्थान के करौली स्थित मदन मोहन मंदिर में हैं। 1748 में करौली की प्रतिमाओं की प्रतिकृति तैयार कराकर वृंदावन के इस मंदिर में स्थापित की गईं। 1819 में नंद कुमार बसु नामक बंगाली जमींदार ने मंदिर को नए सिरे से बनवाया। ओडिशा के पुरी से राधा और ललिता की प्रतिमा भेजी गईं। कम ही लोग जानते हैं कि वृंदावन के छह गोस्वामियों में शामिल सनातन (1488-1558) की समाधि भी मंदिर परिसर में है। चैतन्य महाप्रभु के इस शिष्य ने कुछ ऐसा कर दिखाया, जिसे इतिहास का क्रूर शासक भी नहीं मिटा पाया।

आंकड़े

भारत से निर्यात

भारत दुनिया भर में विभिन्न उत्पादों का निर्यात करता है। इस वर्ष अप्रैल से जुलाई के बीच पेट्रोलियम उत्पाद सबसे ज्यादा निर्यात किए गए।

पेट्रोलियम उत्पाद	17.98%
दवाएं	5.24%
टेलीकॉम उपकरण	4.87%
मोती, कीमती नग	3.73%
इलेक्ट्रिक उपकरण	3.15%

आंकड़े निर्यात के, प्रतिशत में — स्रोत : DGFT

भगवान श्रीरंगनाथ जी ने सारंगमा मुनि को आज्ञा दी कि वह मुनिवाहन को मेरे पास लाएं। मुनि उनको अपने कंधों पर बिठाकर ले गए और भगवान के दर्शन कराए।

भक्त मुनिवाहन

अंतर्यात्रा संकलित

मुनिवाहन बचपन से ही ज्ञानी थे। वह वीणा बजाते थे, लेकिन उनका हृदय भगवान के नाम से जितना आकर्षित होता था, उतना और किसी से आकर्षित नहीं होता था। वह भगवान श्रीरंगनाथ जी के दर्शन को हमेशा अभिलाषा करते थे। वह हर दिन श्रीरंगनाथ जी के मंदिर के समीप चले जाते, लेकिन मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे।

एक दिन वह सवेरे तीन बजे मंदिर के सामने उन रास्तों को साफ कर रहे थे, जहां से लोग मंदिर में दर्शन के लिए आया करते थे। किसी ब्राह्मण की उन पर दृष्टि पड़ गई, जिससे वह मुनिवाहन पर नाराज हुए और कहा कि तूने अत्यन्त होकर मंदिर के समीप आने का साहस क्यों किया। मुनिवाहन को इस बात से तनिक भी दुख नहीं हुआ। वह चुपचाप अपनी झोपड़ी में चले गए और वहीं भगवान रंगनाथ जी की भक्ति करने लगे। वह संसार को भूलकर भगवान की भक्ति में लीन हो गए। आचनक एक महात्मा उनकी झोपड़ी में चले आए और बोले, उठो भैया, मैं भगवान श्रीरंगनाथ जी का तुच्छ सेवक हूं। मुझे सारंगमा मुनि कहते हैं। भगवान ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम मेरे भक्त को कंधे पर बिठाकर आदरपूर्वक मेरे पास ले आओ। इसलिए हे भक्तवर! तुम मेरे कंधे पर चढ़ जाओ और मुझे चरणस्पर्श से कृतार्थ करो। सारंगमा मुनि मुनिवाहन को अपने कंधे पर बिठाकर मंदिर ले गए और तब से इनका नाम मुनिवाहन पड़ा। मुनिवाहन भगवान श्रीरंगनाथ जी का दर्शन पाकर कृतार्थ हुए।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 01 अप्रैल,1962

अल्जीरिया में शांति भंग करने का प्रयास

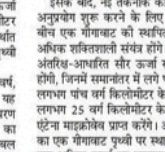
अल्जीरिया में शांति भंग होने दी जायगी
कार्य कारिणी के अध्यक्ष की चेतावनी
बी. ए. एस. के डिपार्टमेन्ट इन ए एंड एन्ड्रयूजी
अल्जीरिया, 12 मार्च। अल्जीरिया की कार्यकारिणी के अध्यक्ष बेन बेला ने आज घोषणा की कि अल्जीरिया में शांति भंग नहीं होने दी जायगी। उन्होंने कहा कि अल्जीरिया में शांति भंग करने के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अल्जीरिया के लोग शांति चाहते

चिंतन

खाद्य महंगाई को जल्द नियंत्रित करें सरकारें

महंगाई एक बार फिर से उच्च स्तर पर है। यह 14 महीनों में सबसे ज्यादा है। खाने-पीने की चीजें महंगी होने से अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.21 फीसदी पर पहुंच गई है। अगस्त 2023 में महंगाई दर 6.83 फीसदी रही थी। सितंबर में भी सब्जियां महंगी होने से खुदरा मुद्रास्फीति दर 5.49 प्रतिशत पर पहुंच गई थी। महंगाई दर आरबीआई के लक्ष्य से अधिक है। झारखंड व महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में महंगाई भी एक मुद्दा है। खुदरा मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के छह प्रतिशत के संतोषजनक स्तर के ऊपर निकल गई है। पिछले साल इसी महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति 4.87 प्रतिशत थी। मुद्रास्फीति के बास्केट में लगभग 50 फीसदी योगदान खाने-पीने की चीजों का होता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों से पता चलता है कि खाद्य महंगाई मासिक-दर-महीने आधार पर 9.24 प्रतिशत से बढ़कर 10.87 फीसदी हो गई है, जो सितंबर में 9.24 प्रतिशत और पिछले साल अक्टूबर में 6.61 प्रतिशत थी। ग्रामीण महंगाई दर भी 5.87 फीसदी से बढ़कर 6.68 फीसदी और शहरी महंगाई दर 5.05 फीसदी से बढ़कर 5.62 फीसदी हो गई है। यानी देश में हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ी हुई है। इन आंकड़ों से साफ है कि रिजर्व बैंक के मौद्रिक उपायों के बावजूद आम लोगों को खाद्य महंगाई से राहत नहीं मिल रही है। आरबीआई ने पिछले महीने नीतिगत दर रेपो को 6.5 प्रतिशत पर यथावत रखा था। सरकार ने केंद्रीय बैंक को मुद्रास्फीति को चार प्रतिशत (दो प्रतिशत घट-बढ़) पर रखने की जिम्मेदारी दी हुई है। खुदरा मुद्रास्फीति पिछले साल सितंबर से आरबीआई के छह प्रतिशत के संतोषजनक स्तर से नीचे चल रही थी। एनएसओ के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर के दौरान 'सब्जियों, फलों और तेलों और वसायुक्त वस्तुओं की कीमतों में काफी वृद्धि देखी गई। खुदरा मुद्रास्फीति चालू वित्त वर्ष (2024-25) की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के लिए एमपीसी के अनुमान से कम से कम 0.6-0.7 प्रतिशत अधिक रहने की संभावना है। इससे एमपीसी की आगामी बैठक में रेपो दर में कटौती की गुंजाइश नहीं लग रही है। अब अगले साल ही रेपो दर में आधा फीसदी तक की कटौती का दौर शुरू हो सकता है। लंबे समय से उद्योग जगत रेपो दर में कटौती का मांग कर रहा है। उच्च रेपो दर के चलते कर्ज पर ब्याज की दर अधिक है। इससे होम, ऑटो, व उद्योग क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। उच्च महंगाई दर लोगों की खरीद व बचत क्षमता को प्रभावित करती है, इससे उद्योग भी प्रभावित होता है। कच्चे तेल, कमोडिटी की कीमतों, मेन्युफैक्चर्ड कांस्ट के अलावा कई अन्य चीजें भी होती हैं, जिनकी खुदरा महंगाई दर तय करने में अहम भूमिका होती है। करीब 300 सामान ऐसे हैं, जिनकी कीमतों के आधार पर खुदरा महंगाई का रेट तय होता है। इनकी कीमतों के अलावा, आयातित मुद्रास्फीति के बढ़ने, जलवायु जोखिम, आपूर्ति चेन में बाधा के कारण भी महंगाई बढ़ती है। जब देश की मुद्रा की मांग और पेशेवर विनिमय दर में गिरावट होती है, तो इसका असर भी महंगाई में दिखाई देता है। उत्पादन और वितरण में अक्षतनीकरण की कमी, अनियमितता में बाधाओं से महंगाई बढ़ जाती है। उच्च महंगाई से समाज के गरीब और मध्यमवर्गीय वर्ग को ज्यादा असर पड़ता है। इसलिए सरकार को आपूर्ति सिस्टम ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए और खाद्य निर्यात को नियंत्रित करना चाहिए। केवल रिजर्व बैंक के मौद्रिक उपायों के भरोसे रहकर महंगाई को नियंत्रित नहीं की जा सकती है।

दो टूक
राज कुमार सिंह

वोट बैंक के विकास की राजनीति

> राजनीतिक दल देश के विकास की कीमत पर अपने वोट बैंक का विकास करते हुए सत्ता कब्जाते हैं और हर कोई मूकदर्शक बना रहता है। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों में भी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का यह बेलगाम खेल तब चल रहा है, जब देश के दो बड़े दलों और नेताओं में ऐसी गारंटियों पर वाक युद्ध चला। कांग्रेस और भाजपा में जारी वाकयुद्ध के बीच भी भाजपानीत राजग और विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' ने महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की रेवड़ियों के वायदे करने में संकोच नहीं किया। महाराष्ट्र में अपने-अपने चुनाव घोषणापत्र में दोनों ही गठबंधन मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते नजर आते हैं।

मुफ्त की रेवड़ियों की चुनावी राजनीति फिर चर्चा में है। इस पर प्रतिबंध के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल हुई है तो महाराष्ट्र एवं झारखंड के विधानसभा चुनावों में मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त की रेवड़ियों की बारिश का मौसम है। चुनावी राज्यों में अक्सर 'त्योहारी सेल' जैसा माहौल होता है, जहां ग्राहक को आकर्षित करने में दुकानदार कोई कसर नहीं छोड़ते।

ग्राहकों को ऑफर का लाभ उठाने के लिए फिर भी अपनी कुछ जेब ढीली करनी पड़ती है, लेकिन राजनीति में तो करदाता की कमाई से राजनीतिक दल 'दानवीर' बनकर वोट बटोरते हैं। देश के विकास की कीमत पर अपने वोट बैंक का विकास करते हुए सत्ता कब्जाते हैं और हर कोई मूकदर्शक बना रहता है। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों में भी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का यह बेलगाम खेल तब चल रहा है, जब देश के दो बड़े दलों और नेताओं में ऐसी गारंटियों पर वाक युद्ध चला। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो पांच गारंटियां दी थीं, उनमें महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की 'शक्ति' गारंटी भी है। पिछले दिनों कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का बयान आया कि कुछ महिलाओं ने टिकट लेकर यात्रा करने की इच्छा जतायी है, इसलिए 'शक्ति' योजना पर पुनर्विचार संभव है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच आये इस बयान पर शिवकुमार की पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने नसीहत दी कि वे ही चुनावी वायदे किए जाने चाहिए, जिन्हें पूरा करना संभव हो। निश्चय ही खरगे को आशंका रही कि शिवकुमार के बयान से कांग्रेस द्वारा किए जाने वाले चुनावी वायदों की विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खरगे के बयान को लपक कर कांग्रेस पर झूठे चुनावी वायदों का आरोप लगाने में देर नहीं लगायी, पर कांग्रेस और भाजपा में जारी वाकयुद्ध के बीच भी भाजपानीत राजग और विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' ने महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की रेवड़ियों के वायदे करने में संकोच नहीं किया। महाराष्ट्र में 10 नवंबर को जारी अपने-अपने चुनाव घोषणापत्र में दोनों ही गठबंधन मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते नजर आते हैं। वोट की खातिर मतदाताओं पर अचानक राजनीतिक 'लाड़' उमड़ रहा है। पहले से भारी कर्ज में डूबे महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की इस होड़ का क्या असर पड़ेगा, इसकी चिंता किसी को नहीं। यही बात आदिवासी बहुल राज्य झारखंड की बाबत कही जा सकती है। चुनाव जीतने के लिए लोक लुभावन वायदों की राजनीतिक प्रवृत्ति तो पुरानी है, लेकिन मुफ्त की रेवड़ियां अब चुनाव जीतने का आसान कारगर नुस्खा बनती दिख रही है। देश भर में मोदी लहर के बावजूद दिल्ली में आप की चुनावी सफलता में मुफ्त पानी-बिजली जैसे वायदों ने निर्णायक भूमिका निभायी। दिल्ली में चुनाव-दर-चुनाव सफलता से उत्साहित अरविंद केजरीवाल अपने चुनावी वायदों को 'गारंटी' बताने लगे, जिसका लाभ आप को पंजाब में भी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता के रूप में मिला।

मुफ्त की रेवड़ियों या ऐसी गारंटियों के जरिये चुनाव

जीतने के लिए अक्सर केजरीवाल को निशाना बनाया जाता है, लेकिन शायद ही कोई दल हो, जो इन चुनावी नुस्खों को न आजमाता हो। हां, नामकरण अलग हो सकता है। कभी गारंटी कहा जाता है तो कभी संकल्प, तो कभी न्याय। विपक्षी दल तो कोरोना काल में शुरू की गयी 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' को लगातार बढ़ाये जाने को भी इसी नजर से देखने-दिखाने लगे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा से पहले हुई एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल की अंतिम बैठक में लगभग 150 लोक लुभावन घोषणाओं को चुनावी 'लॉलीपॉप' के सिवाय और क्या कहा जा सकता है?

कर्नाटक ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस द्वारा चुनाव जीतने के लिए दी गयी गारंटियों पर अमल को लेकर जब-तब सवाल उठते रहते हैं, पर अन्य दलों द्वारा शासित राज्यों की कहानी भी अलग नहीं। वायदे सरकार बनते ही राज्य के कायाकल्प के किये जाते हैं, पर उनमें से ज्यादातर बड़े वायदे अंतिम समय तक लटके रहते हैं या फिर उन पर किंतु-परंतु के साथ प्रतीकात्मक रूप से ही अमल किया जाता है। ऐसा इसलिए भी, क्योंकि हर मतदाता वर्ग को लुभाने के लिए वायदों की बारिश करते समय उनकी व्यवहार्यता और आर्थिक प्रभाव का आकलन ही नहीं किया जाता। जाहिर है, कोई भी सत्तारूढ़ नेता या दल इन योजनाओं का आर्थिक बोझ नहीं उठाता। बोझ तो ईमानदार करदाताओं पर ही पड़ता है, जिनका प्रतिशत विदेशों की तुलना में हमारे देश में बहुत कम है। यह सवाल भी बार-बार उठता रहा है कि क्या उन करदाताओं से सहमति नहीं ली जानी चाहिए, जो देश के विकास के लिए तमाम तरह के कर देते हैं, न कि चुनावी 'रेवड़ियां' बांट कर सत्ता हासिल करने की गैर जिम्मेदार राजनीति के लिए?

बेशक नागरिकों को जीवन के लिए आवश्यक और न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवाना कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी है। देश या प्रदेश की सरकार अपने नागरिकों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाये तो उसकी प्रशंसा ही की जाएगी। सीमित मात्रा में मुफ्त पानी और सस्ती बिजली जैसी सुविधाओं की सोच भी सकारात्मक है। पेट्रोल-डीजल और गैस सिलेंडर जैसी दैनिक उपभोग की चीजें भी आम आदमी की क्रय शक्ति के अंदर रखने की कोशिश की जानी चाहिए, लेकिन लैपटॉप, स्मार्ट फोन, साइकिल, टीवी, फ्रिज आदि मुफ्त बांटना तो मतदाताओं को रिझत देने जैसा है। फिर अब तो बात मासिक या सालाना नकद राशि देकर 'लाड़' जताने तक पहुंच गयी है। क्या यह 'लाड़' वोट का 'रिटर्न गिफ्ट' नहीं, जिसकी कीमत ईमानदार करदाता ही चुकाते हैं, जिनकी चिंताएं और जरूरतें अब चुनाव केंद्रित राजनीति में किसी के एजेंडा पर नहीं रह गयी हैं? कभी तमिलनाडु से शुरू हुआ मुफ्त की रेवड़ियों का यह चुनावी खेल का अब पूरे देश में खूल कर खेला जा रहा है। चुनाव-दर-चुनाव मुफ्त की रेवड़ियों की प्रवृत्ति बढ़ रही है और सरकारी खजाने पर उसका बोझ भी, जिसका नकारात्मक असर विकास कार्यों पर साफ नजर आता है।

बेशक इस बीच सवाल यह भी उठा कि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना 'रेवड़ी-राजनीति' है तो उद्योगों को तमाम तरह की रियायतें देना क्या है? राजनीतिक दलों में लोक लुभावन घोषणाओं की बढ़ती होड़ से साफ झलकता है कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक की नसीहतें बेअसर रही हैं.. और वे नसीहत देने से आगे बढ़ना नहीं चाहते। अब आखिरी उम्मीद मतदाताओं पर टिकी है कि कभी तो वे मतदान तक सीमित कर दी गयी अपनी भूमिका से आगे नागरिक के रूप में अपने वास्तविक अधिकारों और दायित्वों को समझेंगे, ताकि लोकतंत्र को सत्ता का खेल भर बनने से बचाया जा सके।

(लेखक राजनीतिक समीक्षक हैं, ये उनके अपने विचार हैं।
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

सियासी ट्रेंड
बाल मुकुन्द ओझा

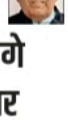

चुनावी नारे लगाएंगे पार्टियों का बेड़ा पार

चुनावी नारे मतदाताओं में जोश और उत्साह भरने का काम करते है। देश में किसी भी राज्य में चुनाव की रणभेरी बजते ही सियासी जुमलों और नारेबाजी की बाढ़ आ जाती है। चुनावी नारों की देश की राजनीति में बड़ी भूमिका रही है। इस समय महाराष्ट्र, झारखंड और विभिन्न राज्यों में हो रहे उप चुनावों में नेताओं के सियासी जुमलों, बोलों, नारों और बयानों ने देश की राजधानी से लेकर पंचायत तक पूरे भारत में चुनावी गर्माहट पैदा कर दी है। इस दौरान जुमले और नारे अपने परवान पर हैं। दोनों राज्यों के विधानसभा चुनावों में मुख्यतः एनडीए और इंडिया गठबंधन में चुनाव जीतने की जोर आजमाइश हो रही है और दोनों तरफ से तरह-तरह की जुमलेबाजी और नारेबाजी गढ़कर मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। यह सर्वविदित है नारे कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भरपूर जोश का संचार तो करते ही हैं, अपितु मुद्दों को चुनाव में स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि नेताओं के आरोप-प्रत्यारोप और बयानबाजियों के बीच प्रचार के लिए नारे सबसे बड़े चुनावी हथियार बने हैं। चुनावी महासमर में नारों की गूंज जितनी बलवती और ऊंची होती है, राजनीतिक दलों और नेताओं का जोश उतना ही हाई होता है। भारतीय राजनीति में नारों और जुमलों ने अच्छी खासी सुर्खियां बटोरी हैं। इस समय सबसे चर्चित नारा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 'बंटेंगे तो कटेंगे' गूंज रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने के बाद योगी के इस बहुचर्चित नारे ने जोर पकड़ लिया है। इस नारे का पहली बार इस्तेमाल यूपी के सीएम ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा की पृष्ठभूमि में आगरा में एक रैली में किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'एक है तो सेफ है' का नारा भी मतदाताओं में बुलंद हो रहा है। इसके जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बीजेपी से योगी आदित्यनाथ के 'विभाजनकारी' नारे और पीएम मोदी के एकता संदेश के बीच फैसला करने को कहा। उन्होंने कहा कि पहले आप आपस में तय कर लें कि किसका नारा अपनाना है-योगी जी का या मोदी जी का। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा उछाला है। यूपी में विधानसभा की नौ सीटों पर उप चुनाव होने जा रहे हैं जहां भाजपा और सपा में नारों का पोस्टर वार चरम पर है। आजादी के बाद कांग्रेस ने नारा लगाया खरो रुपयो चांदी को, राज महात्मा गांधी को जो बाद में जुमला बनकर रह गया, यथार्थ में गांधी के रामराज का सपना कभी पूरा नहीं हुआ। बाद में एक जुमला गांधी के नाम पर उछाला गया जिसे हम मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहते हैं। नारों की चर्चा के बिना चुनाव की बात अधूरी लगती है। चुनावों के दौरान गरीबी हटाओ से लेकर इंदिरा हटाओ, देश बचाओ जैसे नारे खासे चर्चित रहे हैं। देश में चुनावी मौसम में नारों की सियासत कोई नई नहीं है। 1971 में इंदिरा गांधी ने, वे कहते हैं, इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ" का नारा बुलंद किया था। यह नारा उस दौरान लोगों के सिर चढ़कर बोला और इंदिरा गांधी अपनी पार्टी कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताने में सफल हुई। यह अलग बात है कि 'गरीबी हटाओ' सिर्फ नारे और जुमले तक सिमटकर रह गया और गरीबी ज्यूंतल नहीं हुआ। आजादी के बाद कुछ नारे बहुतायत से जनता के बीच उछाले गए इनमें धन और धरती बंट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी, देखो इंदिरा का ये खेल, खा गई राशन पी गई तेल, बेटा कार बनाता है मां बेकार बनाती है, नसबंदी के तीन दलाल- इंदिरा, संजय, बंसीलाल,एक शेरनी सौ लंगूर चिकमंगलूर-चिकमंगलूर, देश की जनता भूखी है यह आजादी झूठी है, जात पर न पात पर इंदिरा जी की बात पर, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, अटल, आडवाणी, कमल निशान, मांग रहा है हिंदुस्तान, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, यूपी को ये साथ पसंद है, मां, माटी, मानुष, मोदी है तो मुमकिन है, न खाऊंगा, न खाने दूंगा आदि-आदि नारे खूब प्रचलित हुए। इसी तर्ज पर 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह नारा 'अब की बार 400 पार' खूब प्रचलित हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में 'हर-हर मोदी, घर-घर मोदी' तथा 'चौकीदार चोर है' नारे खूब गूंजे। इनमें से कुछ नारे चुनाव जीतने में सफल हुए और कुछ असफल। फिर भी नारों की अपनी महत्ता है। नेताओं ने इन नारों के जरिये मतदाताओं को लुभाने के खूब प्रयास किए और अब भी कर रहे है। मतदाता भी तालियों की गड़गड़ाहट और हर्ष ध्वनि के साथ नारों का स्वागत करते हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

जीवन मूल्यों का पाठ है योग

संकलित
दर्शन

भारत ने जो विश्व को बहुमूल्य उपहार दिए हैं, योग उनमें से एक है। योग हमारी अंतर्जात क्षमताओं को जाग्रत करने और पूर्णता की उच्चतम स्थिति की प्राप्ति में सहायक है। लोहे का एक टुकड़ा चुंबक कैसे बन जाता है? जब लौह कण एक दिशा-विशेष में एकत्र हो जाते हैं, तब यह होता है। उसी प्रकार, यदि हम अपने मन को एक ही बिंदु पर-एक ही दिशा में एकाग्र करें तो हम असीम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों ने एकाग्रता के साथ तप किया और इतनी शक्ति अर्जित की। जैसे सूर्य की किरणों को आवर्धक लेंस द्वारा एक बिंदु पर एकत्रित करें, तो रुई जल सकती है। यही बात हमारी आंतरिक शक्तियों पर भी लागू होती है। हम निष्ठापूर्ण एकाग्रता-शक्ति अर्थात योग द्वारा इनका आह्वान कर सकते हैं। योग हो या कोई अन्य साधना, सम्यक ज्ञान और मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। साथ ही, बाहरी व भीतरी अनुशासन भी बरतना चाहिए।बुरे कर्मों से बच कर, हम स्वस्थ विचार और दृष्टिकोण बनाएं और धर्मोचित कर्म करें। मूल्यों पर आधारित जीवन जिएंगे, तभी हमें योगाभ्यास का पूरा-पूरा लाभ प्राप्त होगा। योग हमारी बुद्धि, भावनात्मक मन एवं शरीर के लिए उपयोगी है। यह बिना दुखी हुए, हमें जीवन की समस्याओं से संतुलित रूप से निपटना सिखाती है। आइए, हम सब अपने प्राचीन ऋषि-मुनियों द्वारा सिखाई गई इस अमूल्य विद्या को प्रोत्साहन देने एवं इसे लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करें।

दो अनमोल हीरे

संकलित
प्रेरणा

एक व्यापारी को बाजार में घूमते हुए एक बहुत अच्छी नस्ल का ऊंट दिखाई पड़ा। व्यापारी ऊंट खरीद कर घर ले आया। घर पहुंचने पर व्यापारी ने अपने नौकर को ऊंट का कजावा (काठी) निकालने के लिए बुलाया। कजावे के नीचे नौकर को एक छोटी सी मखमल की थैली मिली जिसे खोलने पर उसे कीमती हीरे जवाहरात भरे होने का पता चला। नौकर चिल्लाया, मालिक आपने ऊंट खरीदा, लेकिन देखो, इसके साथ क्या मुफ्त में आया है। व्यापारी बोला- मैंने ऊंट खरीदा है, न कि हीरे, मुझे उसे तुरंत वापस करना चाहिए। नौकर बोला- मालिक किसी को पता नहीं चलेगा। पर, व्यापारी ने एक न सुनी और वह तुरंत बाजार पहुंचा और दुकानदार को मखमली थैली वापिस दे दी। ऊंट बेचने वाला बहुत खुश था। अब आप इनाम के तौर पर कोई भी एक हीरा चुन लीजिए। व्यापारी बोला- मैंने ऊंट के लिए सही कीमत चुकाई है इसलिए मुझे किसी शुक्रान के उपहार की जरूरत नहीं है। अंत में व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा- जब मैंने थैली वापस लाने का सोचा तो मैंने पहले से ही दो सबसे कीमती हीरे इसमें से अपने पास रख लिए थे। इस कबूलनामें के बाद ऊंट बेचने वाला भड़क गया उसने अपने हीरे जवाहरात गिनने के लिए थैली को तुरंत खाली कर लिया। पर वह था बड़ी पशोपेश में बोला- मेरे सारे हीरे तो यहीं हैं, तो सबसे कीमती दो कौन से थे जो आपने रख लिए? व्यापारी बोला- मेरी ईमानदारी और मेरा आत्म सम्मान। जिस-जिस के पास यह 2 हीरे है वह दुनियां के सबसे अमीर व्यक्ति हैं।

अंतर्मन

आज की पाती

आलसी बनाएगी रेवड़ी संस्कृति

देश में रेवड़ी संस्कृति पर रोक लगाने पर चर्चा होती है, लेकिन सवाल तो यह है कि इस पर रोक कौन लगाएगा? राजनेताओं को इस मुद्दे पर वोट बैंक बनाना होता है और लगभग सभी मतदाता मुफ्तखोरी को ध्यान में रखकर अपने कीमती मत का प्रयोग भी करते हैं, जबकि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि रेवड़ी संस्कृति वो दीमक है जो देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर सकती है। बीच की आर्थिक स्थिति बेहतर होने का एक कारण यह भी है कि यहां हमारे देश जैसा रेवड़ी कल्चर नहीं है। मुफ्तखोरी का एक नुकसान यह हो रहा है कि जो लोग खेतीबाड़ी करते थे, उनमें से बहुत से लोगों ने खेतीबाड़ी करना और पशु पालना बंद कर दिया है। रेवड़ी संस्कृति लोगों को निकम्मा और आलसी ही बनाएगी।

- सतीश उपाध्याय, जगदलपुर

ट्रेंड

खनिज पर स्थानीय का हक

खनिज संपदाओं और वन उपजों से संपन्न राज्य झारखंड को हेमंत सोरेन सरकार ने बाघाओं का अड्डा बना दिया है। आजाद सरकार प्रदेश की संपदाओं पर स्थानीय निवासियों के अधिकार के लिए तत्परता है। इसलिए विपक्षलाल के लोगों ने दान दिया है कि आजाद को ही लाना है।

-अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

पानी बचाना हमारा फर्ज

पंजाब के पानी का रखरखाव और अपने वाली पीढ़ियों के लिए इसे बचाना हमारी ड्यूटी ही नहीं, हमारा फर्ज भी है। इसलिए हमें एक सामाजिक लहर चलाने की आवश्यकता है। आओ, मिलकर इसे चलाते।

-भगवंत मान, सीएम, पंजाब

एक बार में परीक्षा जरूरी

क्या यूपी के छात्र बुनियादी सुविधाओं का इतना अभाव है कि पीसीएस आदि जैसी विशिष्ट परीक्षा दो दिन में चलानी पड़ रही है। परीक्षाओं की विश्वसनीयता अहम मुद्दा है, जिसके लिए एक बार में ही परीक्षा व्यवस्था जरूरी। सरकार इस ओर ध्यान दे।

-मायावती, पूर्व सीएम, उप्र

स्लमडॉग मिलियनेयर

16 साल पहले 12 नवंबर को, स्लमडॉग मिलियनेयर उत्तरी अमेरिका में रिलीज हुई और जंगल की आग की तरह फैल गई। यह फिल्म न केवल लोरे जीवन को अनमोल रिश्तों से समृद्ध करती है, बल्कि विविध रूप से भी सराहना प्राप्त करती रहती है।

-अनिल कपूर, अभिनेता

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

करंट अफेयर

संरा सुरक्षा परिषद में सुधार की तत्काल जरूरत : भारत

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के भौगुट ढांचे में 'मामूली फेरबदल' की कोशिशों के खिलाफ आगाह करते हुए कहा कि इससे स्थायी सदस्यता में विस्तार और पहिचा, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के कम प्रतिनिधित्व पर ध्यान देने जैसे महत्वपूर्ण तत्वों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा सकता है। ये टिप्पणियां संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने सोमवार को 'सुरक्षा परिषद में न्यायसंगत प्रतिनिधित्व और सदस्यता में वृद्धि का प्रश्न' विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक पूर्ण सत्र में कीं। उन्होंने कहा कि यूएनएससी में सुधार की तत्काल आवश्यकता कई दशकों से सामूहिक रूप से दोहराए जाने के बावजूद, यह 'निराशाजनक है कि 1965 के बाद से इस संबंध में हमारे पास दिखाने के लिए कोई परिणाम नहीं है, जब सुरक्षा परिषद का अंतिम विस्तार केवल अस्थायी श्रेणी में किया गया था।' साल 1965 में परिषद की सदस्यता छह निर्वाचित सदस्यों से बढ़ाकर 10 कर दी गई थी (अंतर-सरकारी वार्ता (आईजीएन) की प्रक्रिया की प्रकृति की ओर इशारा करते हुए, हरीश ने कहा कि अपनी स्थापना के 16 साल बाद, आईजीएन एक-दूसरे के साथ संवाद के बजाय मुख्य रूप से बयानों के आदान-प्रदान तक ही सीमित है।

ऑफ बीट

केवल एक परमाणु पक्षी का रंग बदल सकता है

पूरे जंतु जगत में पक्षी सबसे रंगीन जीवों में से एक है। लेकिन इतने सारे रंगों वाले पक्षी अलग अलग कैसे होते हैं? चमकीले लाल, नारंगी और पीले पंख या चोंच वाले लगभग सभी पक्षी अपने रंग उत्पन्न करने के लिए कैरोटीनॉयड नामक मिगमेंट के समूह का उपयोग करते हैं। लेकिन, ये पक्षी सीधे तौर पर कैरोटीनॉयड नहीं बना सकते। उन्हें अपने आहार में पौधों से ये तत्व प्राप्त करने होते हैं। लेते इस नियम के अपवाद हैं, जिन्होंने रंगीन रंगद्रव्य बनाने का एक बिल्कुल नया तरीका विकसित किया है, जिसे 'सिटाकोफल्विन' कहते हैं। वैज्ञानिकों को इन विभिन्न रंगों के बारे में कुछ समय से जानकारी है, लेकिन पक्षियों द्वारा रंग में भिन्नता लाने के लिए इनका उपयोग करने के पीछे के जैव-रासायनिक और आनुवंशिकी आधार को लेकर उनकी समझ अभी सीमित है। हालांकि, तोते और 'फिंच' (रंग बिरंगी छोटी चिड़ियों की प्रजाति) के बारे में हाल ही में किए गए दो अलग-अलग अध्ययनों ने इस रहस्य पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। एक अध्ययन 'करेंट बायोलॉजी' में प्रकाशित हुआ है जिसका नेतृत्व हमबे से एक (डैनियल हूपर) ने किया था। दूसरे अध्ययन का नेतृत्व पुर्तगाली जीवविज्ञानी रॉबर्ट आबेरे ने किया और उसे 'साइंस' पत्रिका में प्रकाशित किया गया।